चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 22 अगस्त- 28 अगस्त 2016 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

ख्वाड़ी देशों में चला 'रेस्क्यु ऑपरेशन'

सियासत का जनरल

दीनबंधु कबीर

सेना से लेकर सियासत तक मोर्चे पर डटे रहने वाले योद्धा साबित हो रहे हैं पूर्व सेनाध्यक्ष और मौजूदा विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह. जनरल वीके सिंह युद्धग्रस्त, हिंसाग्रस्त और समस्याग्रस्त क्षेत्रों से भारतीयों को सुरक्षित निकाल कर लाने के तमाम सफल ऑपरेशनों के नायक के बतौर उभर कर सामने आए हैं. लीबिया हो या इराक, यमन हो या सूडान, यूक्रेन हो या सऊदी अरब, जहां भी भारतीय फंसे, उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल कर भारत पहुंचाने की जिम्मेदारी जनरल वीके सिंह को ही दी गई और उन्होंने भी खतरे और जोखिम से भरी स्थितियों में सैन्य कुशलता और रणनीति का इस्तेमाल कर भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. राजनीति के गलियारे में वीके सिंह को अब सियासत का जनरल कहा जाने लगा है. युद्ध और हिंसाग्रस्त देशों से अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल ले आने से भारतवर्ष की दुनियाभर में ऐसी साख बनी कि अमेरिका, फ्रांस समेत 40 विभिन्न देशों ने हिंसाग्रस्त देशों में फंसे अपने नागरिकों को निकालने में जनरल वीके सिंह से मदद मांगी और भारत सरकार के प्रतिनिधि के बतौर उन्होंने भारतीयों के साथ-साथ विदेशी नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की.

जो भारतीय युद्धग्रस्त और हिंसाग्रस्त देशों से सुरक्षित निकल कर भारत पहुंचे हैं, उनकी आपबीती सुनें तो रेस्क्यु ऑपरेशंस की कामयाबी के पीछे की जद्दोजहद, तकलीफ, रणनीति और जोखिम का अहसास होगा. एयरपोर्ट ध्वस्त हो चुका हो, लगातार बमबारी हो रही हो, विमानों से हमले हो रहे हों, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने भारतीय विमानों को एयरपोर्ट पर लैंड करने से मना कर दिया हो, ऐसी विपरीत स्थितियों का सामना कर भारतीयों को बाहर निकाल लाने में कोई शख्स अपनी युद्ध-कुशलता और रणनीतियों की वजह से कामयाब हो रहा हो, यह सुन कर आपको रोमांच भी आएगा और गौरव की अनुभूति भी होगी. रेस्क्यु ऑपरेशंस से जुड़े रहे विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी कहते हैं कि ऐसे ऑपरेशंस में जनरल ऐसे ऐक्ट करते हैं जैसे उन्हें पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, निश्चित तौर पर यह सेना की ट्रेनिंग का असर है, टास्क एंड टार्गेट ओरिएंटेड, लिहाजा लक्ष्य साधने और उसे हासिल करने में अधिक दिक्कत नहीं होती. कई जगह उन्हें जनरल होने का फायदा भी मिल जाता है. इससे कूटनीतिक के साथ-साथ सामरिक जटिलताएं सुलझाने में भी मदद मिल जाती है.

यमन और दक्षिणी सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने का ऑपरेशन अधिक कठिनाई से भरा रहा है. लीबिया से करीब तीन हजार और इराक से सात हजार लोगों को पहले ही निकाल लिया गया था, लेकिन यमन में फंसे हजारों भारतीयों का बाहर निकलना मुश्किल था. विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी मानते हैं कि यमन का रेस्क्यु अभियान काफी टफ और जोखिम भरा था. यमन से साढ़े छह हजार लोगों को बहुत ही मुश्किल से निकाला गया. भीषण युद्ध के बीच ही रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया. बमबारी के कारण सना एयरपोर्ट ध्वस्त हो चुका था. भारतीयों को निकालने के लिए सरकारी पक्ष ने अपनी तरफ से गोलीबारी रोकने के लिए मात्र दो घंटे का समय (विंडो) दिया था. लेकिन इतने ढेर सारे लोगों को लाने और पासपोर्ट पर एक्जिट की मुहर लगाने में ही दो घंटे लग गए. इस दरम्यान सरकारी फाइटर विमानों ने दुश्मनों पर हमले फिर शुरू कर दिए. इस के मध्य ही भारतीयों की दो बड़ी खेपें निकालने में कामयाबी मिली. जनरल ने खुद सना में ही रुक जाने का फैसला किया. उनके पास कोई सामान भी नहीं

युद्धग्रस्त यमन से भारतीयों को युद्ध कौशल से निकाला जनरल वीके सिंह ने

हिंसाग्रस्त दक्षिणी सूडान में फंसे भारतीयों के लिए हुआ 'ऑपरेशन संकट-मोचन'

तनावग्रस्त सऊदी अरब में हो रहे अत्याचार से उबारे जा रहे भारतीय कामगार

था, क्योंकि तय कार्यक्रम के मुताबिक उन्हें उसी दिन दिल्ली वापस लौट आना था. लेकिन ऑपरेशन अभी बाकी था, लिहाजा उन्होंने सना में ही रुकने का फैसला किया. रात को जनरल वीके सिंह को ऐसे एक पुराने होटल का पता लगा जो कभी ताज ग्रुप चलाया करता था, बाद में उसे स्थानीय नियंत्रण में दे दिया गया था. होटल के बाहर बाकायदा एयर डिफेंस गन्स लगे हुए थे और सुरक्षा बल रुक-रुक कर गोलियां दाग रहे थे. जनरल सिंह उसी होटल में रुके. वहां एक रसोइया भी भारतीय निकला जो उत्तराखंड के गढ़वाल का था. जनरल सिंह के पास अगले दिन पहनने के लिए कपड़े नहीं थे. रात में उन्होंने कपड़े धोए, उसे सुखाया और सुबह वही पहना. उस ऑपरेशन में अकेले सना से 4700 लोग निकाले गए. अदन से जहाज तक नावों से भी लोगों को निकाला गया. नौसेना के भी तीन पोत बुला लिए थे. दो क्रूज लाइनर भी मंगा लिए गए थे. सबसे मुश्किल तो तब हुई जब सना से भारतीयों को निकाल कर ला रहे आखिरी विमान को जिबूती में एटीसी ने उतरने से मना कर दिया. एटीसी ने पायलट को धमकियां दीं और वापस लौट जाने की हिदायत दी. विमान मुड़कर वापस लौटने भी लगा, लेकिन ऐन मौके पर जनरल सिंह ने सैन्य कुशलता का इस्तेमाल किया. उन्होंने कॉकपिट में जाकर सीधे एटीसी से बात की और कहा कि सारे विमानों की लैंडिंग फीस की रकम उनके पास है, अगर उन्हें उतरने की इजाजत नहीं मिली तो पैसा नहीं मिल पाएगा. इस पर एटीसी वाले ढीले पड़े, उतरने की इजाजत दी, लेकिन फिर कुछ ही मिनटों में पलट गए और विमान को वापस ले जाने को कहा. विमान में रेस्क्यु हुए भारतीय और विदेशी भरे हुए थे. आखिरकार जनरल ने एटीसी से कहा कि विमान में फ्यूल नहीं है, लिहाजा वे विमान को जबरन उतार रहे हैं. ऐसा कह कर विमान को सीधे लैंड करा दिया गया. जबकि विमान में फ्यूल पूरा था, लेकिन इस तरह लोगों को सुरक्षित लाया जा सका. इसका दुनिया के देशों पर असर यह हुआ कि 40 देशों ने भारत से रेस्क्यु में मदद मांगी. जिबूती में अमेरिकी राजदूत ने जनरल वीके सिंह से मुलाकात कर मदद मांगी. इस पर अमेरिकी नागरिकों को भी बाहर निकाला गया.

यमन में करीब साढ़े छह हजार भारतीय फंसे थे और युद्ध चल रहा था. ऐसा पहली बार हुआ कि विदेशी जमीन पर युद्ध छिड़ा हुआ हो और भारत सरकार का कोई मंत्री भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रहा हो. यह मिशन एक साथ तीन देशों के तीन शहरों के बीच चला. लेकिन इस मिशन का कंट्रोल जनरल के हाथ में था. फौज का लंबा अनुभव उनके इस काम को सरल बना रहा था. जनरल कभी यमन की राजधानी सना से राहत ऑपरेशन का निर्देशन कर रहे थे तो कभी पड़ोसी देश रिपब्लिक ऑफ जिबूती और अदन पहुंच जाते थे. कभी भारतीयों को लेकर उड़ने वाले पायलट से रूबरू हो रहे थे तो कभी घबराए भारतीयों को तसल्ली दे रहे थे. ऐसे विपरीत हालात में जब इस बड़े बचाव मिशन को अंजाम दिया जा रहा था, उस समय यमन की राजधानी सना पर सऊदी अरब समर्थित लड़ाकू जहाज बम बरसा रहे थे. चौतरफा गोलाबारी हो रही थी. सना शहर एक तरह से तबाह हो चुका था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था. इसी दरम्यान जनरल वीके सिंह भारतीयों को हवाई जहाज से जिबूति उतारना चाहते थे, जब भारी गोलीबारी की वजह से सना और जिबूती के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इजाजत नहीं दी थी.

उधर, अदन बदंरगाह के पास भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस मुंबई को पहुंचना था, लेकिन अदन बंदरगाह के पास भी भयंकर गोलीबारी चल रही थी. आईएनएस मुंबई बंदरगाह में दाखिल नहीं हो सका.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सियासत का जनरल

पृष्ठ 1 का शेष

जनरल वीके सिंह ने पहल करके 12 छोटी नौकाओं को किराए पर लिया. छोटी नौकाओं से भारतीयों को युद्धपोत तक ले जाया गया. छोटी नौकाओं के जरिए लोगों को आईएनएस मुंबई तक पहुंचाना बेहद मुश्किल ऑपरेशन था, लेकिन वहां भी जनरल वीके सिंह का फौजी अनुभव काम आया और सैकड़ों लोगों को युद्धपोत तक पहुंचाया जा सका. मुश्किल रेस्क्यु ऑपरेशन देख कर ही अमेरिका ने भी भारत से मदद मांगी थी. अमेरिका ने अपने नागरिकों को यमन से निकालने का अनुरोध किया था. भारत से मदद मांगने वाले देशों की लिस्ट बढ़ती चली गई. यमन की राजधानी में मौजूद अमेरिकी दूतावास से वाकायदा एक इमरजेंसी संदेश निकाला गया. भारत सरकार ने अमेरिकियों को यमन से निकाल कर जिबूती तक पहुंचाया. जबकि अमेरिका का समुद्री बेड़ा अदन की खाड़ी में तैनात था. भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस सुमित्रा से भी यमन में फंसे 348 भारतीयों को जिबूती लाया गया. जहां से वे विमान से भारत लौटे. आईएनएस सुमित्रा समुद्री डाकुओं के खिलाफ अभियान के लिए अदन में ही जूझ रहा था. एयर इंडिया के विमानों से भी 600 नागरिकों को बचाया गया. इसके अलावा रेस्क्यु ऑपरेशन में कुछ अन्य विदेशी एयरलाइंस के विमान भी किराए पर लिए गए थे.

कम मुश्किल नहीं थी सूडान की उड़ान

दक्षिण सूडान में जारी गृह युद्ध में फंसे सैकड़ों भारतीयों को सुरक्षित निकालने का काम कम मुश्किल का नहीं था. इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए भी विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा पहुंच कर डट गए थे. सूडान के रेस्क्यु अभियान को 'ऑपरेशन संकट मोचन' नाम दिया गया था. 'ऑपरेशन संकट मोचन' का मकसद था दक्षिण सूडान में फंसे सैकड़ों से अधिक भारतीयों को जुबा से सुरक्षित बाहर निकालना. इस अभियान में भारतीय वायुसेना के दो मालवाहक सी-17 विमान का इस्तेमाल किया गया. भारतीय दूतावास के पास सिर्फ तीन सौ भारतीयों ने ही वापसी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया था. दक्षिण सूडान के कई हिस्सों में पूर्व विद्रोही और सरकारी सैनिकों के बीच भारी संघर्ष चल रहा था. दक्षिण सूडान में फंसे करीब छह सौ भारतीयों में से 450 के जुबा में और करीब 150 लोगों के राजधानी के बाहर फंसे होने का अनुमान था. युद्ध प्रभावित दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा से आखिरकार 156 लोगों को लेकर भारतीय वायु सेना का विमान सी-17 जब थिरुअनंतपुरम पहुंचा तो जिंदाबाद के नारों से आकाश गूंज गया. सुरक्षित आए लोगों में दो नेपाली नागरिक भी शामिल थे. 156 लोगों में नौ महिलाएं और तीन बच्चे भी थे. अन्य यात्रियों को लेकर वह विमान बाद में दिल्ली आया था. जनरल सिंह ने भारत सरकार को रिपोर्ट दी थी कि 156 लोग लाए गए. करीब 40 लोगों ने वाणिज्यिक उड़ानें शुरू होते ही अपना टिकट आरक्षित करा लिया था. तकरीबन तीन सौ लोगों ने अपने कारोबारी कारणों से भारत आने से मना कर दिया. रेस्क्यु में लगा भारतीय वायुसेना का विमान युगांडा होते हुए आया था. वहां जनरल सिंह ने युगांडा के प्रधानमंत्री रूहाकना रूगुन्दा से भी मुलाकात की थी. दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत भी ढाई हजार भारतीय तैनात हैं. सूडान से सुरक्षित निकल कर लोग जब विमान पर सवार हुए तो खुशी में उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए. यह ऑपरेशन करीब 30 घंटे तक चला था. भारतीय वायु सेना के कार्गो विमान सी-17 में यात्रियों के बैठने के लिए अलग से सीटें लगाई गई थीं. विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने बचाए गए भारतीय परिवारों से भारतीय वायु सेना की खास तौर पर सराहना करने के लिए कहा था. दक्षिणी सूडान से सुरक्षिक निकल कर भारत पहुंची अंजलि अरुण ने कहा भी कि जुबा से निकाल कर लाना मुश्किल अभियान था. वे कहती हैं कि वहां लगातार हो रही गोलीबारी के बीच हमें निकाल कर लाया गया. जय कृष्णन कहते हैं कि वहां के हालात बहुत बुरे थे. फायरिंग के कारण कोई घरों से बाहर झांक भी नहीं रहा था. ऐसे में भारतीयों को बाहर निकाल कर लाया गया. व्यापारी अरुण कहते हैं कि उनका वहां पुराना बिजनेस है, सबकुछ छोड़ कर जा भी नहीं सकते. देखभाल के लिए 10 लोगों को छोड़ कर वे भारत आए हैं.

ऐसे थे मुंबई वाले और वैसे थे केरल वाले

वह मुंबई का रहने वाला मुस्लिम युवक था जिसने सुरक्षित बाहर निकलने के बाद भारतीय विमान पर सवार होते ही भारत माता की जय का नारा लगाना शुरू किया था. उसके बाद तो विमान पर सवार सारे लोगों ने नारे लगाए. वह युवक मुंबई का रहने वाला है. जब वह विमान पर सवार हुआ, उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे. जनरल ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा. उसने कहा, हम धन कमाने इन देशों में आते हैं. अपने देश की तरफ ध्यान भी नहीं देते. कोई टैक्स नहीं देते. लेकिन आज आफत में फंसने पर हमें भारत सरकार ने ही बचाया. हम जीवन भर इस उपकार को नहीं भूलेंगे. ऐसा कह कर उसने भारत माता की जय का नारा लगाना शुरू कर दिया. और दूसरी तरफ केरल के सज्जन थे बेबी जॉन. रेस्क्यु ऑपरेशन की प्रक्रियाओं में बाधा डालते और खुद को केरल के मुख्यमंत्री का आदमी बताते. क्रूज लाइनर से जाने के बजाय हवाई जहाज से वापस लौटने की जिद करते. आखिरकार जनरल वीके सिंह ने केरल के मुख्यमंत्री से सम्पर्क साधा. मुख्यमंत्री ने बेबी जॉन को खारिज कर दिया. इसके बाद जनरल को बेबी जॉन के साथ सैन्य अधिकारी की तरह ही सख्ती से पेश आना पड़ा. उसके बाद जॉन सही हो गए और जहाज से ही भारत लौटे. ■

फंस गए भारतीय कामगार, काम आई भारत सरकार

सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों में नौकरी करने गए कामगारों को भी नियोक्ता कंपनियों की प्रताड़ना से उबारने का बीड़ा भी भारत सरकार ने ही उठाया. यह जिम्मेदारी भी जनरल वीके सिंह ने ही संभाली और सऊदी अरब सरकार से बात करके समस्या का हल निकाला. जनरल की बातों से प्रभावित सऊदी अरब के शाह ने भी सरकार को भारतीय कामगारों की समस्या का त्वरित हल ढूंढने का निर्देश दिया है. सऊदी अरब की नियोक्ताओं कंपनियों ने 7,700 कामगारों को नौकरी से निकाल दिया था. भारतीय कामगारों को विभिन्न शिविरों में रखा गया था. पहले तो कंपनियां उनका खाना दे रही थीं, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पहल और जनरल वीके सिंह की सऊदी अरब के श्रम और सामाजिक विकास मंत्री मुफरेज अल हकबानी से बातचीत के बाद इसका हल निकला. सऊदी सरकार ने कामगारों के खाने की व्यवस्था की.

कच्चे तेल की कीमतें घटने और सऊदी अरब की सरकार द्वारा खर्चों में कटौती करने के कारण खाड़ी देश की अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार हो गई है, जिससे हजारों भारतीयों की नौकरी चली गई. सऊदी गए विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने वहां के श्रम मंत्री से आग्रह किया कि नियोक्ता कंपनियों की एनओसी के बगैर बेरोजगार भारतीय कामगारों को निकासी (एक्जिट) वीजा उपलब्ध कराया जाए और कर्मचारियों के बकाये का भुगतान हो. सऊदी की प्रमुख नियोक्ता कंपनी मेसर्स सऊदी ओगर से जुड़े 4,072 भारतीय कामगार रियाद में नौ शिविरों में रह रहे थे. दूसरी कंपनी मेसर्स साद ग्रुप से जुड़े 1,457 कर्मचारियों को दम्माम में दो शिविरों में रखा गया था. मेसर्स शिफा सनाया के पांच कामगार रियाद में एक शिविर में थे जबकि मैसर्स तैया कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के 13 भारतीय कर्मचारी अन्य एक शिविर में थे. रियाद के चौदह शिविरों में रह रहे कुल 5,547 भारतीय कामगारों को भारतीय दूतावास द्वारा सहायता उपलब्ध कराई गई. जेद्दाह के छह शिविरों में मेसर्स सऊदी ओगर से जुड़े 2,153 भारतीय कामगार हैं, जिन्हें भारतीय वाणिज्य दूतावास की तरफ से भोजन उपलब्ध कराया गया. जनरल वीके सिंह ने कहा कि सऊदी का कानून अलग है, वहां जाकर पहले यह अध्ययन करना पड़ा कि आखिर कठिनाई क्या है. रेस्क्यु में मुश्किल यह भी आई कि वहां की कुछ कंपनियां विरोध में बदमाशियों पर उतर आईं. बिन लादेन कंपनी ने तो वहां तोड़फोड़ भी शुरू करा दी. साद कंपनी के लोगों ने भी तोड़फोड़ की, इससे क्या हुआ कि वहां फंसे चार पांच सौ लोगों को अलग कैंप में शिफ्ट कर दिया. जनरल ने जेद्दाह से रियाद जाकर वहां के श्रम मंत्री से मुलाकात की. भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष होने का भी फायदा उन्हें मिला. सऊदी अरब के शाह ने खास तौर पर ध्यान दिया और वहां से आदेश आ गया कि समस्या का फौरन हल निकालो. एकामा (आदेश-पत्र) बदले जाने की प्रक्रिया में देर हो रही थी. दूतावास के जरिए जो भारत वापस आना चाहते थे, उनका लंबित भुगतान कराए जाने की मांग भी अटकी थी. सऊदी सरकार से बात करने के बाद यह तय हुआ कि जो लोग लौट रहे हैं, उन्हें दो महीने की सैलरी दी जाए और बकाए के भुगतान की प्रक्रिया चालू हो. उन दावों को निर्धारित समय सीमा में सुलटाया जाए. उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जिन भारतीय कामगारों की नौकरियां चली गईं और उनकी हालत खस्ता थी, उनसे जनरल वीके सिंह ने मुलाकात की और समस्या का हल कराया. भारतीय कामगारों को एक्जिट वीजा दिए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं. वे क्रमशः भारत लौट रहे हैं. लौटने वाले कर्मचारियों के बकाए के भुगतान के लिए भी भारत सरकार पहल करेगी. ■

भारतीय कामगारों के लिए गहरी खाई बनते खाड़ी देश

सऊदी अरब में सैकड़ों भारतीय कामगार दाने-दाने को मोहताज हो गए. आर्थिक मंदी के कारण कई कंपनियों ने हजारों कामगारों को नौकरी से बाहर निकाल दिया. महीनों से वेतन बंद होने के कारण उनकी भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई. जेद्दा में इस तरह के 2,450 श्रमिकों के भारतीय वाणिज्य दूतावास की ओर से भोजन बांटे जाने के बाद यह खुलासा हुआ कि सऊदी की ओगर कंपनी इन कामगारों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं दे रही थी. इस एक कंपनी के 50 हजार कर्मचारियों में से करीब चार हजार कर्मचारी भारतीय हैं. उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब में करीब 30 लाख भारतीय प्रवासी हैं, जबकि करीब आठ लाख भारतीय कुवैत में हैं, जिनमें अधिकांश कारखानों में काम करने वाले कामगार हैं. भारतीय दूतावासों को भारतीय कामगारों की तरफ से जो शिकायतें मिल रही हैं, वे आश्चर्यजनक हैं. पिछले तीन साल में खाड़ी के नौ देशों के बारे में 55 हजार 119 कामगारों की शिकायत मिली हैं. इनमें से 87 फीसदी शिकायतें छह खाड़ी देशों से सम्बद्ध हैं. इनमें आधे 13 हजार 624 कतर और 11 हजार 195 कामगार सऊदी अरब के हैं. मलेशिया से 6 हजार 346 कामगारों की शिकायतें मिली हैं. हैरत का आंकड़ा यह भी है कि सऊदी अरब की जेलों में 1697 भारतीय कामगार बंद हैं. इसी तरह संयुक्त अरब अमीरात की जेलों में 1143 भारतीय कामगार में हैं. यह आंकड़ा किसी एनजीओ या किसी निजी संस्था का नहीं है. यह तथ्य विदेश मंत्रालय द्वारा 20 जुलाई 2016 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था. अमरिका में रह रहे भारतीयों की तुलना में सऊदी अरब या कुवैत में रहने वाले भारतीयों की खराब काम करने की स्थिति के कारण उनके मौत का जोखिम 10 गुना अधिक है. इस बारे में इंडिया-स्पेंड की रिपोर्ट (अगस्त 2015) बताती है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में प्रति एक लाख भारतीय कामगारों में से 65 से 78 कामगार विभिन्न कारणों से मर जाते हैं. छह खाड़ी देशों में औसतन हर वर्ष 69 भारतीयों की मृत्यु हो जाती है. दुनिया के बाकी हिस्सों में यह आंकड़ा 26.5 है, यानि खाड़ी देशों से करीब 60 फीसदी कम. ■

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 08 अंक 25
22 अगस्त- 28 अगस्त 2016

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोनः 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

feedback@chauthiduniya.com

अनशन खत्म संघर्ष जारी

एस. बिजेन सिंह

लोकतंत्र में जब कोई व्यक्ति व्यवस्था से हताश निराश हो जाता है, तो उसके पास बहुत सीमित विकल्प होते हैं. वह अपनी मांगों को लेकर धरना, भूख हड़ताल या सत्याग्रह करता है, लेकिन क्या इसके बावजूद उसे न्याय मिल पाता है? देश की लोकतांत्रिक सरकार ने 16 वर्षों से भूख हड़ताल कर रही इरोम शर्मिला की मांगें नहीं सुनीं. इन 16 सालों में सरकार ने शर्मिला से बात करने की जरूरत भी नहीं समझी. अब शर्मिला भूख हड़ताल छोड़कर चुनाव लड़ेंगी. ऐसे में इस देश में किसी अहिंसक आंदोलन का कितना महत्व रह जाएगा? इरोम राजनीति के जरिए कितना बदलाव ला पाएंगी, ये कुछ ऐसे सवाल हैं, जो आम जन को भीतर तक कुरेद रहे हैं.

आयरन लेडी के नाम से चर्चित इरोम शर्मिला ने 9 अगस्त को 16 साल से जारी अनशन तोड़ दिया. जेल से छूटने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि लोग उनको संत या देवी मान बैठे हैं, जबकि मैं एक सामान्य महिला हूं. इरोम को लगता है कि लोग उनको शहीद होना देखना चाहते हैं इसलिए वे उनके आंदोलन के तरीके बदलने से इत्तेफाक नहीं रखते. शर्मिला मणिपुर की मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं ताकि अफस्पा के मुद्दे को जिंदा रखा जा सके. उनका मानना है कि लोग राजनीति से घृणा करते हैं, लेकिन समाज में भी तो गंदगी है. उन्होंने कहा कि अगर 20 निर्दलीय प्रतिनिधि उनके साथ आएं तो वे चुनाव के बाद सीएम इबोबी की सत्ता पलट सकती हैं. उनका आंदोलन जारी है, वे कभी पीछे नहीं हटेंगी. शर्मिला मणिपुर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट-1958 (अफस्पा) हटाने की मांग कर रही थीं. 2017 को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में शर्मिला निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मुख्यमंत्री इबोबी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी. राज्य के लोग उनके इस कदम का विरोध कर रहे हैं. भूमिगत संगठनों ने भी शर्मिला को चिट्ठी लिखकर इसका विरोध किया है. हर वर्ग से विरोध की आवाज उठी. गौरतलब है कि शर्मिला ने 2 नवंबर 2000 से भूख हड़ताल शुरू किया था, जब इंफाल से नौ किलोमीटर दूर मालोम में असम रायफल्स के जवानों ने 10 लोगों को मार गिराया था. उनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे.

शर्मिला का मानना है कि वे अनशन से बदलाव नहीं ला पाईं. इन 16 सालों में उनके संघर्ष से सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी. अब वे एक नए तरीके से संघर्ष करेंगी. उन्होंने कहा कि संघर्ष वही है, केवल रणनीति बदला है. शर्मिला को इस बात का अफसोस है कि मणिपुर में हुई एक फर्जी मुठभेड़ में शामिल हेड कांस्टेबल हेरोजीत द्वारा कोर्ट के सामने अपनी गलती माने जाने के बाद भी प्रदेश की जनता चुप है. हेरोजीत ने कोर्ट के सामने कहा था कि अधिकारियों के ऑर्डर पर ही उन्होंने गोली मारी थी. इसके बाद अफस्पा के विरोध में चारों तरफ से आवाज उठनी चाहिए थी. उन्हें सबसे ज्यादा निराश इस बात से है कि इस आंदोलन में वे अकेली पड़ गई हैं. उनका मानना है कि जबतक लोग जनता के सच्चे प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे, तबतक समाज में बदलाव नहीं आएगा. इसलिए उन्होंने अफस्पा को मुद्दा बनाकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है. उन्होंने खुराई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की इच्छा जाहिर की. शर्मिला किसी राजनीतिक पार्टी का मुखौटा नहीं बनना चाहतीं. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने उन्हें पहले भी चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था.

शर्मिला अफस्पा विरोधी संघर्ष की नायिका रही हैं. 16 साल की भूख हड़ताल से शर्मिला ने मानवाधिकार हनन को चर्चा के केंद्र में ला दिया. ये 16 साल भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं. ये उन्हीं के प्रयासों की जीत है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1500 फर्जी मुठभेड़ मामले में संतोष हेगड़े कमेटी का गठन किया था. हालांकि, ये अलग बात है कि स्थानीय राजनीतिक पार्टियों ने उनका कभी समर्थन नहीं किया. शर्मिला के इस घोषणा से मुख्यमंत्री ओक्रम इबोबी सिंह और उनकी सरकार को सबसे ज्यादा राहत मिला है. अगर इन 16 सालों में शर्मिला को जेल वार्ड में कुछ हो जाता तो शायद मणिपुर को संभालना मुश्किल था. सरकार ने इन 16 सालों में शर्मिला को जिंदा रखने के लिए न जाने कितने पैसे खर्च किए? सरकार में शर्मिला को लेकर सपोर्ट कम दबाव ज्यादा था. शर्मिला के इस मौन अनशन के कारण ही इंफाल म्युनिसिपल एरिया से अफस्पा हटाना पड़ा था.

चुनाव के मैदान में शर्मिला कितनी सफल होंगी या अपनी मांग को लेकर कितना आगे जा पाएंगी यह अभी कहना मुश्किल है, लेकिन यह सच है कि उनके लिए राजनीति की डगर इतनी आसान नहीं है. वे किसी राजनीतिक पार्टी की प्रतिनिधि नहीं हैं, वे अकेली निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी. वे चुनाव में जीत-हार का सामना तो करेंगी ही, लेकिन उनकी दूसरी चुनौती यह होगी कि वे अफस्पा के मुद्दे को विधानसभा में जोरदार तरीके से उठा पाती हैं या नहीं.

इन 16 सालों में शर्मिला के समर्थन और अफस्पा के विरोध में कई जन संगठन तो बन गए, फिर भी यह जनांदोलन का रूप नहीं ले सका. शर्मिला के इस संघर्ष में कोई सांगठनिक ताकत नहीं है. वे हॉस्पिटल जेल के एक वार्ड में बैठकर चुपचाप अनशन करती रहीं. जब महात्मा गांधी ने अनशन किया था, तो उनके पीछे पूरे देश की ताकत थी. लेकिन शर्मिला के इस अनशन के साथ न तो शुरू में कोई संगठन था और न ही अब है. शुरू में छात्र संगठन भी उनके अनशन में शामिल होने से कतराते थे. 2004 के बाद शर्मिला के अनशन पर लोगों का समर्थन मिलने लगा. तबतक ह्यूमन राइट्स एवार्ड एवं रवींद्रनाथ टैगोर पीस अवॉर्ड शर्मिला को मिल चुका था. इसी दौरान शर्मिला को एक विदेशी युवक से प्यार हुआ, तब लोगों में इसे लेकर विरोध और गुस्सा था. इस बात पर मणिपुर की ईमा यानी महिलाओं से भी शर्मिला के मतभेद हो गए थे. उनके इस निजी फैसले से लोग आहत थे. शर्मिला एक साधारण महिला की तरह इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहती थीं. शर्मिला अपने आपको आंदोलन का नेता मानने से इनकार करती रहीं. शर्मिला के मना करने की वजह से फेस्टिवल ऑफ होप जस्टिस एंड पीस कैंपेन आगे नहीं बढ़ सका. यही कारण है कि शर्मिला से प्यार और समर्थन करने के बाद भी यह आंदोलन, एक राजनीतिक आंदोलन में नहीं बदल सका.

ऐसे में शर्मिला अगर राजनीति में आईं तो उनको राजनीति की सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ेगा. एक तरफ शर्मिला का निजी फैसला शादी व चुनाव लड़ना है, दूसरी तरफ सेना है. सेना हमेशा से अफस्पा के समर्थन में है. सेना की मर्जी के खिलाफ सरकार भी अफस्पा हटा नहीं सकती है. चुनाव के मैदान में शर्मिला कितनी सफल होंगी या अपनी मांग को लेकर कितना आगे जा पाएंगी यह अभी से कहना मुश्किल है, लेकिन यह सच है कि उनके लिए राजनीति की डगर इतनी आसान नहीं होगी. वे किसी राजनीतिक पार्टी की प्रतिनिधि नहीं हैं, वे अकेली निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी. वे चुनाव में जीत-हार का सामना तो करेंगी ही, लेकिन उनकी दूसरी चुनौती यह होगी कि वे अफस्पा के मुद्दे को विधानसभा में जोरदार तरीके से उठा पाती हैं या नहीं. इससे पूर्व नगालैंड विधानसभा ने अफस्पा हटाने का फैसला सर्वसम्मति से पास कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने नगालैंड सदन के फैसले को मंजूर नहीं किया. ऐसे में शर्मिला के राजनीति में आने का फैसला कितना कारगर होगा, इस पर लोगों की नजर टिकी है. ■

राज्य की ईमानदार कोशिश से ही हटेगा अफस्पा

लोकसभा सांसद सीएन जयदेवान के एक सवाल का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री किरन रिजिजू ने कहा कि मणिपुर में अफस्पा राज्य सरकार की वजह से लागू है. मणिपुर को अशांत क्षेत्र (डिस्टर्ब एरिया) की घोषणा राज्य सरकार ने ही की है. अफस्पा के मुद्दे पर राज्य सरकार समय-समय पर सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर समीक्षा करती है. गृह राज्य मंत्री के इस बयान के बाद जनता ने सोशल मीडिया पर एक अभियान छेड़ दिया. उन्होंने मांग रखी कि मुख्यमंत्री इबोबी सिंह को इस मामले में अहम निर्णय लेना चाहिए. फिर भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है. त्रिपुरा जैसे राज्य में मजबूत स्थानीय सरकार की वजह से मई 2015 को अफस्पा हटा लिया गया था. राज्य में कानून-व्यवस्था दुरुस्त होने पर राज्य सरकार ने अफस्पा हटाने का निर्णय लिया था. लेकिन नगालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और मेघालय की अशांत स्थिति को देखकर वहां अब भी अफस्पा लागू है. नगालैंड विधानसभा ने सर्व-सम्मति से फैसला लेकर अफस्पा हटाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, फिर भी केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया था. नगालैंड डिस्टर्ब एरिया घोषित है. नगालैंड में एनएससीएन (आईएम) के साथ केंद्र सरकार से वार्ता चल रही है इसलिए वहां का राजनीतिक परिदृश्य अलग है. मणिपुर में भी 16 वर्षों से इरोम शर्मिला यह मांग करती रही है. लेकिन राज्य सरकार ने इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं ली. यह सच है कि राज्य की कानून-व्यवस्था के मद्देनजर केंद्र सरकार अफस्पा को लेकर राज्य सरकार के फैसले पर हस्तक्षेप कर सकती है. केंद्र की स्वीकृति के बिना किसी भी राज्य से अफस्पा हटाना संभव नहीं है.

आखिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस बयान से पूरी तरह से इनकार भी नहीं किया जा सकता. मणिपुर राज्य सरकार ने लापरवाही जरूर बरती है. इतने लंबे समय से अफस्पा को लेकर लोग मर रहे हैं, कई अप्रिय हिंसा हुई, 2004 में असम रायफल्स के जवानों ने थांगजम मनोरमा से दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी, 2004 में ही मनोरमा की हत्या के खिलाफ पेबम चितरंजन ने अपने ऊपर तेल छिड़ककर आग लगाकर आत्महत्या कर ली. असम रायफल्स के गेट पर मणिपुर की महिलाओं ने नंगा प्रदर्शन किया. बैनर में लिखा था कि इंडियन आर्मी रेप अस. यह भारतीय राजनीति के इतिहास में एक काला अध्याय था. इतना सब होने के बाद भी राज्य सरकार 16 साल से मौन है. ऐसे में किरण रिजिजू का बयान गलत नहीं है. हो सकता है चुनाव के मद्देनजर यहां की जनता इसे एक राजनीतिक बयानबाजी माने. लेकिन ये भी उतना ही सच है कि केवल सिविल ऑर्गेनाइजेशन्स और शर्मिला के चिल्लाने भर से केंद्र सरकार भला क्या करेगी? केंद्र सरकार कितनी मदद करती है यह तो राज्य सरकार की ईमानदार कोशिश पर निर्भर है. ■

असम में शांति को चुनौती

असम के कोकराझाड़ में पांच अगस्त को आतंकवादियों के हमले में 14 लोग मारे गए और 20 से ज्यादा घायल हुए. इस हमले के पीछे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, एनडीएफबी (एस) का हाथ माना जा रहा है. यह घटना कोकराझाड़ के एक भीड़-भाड़ बाजार में अंजाम दिया गया था. सिक्योरिटी फोर्स ने भी जवाबी हमले में एक आतंकवादी को मार गिराया. यह घटना बोडो बहुल इलाकों में पिछले दो साल की सबसे बड़ी घटना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की इस घटना की निंदा की. नव निर्वाचित असम के मुख्यमंत्री सोनोवाल का मानना है कि कोकराझाड़ हमले में बाहरी शक्ति शामिल हो सकती है. इसकी जांच की जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्रोही हमले कर सस्ती लोकप्रियता बटोरना बंद करें. डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) एक सशस्त्र अलगाववादी संगठन है, जो 1986 में गठित किया गया था. इसकी कई शाखाएं हैं एनडीएफबी (आर), एनडीएफबी (पी), एनडीएफबी (एस). यह संगठन बोडो आदिवासी इलाकों में सक्रिय सबसे बड़ा ताकतवर संगठन है. बोडो उग्रवादी असम में पृथक बोडो राज्य बोडोलैंड की मांग कर रहे हैं. इसी वजह से वे बाहरी लोग जैसे संथाल, मुंडा और ओराउन आदिवासी, जो अंग्रेज सरकार के समय में असम चाय बागानों में मजदूरी के लिए लाए गए थे, को भगाना चाहते हैं. एनडीएफबी

प्रवासी बंगाली मुस्लिमों पर भी निशाना बनाए हुए थे. विवाद की जड़ में स्थानीय आदिवासी और घुसपैठी मुसलमान हैं. दरअसल बोडोलैंड स्वायत्त परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गैर बोडो समुदायों ने बीते कुछ समय से बोडो समुदाय की अलग राज्य बनाने की दशकों पुरानी मांग का विरोध शुरू कर दिया है. इस विरोध में गैर बोडो सुरक्षा मंच और अखिल बोडोलैंड मुस्लिम छात्र संघ की प्रमुख भूमिका रही है. जाहिर है यह पहल बोडो आदिवासियों को रास नहीं आ रही है. इन पुश्तैनी वाशिंदों की नाराजगी का कारण यह भी है कि सीमा पर से घुसपैठी मुसलमान उनके जीवन यापन के संसाधनों को लगातार हथिया रहे हैं. यह सिलसिला 1950 के दशक से जारी है. इसलिए राज्य सरकार के विरोध में वे समय-समय पर इस तरह के हमले कर विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं. बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के नेता हग्रामा मोहिलारी ने तो पिछले विधानसभा में भाजपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ा था. असम, मणिपुर सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में 15 अगस्त और 26 जनवरी का वहां के आतंकवादी गुट हमेशा विरोध करते रहे हैं. इसके चलते सुरक्षा बल व खुफिया एजेंसियां पहले से ही सतर्क हैं, इसके बावजूद हमला हुआ. केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार है, इसलिए यह बहाना नहीं चल सकता कि राज्य और केंद्र की गुप्तचर संस्थाओं के बीच अपेक्षित ताल-मेल की कमी थी. ■

sbijensngh@gmail.com

इंसानी लोभ का प्रतिशोध है बाढ़

चंदन राय

पानी...पानी... जहां तक देखिए, हर तरफ हिलोरें लेता अथाह जल प्रवाह. जल प्रलय के बीच उब-डुब होकर टीले की तरह दिखते गांव. पानी में बहते पशु व अन्य जान-माल. सिर पर गृहस्थी का सामान रख कुछ बचा लेने की जद्दोजहद में पानी के तेज बहाव से जूझते किसान. कमोबेश देश के कुछ हिस्सों में हर साल बाढ़ का ऐसा ही हृदय विदारक दृश्य होता है. लेकिन इनमें कुछ अभागी महिलाएं, बच्चे व पुरुष खुशकिस्मत नहीं होते. बाढ़ में न जाने कितनी महिलाएं बच्चों को गोद में लिए अथाह जलराशि में समा जाती हैं. बाढ़ का पानी उतर जाए, तो भी मुसीबत कम नहीं होती. जल जनित रोग, महामारी, अकाल और न जाने कितनी ढेर सारी मुसीबतें.

हमारा देश दुनिया के सबसे अधिक बाढ़ संभावित देशों में से एक है. गृह मंत्रालय के अनुसार, 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 23 राज्य बाढ़ की दृष्टि से अतिसंवेदनशील हैं. इस बार असम से लेकर जम्मू तक बाढ़ की विनाशलीला जारी है. राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार, झारखंड, जम्मू और हिमाचल के कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है. इस बार देश के 11 राज्यों के 33 करोड़ लोगों ने बाढ़ की विभीषिका झेली है. सिर्फ मैदानी क्षेत्र ही नहीं, पहाड़ी क्षेत्र भी पानी की मार झेल रहे हैं. उत्तराखंड में बेस्तड़ी जैसे कई गांवों ने जलसमाधि ले ली है.

मध्यप्रदेश में 23 से ज्यादा जिलों में सामान्य से अधिक बारिश होने से लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं. सतना जिले में 300 गांवों के करीब डेढ़ लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. वहीं बिहार में कोसी, महानंदा व कमला बलान नदियों का जलस्तर बढ़ने से हर तरफ तबाही का मंजर है. अनुमान है कि बाढ़ के प्रकोप से यहां 13 जिलों के 31 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. अब तक 61 लोगों की मौत हो चुकी है. राज्य के पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, दरभंगा, मधेपुरा, भागलपुर, कटिहार, सुपौल, सहरसा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज समेत मुजफ्फरपुर जिले के 69 प्रखंड बाढ़ की चपेट में हैं. बाढ़ से 13 हजार से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 1.61 लाख हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो गई है. छह लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें से करीब 3.78 लाख लोग राहत शिविरों में शरण लिए हैं. वहीं असम में बाढ़ से मरने वालों की तादाद 31 तक पहुंच गई है. राज्य के 21 जिलों में 2500 गांवों में 17 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. महाराष्ट्र के महाड़ में एक ब्रिटिशकालीन पुल के बाढ़ में टूट जाने से कई वाहन बह गए, जिनमें कई लोगों के मरने की आशंका है. नासिक में रिकॉर्ड बारिश होने से शहर पानी-पानी हो गया है.

बाढ़ महज एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक मानवजनित भीषण आपदा है. सरकार का तर्क है, औद्योगिक विकास के लिए ऊर्जा जरूरी है और ऊर्जा चाहिए तो फिर नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को रोकने के लिए बड़े-बड़े बांध भी बनेंगे ही. ऐसे में नदियां अपने प्राकृतिक प्रवाह को रोके जाने का प्रतिशोध बाढ़ की विनाश लीला के रूप में लेती हैं. दरअसल विकास और विनाश साथ-साथ ही चलते हैं. नदी घाटी क्षेत्रों में जंगलों का तेजी से कटान हो रहा है. इससे नदी के तटों की मिट्टी को पकड़ कर रखने की क्षमता कमजोर हो जाती है और मिट्टी व कीचड़ नदी की तलछट में जमा होने लगते हैं. इससे नदियों की बारिश के पानी को समेट कर रखने की क्षमता समाप्तप्राय हो जाती है. थोड़ी सी बारिश में ही वे उफनकर बांधों को तोड़ती हुई आस-पास की मानवीय आबादी को अपनी आगोश में ले लेती हैं. वहीं मैदानी इलाकों में सिंचाई के लिए नदियों से कई नहरें निकाली जाती हैं. नदियों में पानी कम रह जाने से वे गाद को समुद्र तक ढोकर नहीं ले जा पाती हैं. ऐसे में उथली और सपाट नदियां थोड़ी बारिश में ही विकराल रूप धारण कर लेती हैं. नदियों के मुहाने पर बसी रिहायशी बस्तियां इस समस्या को और बढ़ा देती हैं. इससे नदियों का प्राकृतिक प्रवाह गड़बड़ा जाता है और बाढ़ का पानी तटबंधों को तोड़कर शहरों में घुस आता है. सरकार की काहिली के कारण अब शहर के संभ्रांत लोग भी बाढ़ जैसे हालात झेलने को मजबूर हैं.

कुछ पर्यावरणविदों का मानना है कि बारिश के मौसम में नदियों में पानी के प्रवाह को न्यूनतम बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए. लेकिन इसके उलट, सरकार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए नदियों पर बड़े-बड़े बांध बनाकर पानी के स्तर को और बढ़ा देती है. बांधों में जब पानी का स्तर अधिकतम हो जाता है, तो बांध के गेटों पर बढ़ रहे प्रेशर को कम करने के लिए बिना पूर्व सूचना के गेट खोल दिए जाते हैं. नदियों में पानी का प्रवाह अचानक तेज होने से वे तटबंधों को तोड़ती हुई अपना रास्ता बदल लेती हैं और तट के किनारे बसे मानवीय आबादी पर आपदा के रूप में टूट पड़ती हैं. पर्यावरणविदों व स्थानीय लोगों की मांगों को अनसुना कर बांध बनाते समय बांध निर्माता कंपनियां बाढ़ सुरक्षा के बड़े-बड़े दावे करती हैं, लेकिन तबाही के बाद इन दावों की असलियत सामने आती है. सवाल ये है कि सरकार मानव जनित आपदा के लिए इन बांध निर्माता कंपनियों को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा करती? उनसे यह क्यों नहीं पूछा जाता कि आपके बांध सुरक्षा के उन दावों का क्या हुआ? लेकिन जब सरकार खुद उन बांध निर्माता कंपनियों की हिफाजत में निरीह जनता पर लाठियां बरसाने को तैयार हो, तो जनता के पास राहत शिविरों में शरण लेने के अलावा और क्या उपाय रह जाता है?

कछार या टाल का इलाका नदियों का घर होता है. उपजाऊ मिट्टी होने के कारण इसका इस्तेमाल खेती के लिए किया जाना चाहिए, न कि व्यावसायिक गतिविधियों या मानवीय रिहाइश के लिए. अगर आप नदियों के घर में अनधिकृत रूप से घुसेंगे, तो वे फिर इस अतिक्रमण को रोकने के लिए अपना विस्तार करेंगी ही. इसके अलावा नदियों के मैदानी इलाकों में पेड़-पौधों को लगाया जाना चाहिए. पेड़-पौधों में जल संग्रहण क्षमता होने के कारण वे बारिश के पानी को रोक कर रखती हैं. इतना ही नहीं, तटीय इलाकों में हरियाली होने से मिट्टी का कटाव कम होगा, जिससे नदियों में गहराव बना रहेगा और वे बारिश में उथली होकर जल्द उफनेंगी नहीं. सरकार को भी चाहिए कि वह अंधाधुंध बड़े बांध बनाए जाने की नीति पर पुनर्विचार करे. नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को जहां तक हो सके, बाधित नहीं करने का प्रयास करना चाहिए. नदी-जोड़ो परियोजना के जरिए एक नदी में पानी के अत्यधिक प्रवाह को दूसरी सहायक नदियों की ओर मोड़ा जा सकता है, ताकि पानी का दवाब किसी एक जगह पर पड़ तबाही न ला सके या उसके प्रकोप को कम किया जा सके.

भारतीय संविधान के अनुसार नदी, जल व बाढ़ संबंधी नियंत्रण कार्य राज्यों के विषय हैं. इसके बावजूद केंद्र ने 1990 में राज्यों के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर बाढ़ प्रबंध का कार्यक्रम चालू किया. यह आयोग बाढ़ प्रबंध योजनाओं का मूल्यांकन और मॉनिटरिंग करता है. लेकिन सरकार की इन योजनाओं और प्रबंधन के बावजूद बाढ़ को नियंत्रित नहीं किया जा सका. रस्मी तौर पर सरकार हर साल बाढ़ से निपटने के लिए ठोस योजनाएं व कार्यक्रम बनाती है, लेकिन बाढ़ आते ही ये योजनाओं पानी में तैरने लगती हैं. बाढ़ और बारिश की प्रतिद्वंद्विता में सरकारी कार्यक्रम दम तोड़ देते हैं. टिकाऊ और दीर्घकालिक योजनाएं बनाकर व पूर्व चेतावनी तंत्र विकसित कर ही बाढ़ की आपदा को कम किया जा सकता है. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अपनी श्रेष्ठता का इस्तेमाल कर बाढ़ पूर्व चेतावनी का इस्तेमाल आपदा नियंत्रण में किया जा सकता है.

प्रसिद्ध गांधीवादी अनुपम मिश्र कहते हैं, बाढ़ अतिथि नहीं है. यह कभी अचानक नहीं आती. दो-चार दिन का अंतर पड़ जाए तो बात अलग है. इसके आने की तिथियां बिलकुल तय हैं. लेकिन जब बाढ़ आती है तो हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे यह अचानक आई हुई विपत्ति है. इसके पहले जो तैयारियां करनी चाहिए, वे बिलकुल नहीं हो पाती हैं. इसलिए अब बाढ़ की मारक क्षमता और बढ़ गई है. बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के निवासी बाढ़ के साथ जीने की कला सीख लेते हैं. बाढ़ अपना रौद्र रूप दिखाकर फिर अपनी जलधारा में लौट आता है. सरकार कुछ कार्यक्रमों का आयोजन कर इतिश्री कर लेती है. मीडिया भी मौत के आंकड़ों को गिनने में जुट जाता है. हर साल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की यही कहानी है. कुछ भी नहीं बदलता, बस पीछे छूट जाती हैं अपनों को खोजती हुई कुछ नम आंखें, आहें, क्रंदन-रुदन. ■

हिमालय से छेड़छाड़ आफत को बुलावा

हिमालय सबसे कम उम्र का पहाड़ है. इसकी विकास प्रक्रिया निरंतर जारी है. इसके बड़े भाग में चट्टानें न होकर, मिट्टी हैं. बारिश में जब यहां का पानी ढलान से नीचे की ओर बहता है, तो मिट्टी उसे आसानी से रास्ता दे देती है. इसके अलावा पेड़-पौधों की कमी होने से पानी तेजी से मैदानी इलाकों की ओर बढ़ती हैं. पहाड़ी ढालों पर वनों के रहने से पत्तियों के आच्छान के कारण वर्षा जल का बहाव तेज नहीं होता है. इससे मिट्टी का बहाव भी कम होता है और मैदानी इलाकों में बाढ़ की आशंका कम होती है.

राहत की लूट

दरअसल, नेताओं व अधिकारियों के लिए बाढ़ एक वार्षिक कार्यक्रम की तरह है, जो हर साल तय समय पर आता है. इस बाढ़ टूरिज्म के दौरान नेता व अधिकारी हवाई दौरे पर निकल पड़ते हैं. बाढ़ प्रबंधन, राहत, मुआवजा, पुनर्वास के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं. किसान रबी और खरीफ के बाद एक और फसल रिलीफ फसल काटे जाने का इंतजार करने लगते हैं. जहां सरकारी अधिकारियों की नजर रिलीफ फंड पर टिकी होती है, वहीं राहत शिविरों में शरण लिए आम लोग खाने के पैकेट की छीना-झपटी में लगे रहते हैं. कमोबेश हर साल निरीह जनता इसी तरह बाढ़ की विनाशलीला का इंतजार करती है. खैर, इंतजार तो नेताओं व अधिकारियों को भी होता है, रिलीफ फंड का. जितना भयंकर बाढ़ का प्रकोप, उतना ज्यादा रकम अंदर. ■

feedback@chauthiduniya.com

परिजनों ने मुंह फेरा तो मानसिक अस्पताल बना ठिकाना

अपनों के लौटने की बाट जोह रही महिलाएं

प्रशांत शरण

देवघर की संगीता की कहानी अजीब है. जिस बेटे को उन्होंने बड़े प्यार से पाल-पोसकर बड़ा किया, उसी ने मुश्किल घड़ी में मुंह फेर लिया. पिता की मौत के बाद बेटे ने अपनी मां को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था. मां ने पहले ही अपनी सारी संपत्ति बेटे के नाम कर दी थी, तब भी बेटे को उस पर तरस नहीं आया. इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब कलियुगी बेटे ने अपनी मां को पागल बताकर रांची के मानसिक अस्पताल रिनपास में भर्ती करा दिया. वे करीब 22 वर्षों से इस अस्प-ताल में भर्ती हैं. पूरी तरह से स्वस्थ होने के बावजूद बेटे ने अपनी मां को पहचानने से ही इनकार कर दिया है. अच्छे पद पर कार्यरत होने के बाद भी बेटा अपनी मां को घर लाने के लिए तैयार नहीं है.

संगीता जैसी कई औरतों की यहां एक ही दास्तां है, जिन्हें उनके परिजनों ने त्याग दिया है. उनके अपने ही अब बेगाने हो गए हैं. ये महिलाएं अब अस्पताल परिवार की ही सदस्य हो गई हैं. इन महिलाओं के परिजनों ने ऐसा जख्म दिया कि वे मानसिक रोगी हो गईं. इसके बाद परिजन उन्हें रांची के मानसिक आरोग्यशाला रिनपास में भर्ती करा चले गए. ईलाज के बाद ऐसी महिलाएं ठीक भी हो गईं, पर उनके परिजन कभी नहीं लौटे. अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को दर्जनों बार फोन भी किया, पर परिजनों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया. परिवार द्वारा दिये गये दर्द का यह असर हुआ कि वे अब इस मानसिक अस्पताल के ही अंग होकर रह गए हैं. 550 बेड वाले इस मानसिक अस्पताल में ऐसे करीब 80 स्थायी रोगी हैं, जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं. इनमें से कुछ तो बड़े घरों से संबंध रखती हैं, पर जब परिजन ही भाग्य के सहारे छोड़ दें, तो फिर कहां जाएं? इनमें से कुछ जमीन-जायदाद विवाद में तो कुछ पतियों ने दूसरी महिलाओं से संबंध होने के कारण, तो कुछ बेटों ने अपनी मां से छुटकारा पाने के लिए पागल बताकर इस अस्पताल में भर्ती करा दिया.

हद तो तब हो जाती है, जब मरने के बाद भी परिवार का कोई सदस्य शव लेने नहीं आता है. अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने अपनी पत्नी को यहां ईलाज के लिए भर्ती कराया था. जांच में डॉक्टरों ने पाया कि उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी, उनमें रोग के कोई लक्षण नहीं पाये गये. लेकिन इस अधिकारी ने अपनी पहुंच और पैरवी के बल पर अपनी पत्नी को जबरन भर्ती करा दिया. एक-दो माह बाद जब अस्पताल प्रबंधन ने अधिकारी को सूचित किया कि उनकी पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, वे उसे अस्पताल से ले जाएं, तो अधिकारी ने अपनी पत्नी को पहचानने से ही इनकार कर दिया. उन्होंने साफ तौर पर यहां तक कह दिया कि उनकी पत्नी अस्पताल में भर्ती हुई ही नहीं. उनके बेटा, जो एक अधिकारी है, को भी इस संबंध में जानकारी दी गई तो उसने अपनी मां को ले जाने में असमर्थता जताई. पर जब इन्हीं महानुभावों को किसी कागज पर दस्तखत कराना था, तो बाप-बेटे दोनों पहुंच कर कुछ कागजातों पर हस्ताक्षर कराये, फिर चुपचाप यहां से चले गये. इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों की संवेदनाएं कितना मर गयी हैं.

सामाजिक कार्यकर्ता वासवी का कहना है कि रिनपास में भर्ती अधिकतर महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं. परिवार के लोग जमीन-जायदाद एवं संपत्ति पर कब्जा करने के लिए अकेली या विधवा महिलाओं को जबरन पागल करार देकर अस्पताल में भर्ती करा देते हैं. रांची के पास के गांव की एक महिला की पंद्रह एकड़ जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से रिनपास में भर्ती कराकर उसे पागल बना दिया गया. उस महिला की कोई संतान नहीं थी और पति की कम उम्र में मृत्यु हो जाने के बाद उसकी संपत्ति पर परिवार वालों की नजर थी. ऐसा कर परिजनों ने उसकी पूरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया.

रिनपास के क्लीनिक साइकोलॉजी विभाग के हेड डॉ. जय प्रकाश का कहना है कि अस्पताल में कई ऐसे मरीज हैं, जिन्हें समाज अब स्वीकार नहीं करना चाहता है. उनके परिवार ने उनसे नाता तोड़ लिया है. चालीस वर्षों से कई मरीजों का आसरा अस्पताल बना हुआ है. धुंधली यादों में ये महिलाएं अपने घर को खोजने का प्रयास तो जरूर करती हैं, लेकिन अंत में उन्हें अपने परिजनों से निराशा ही हाथ लगती है. ऐसे में उन्हें अस्पताल प्रबंधन ही उनके परिवार का हिस्सा बनकर सहारा देता है. यहां उनकी उचित तरीके से देखभाल की जाती है और हर समस्या का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है.

बिहार की एक महिला की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि एक साठ वर्षीया महिला जो नवादा की रहने वाली थी, उसकी मौत पिछले वर्ष रिनपास में हो गयी थी. वे पिछले तीस साल से अस्पताल में थीं. उनके परिवार वालों को कई बार उनकी मृत्यु हो जाने की सूचना दी गई, पर उनका शव तक लेने कोई नहीं आया, आखिरकार अस्पताल प्रबंधन ने ही अंतिम संस्कार की जिम्मेवारी भी उठाई. अब तो रिनपास ने ऐसे मरीजों के दाह संस्कार के लिए एक अलग से फंड ही बना लिया है.

बिहार की ही एक अन्य महिला का स्थायी पता अब रिनपास ही बन चुका है. अब उनके परिवार के सदस्य यहां के डॉक्टर एवं केयरटेकर हैं. इनकी संपत्ति एक जोड़ी कपड़ा और बेड पर बिछा हुआ चादर है. इन्होंने अपनी जिंदगी के चालीस साल अस्पताल की चारदीवारी के भीतर ही गुजार दिए. यादों के पिटारे से गांव का नाम कभी-कभी जुबां पर लाती हैं. बेटे और पति का चेहरा भी पूरी तरह याद है. परिवार पूरी तरह से सुखी-संपन्न है, पर पिछले कई वर्षों से कोई देखने भी नहीं आ रहा है. अस्पताल प्रबंधन ने कई बार इस महिला को घर भेजने की कोशिश की. दर्जनों बार पत्र भेजा गया, आदमी भी भेजे गए, पर परिवार वालों ने अपनाने से ही इनकार कर दिया. यह महिला हमेशा गुमसुम सी अपनी यादों में खोई रहती है. कोई पास बैठता है तो अपने बच्चों और पति के संबंध में तरह-तरह की बातें करती हैं, पर उनकी जेहन में बसे ये नाम उनके लिए खुद बेगाने हो गए. धनबाद की नीलिमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. उसके पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें घर पहुंचा दिया था, पर लगभग एक सप्ताह बाद परिवार वाले उसे फिर गेट पर छोड़कर चले गये. वह लावारिस हालत में अस्पताल के बाहर पड़ी हुई थीं, परिवार वालों ने उसे दवाईयां भी नहीं दी थीं, आखिरकार अस्पताल प्रबंधन ने फिर से मजबूरी में अस्पताल में भर्ती कर लिया. अब फिर वह इसी अस्पताल की होकर रह गई है.

इस अस्पताल के मरीजों की ऐसी हृदय विदारक कहानियां सुन पत्थर दिल इंसान भी पसीज सकता है, लेकिन इनके परिजनों को दया नहीं आई. इन महिलाओं को एक ही समस्या है कि वे स्वस्थ होने के बाद भी जाएं तो कहां जाएं? जब अपनों ने ही मुंह फेर लिया, तो फिर समाज में किससे आसरे की उम्मीद करें. ऐसे में ये लोग अस्पताल परिसर को ही स्थायी ठिकाना बना लेते हैं. अस्पताल प्रबंधन से जब इन महिलाओं को मिल रही सुविधाओं के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि ये हमारे परिवार की तरह हैं. हम ऐसे मरीजों को खाना-पीना, रहना, दवा, साज-श्रृंगार के समान, कपड़े व खाना बनाने की सुविधा भी देते हैं. इसके अलावा साल में अस्पताल प्रबंधन द्वारा दो बार विभिन्न स्थानों पर घुमाने के लिए ले जाया जाता है. इनलोगों को सिलाई-कढ़ाई एवं अन्य तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है.

सामाजिक कार्यकर्ता वासवी का कहना है कि रिनपास में भर्ती अधिकतर महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं. परिवार वाले जमीन-जायदाद एवं संपत्ति पर कब्जा करने के लिए अकेली या विधवा महिलाओं को जबरन पागल करार देकर अस्पताल में भर्ती कराकर चले जाते हैं. रांची के पास के गांव की एक महिला की पंद्रह एकड़ जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से रिनपास में भर्ती कराकर उसे पागल बना दिया गया. उस महिला की कोई संतान नहीं थी और पति के कम उम्र में मृत्यु हो जाने के बाद उसकी संपत्ति पर परिवार वालों की नजर थी. ऐसा कर परिजनों ने उसकी पूरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया. कुछ को डायन-बिसाही एवं कुछ पतियों ने दूसरी महिला के प्यार में फंसकर अपनी पत्नी को पागल करार दिया और फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के सहारे इस अस्पताल की चारदीवारी के भीतर पहुंचा दिया. अस्पताल प्रबंधन की समस्या है कि इन महिलाओं के कारण दूसरे मरीजों को यहां जगह नहीं मिल पाती है. सबसे दुखद यह है कि स्वस्थ होने के बाद भी हमेशा गंभीर मरीजों के बीच रहने के कारण इनकी मानसिक स्थिति भी वैसी ही हो जाती है.■

feedback@chauthiduniya.com

बड़वानी

नर्मदा डूब क्षेत्र के इन गांवों का क्या होगा

चौथी दुनिया ब्यूरो

सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की मांग आज तक पूरी नहीं हुई है. मध्य प्रदेश के बड़वानी के खारिया भादल समेत कई गांवों पर पानी का कहर टूट पड़ा है. इन गांवों को बचाने के लिए कई संगठन आंदोलन कर रहे हैं. नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले मेधा पाटकर के नेतृत्व में गांववालों ने जल, जंगल और जमीन हक सत्याग्रह 30 जुलाई से शुरू किया. 7 अगस्त तक आते-आते गांव का कई हिस्सा डूब क्षेत्र में आ गया था, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. 9 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले में थे. आजादी के 70 वर्ष पूरे होने पर वे शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भाबरा गए थे. यहां से करीब 70 किमी दूर बड़वानी जिला और तहसील का खारीया भादल गांव पानी से भरना शुरू हो गया था.

गौरतलब है कि खारीया भादल मध्य प्रदेश के बड़वानी तहसील के 7 वनग्रामों में से एक है. 30 वर्षों से यहां के लोग पुनर्वास की लड़ाई लड़ रहे हैं. नर्मदा डूब क्षेत्र के किसानों और आदिवासियों को अभी तक उचित पुनर्वास सुविधा नहीं मिली है. दूसरी तरफ, सरकार की ओर से सरदार सरोवर गेट बंद करने की बात की जा रही है. इससे पूरे गांव और क्षेत्र पर डूब का खतरा मंडराने लगा है. इसी बात को लेकर सरदार सरोवर बांध से प्रभावित गांव के लोग बड़वानी के राजघाट पर 30 जुलाई से ही अनिश्चितकालीन जल हक सत्याग्रह कर रहे हैं. मेधा पाटेकर का कहना है कि इस डूब क्षेत्र के कई गांवों का अब तक पुनर्वास नहीं हुआ है. वे कहती हैं कि सरकार वर्षों से डूबे गांवों को अब डूब से बाहर बता रही है, लेकिन समस्या अब भी जस की तस बनी हुई है. उनका कहना है कि इसी वजह से सरदार सरोवर डैम के गेट लगाने का विरोध हो रहा है.

क्या है मांग

1. जमीन के बदले जमीन उपलब्ध कराई जाए.
2. पुनर्वास के बिना बांध की ऊंचाई न बढ़ाई जाए.
3. सरदार सरोवर के गेट बंद नहीं किए जाएं.
4. झा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए.
5. जीरो बैलेंस बताया जा रहा है, जबकि गांव में लोग रह रहे हैं.
6. बांध की ऊंचाई बढ़ाने पर डूब क्षेत्र कम कैसे हुआ, ये स्पष्ट किया जाए.
7. सभी पुनर्वास स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं दी जाएं.
8. मछुआरों को मछली पकड़ने का अधिकार दिया जाए.
9. भूमिहीनों को व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता दी जाए.

खारीया भादल गांव की जमीन 7 अगस्त से ही डूबने लगी थी. इससे नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का झूठ भी सामने आ गया, जिसमें प्राधिकरण ने बताया था कि ये डूब क्षेत्र नहीं है, जबकि यहां के परिवारों को 2006 से और इस साल भी डूब की समस्या झेलनी पड़ रही है. इस बार भी अगर नर्मदा का जलस्तर और बढ़ा तो भादल के साथ ही आस-पास के तुअरखेरा, करही, धजाड़ा, ककराना के भी डूब क्षेत्र में आने का खतरा बढ़ जाएगा. नर्मदा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही खारीया भादल गांव के पूर्ण रूप से डूब जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है. कई मकान, जमीन और दुकान पानी में डूब चुके हैं. मेधा पाटेकर का कहना है कि मध्यप्रदेश सरकार कहती है कि सरदार सरोवर बांध की डूब में आने वाले सभी गांवों और परिवारों का पुनर्वास हो चुका है लेकिन उनका यह दावा पूरी तरह से झूठा है, क्योंकि अब भी डूब प्रभावित क्षेत्र में 48 हजार परिवार निवास कर रहे हैं. उनकी अब तक किसी ने सुध नहीं ली है. उन्होंने यह भी आरोप लगाए कि मध्यप्रदेश और गुजरात सरकार की यह रणनीति है कि बांध के पूरा भरते ही जब यह क्षेत्र पूरी तरह से डूब जाएगा, तो प्रभावित लोग खुद ही घर-जमीन छोड़ देंगे और सरकार को पुनर्वास की व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ेगी. अगर ऐसा हुआ तो आप मान लें कि सरकार ने 244 गांव और एक नगर को डुबोए जाने की तैयारी कर ली है.

पुनर्वास के नाम पर खारीया भादल के कुल 11 लोगों को खलघाट में खेत तो मिला, लेकिन आज तक उन्हें घर बनाने के लिए जमीन नहीं मिली. खेती के लिए जो जमीन मिली थी, उसे भी लेकर समस्या थी. इस गांव के लोगों को महेश्वर तहसील की रावरघाटी गांव की जमीन दी गई थी. भादल गांव के लोग इसका विरोध कर रहे थे. जब पुनर्वास अधिकारी, बड़वानी ने इन लोगों के साथ क्षेत्र में जाकर, प्रत्यक्ष जांच की तो पता चला कि रावरघाटी में 34.350 हेक्टेयर जमीन में से 19.350 हेक्टेयर जमीन तो खेती लायक है ही नहीं. इतना ही नहीं, बाकी जमीन पर कई वर्षों से आदिवासी खेती कर रहे हैं, जिसपर उनका कानूनी हक है और वहां से उन्हें हटाना संभव नहीं है. खारीया भादल के कुल परिवारों में से करीब 19 घोषित आदिवासियों को आज भी जमीन नहीं मिला है. 2006 से ही यह इलाका डूब में आता गया, जिससे ये लोग बारिश में खेती भी नहीं कर पाते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

गुजरात में दलितों की पिटाई और राजस्थान में गायों की मौत के बाद सियासत तेज़

गाय के नाम पर धर्म नहीं, धंधा

गुजरात में कथित गौरक्षकों ने जिस तरह दलितों को सार्वजनिक और बर्बर तरीके से पीटा और जिस तरह राजस्थान में गायों की मौत की तस्वीरें सामने आईं, उसने देश के लोगों को दुख पहुंचाया और राजनीतिक दलों को राजनीति करने का मौका दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सार्वजनिक सभा में गौरक्षा के नाम पर धंधा करने वालों को धिक्कारा तो अन्य राजनीतिक दलों ने इसे नाकाफी बताया. मोदी ने कहा कि गाय के नाम पर धर्म नहीं, धंधा हो रहा है. कई लोगों ने गौरक्षा के नाम पर दुकानें खोल रखी हैं. ऐसे गौरक्षकों को देख कर बहुत गुस्सा आता है.

डॉ. दिलीप कुमार सिंह

गाय धंधा हो गई है. सियासतदानों के लिए भी और व्यापारियों-माफियाओं के लिए भी. राजस्थान में जिस तरह गौशाला में नारकीय अवस्था में गायों को घिसटते हुए और मरते हुए देखा गया, उसने पूरे देश के लोगों का दिल दहला दिया. पूरा देश ऐसे गौरक्षकों के प्रति घृणा से भर गया. गायों का ऐसा ही हाल अन्य राज्यों में भी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुरुस्त कहा कि गौरक्षा के नाम पर 80 फीसदी लोग धंधा कर रहे हैं. गायों को मारने का मसला हो या सरकारी धन लेकर गायों को पालने का, गायों की रक्षा के नाम पर चमड़े का कारोबार करने वाले दलितों की बर्बर पिटाई का मसला हो या गोमांस के बहाने किसी अल्पसंख्यक की हत्या करने का, या गायों के पक्ष-विपक्ष को लेकर सियासत करने का मसला हो, सबके पीछे झांकें तो आपको धंधा ही दिखाई देगा.

गुजरात में कथित गौरक्षकों ने जिस तरह दलितों को सार्वजनिक और बर्बर तरीके से पीटा और जिस तरह राजस्थान में गायों की मौत की तस्वीरें सामने आईं, उसने देश के लोगों को दुख पहुंचाया और राजनीतिक दलों को राजनीति करने का मौका दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सार्वजनिक सभा में गौरक्षा के नाम पर धंधा करने वालों को धिक्कारा तो अन्य राजनीतिक दलों ने इसे नाकाफी बताया. मोदी ने कहा कि गाय के नाम पर धर्म नहीं, धंधा हो रहा है. कई लोगों ने गौरक्षा के नाम पर दुकानें खोल रखी हैं. ऐसे गौरक्षकों को देख कर बहुत गुस्सा आता है. मोदी ने यह भी कहा कि कुछ लोग जो पूरी रात असामाजिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, वे दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं. प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि ऐसे गौरक्षकों की डोजियर तैयार करें तो पाएंगे कि इनमें से 70 से 80 फीसदी अपराधी तत्व हैं. मोदी ने कहा कि अगर सचमुच में गौरक्षक हैं तो प्लास्टिक फेंकना बंद करवा दें.

गायों का प्लास्टिक खाना रुकवा दें तो यह सच्ची गोसेवा होगी. क्योंकि अधिकांश गायें कत्ल से नहीं बल्कि सबसे ज्यादा प्लास्टिक खाने की वजह से मरती हैं. मोदी का बयान आने के बाद गाय पर राजनीति और तेज हो गई. कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने मोदी पर कस कर निशाना साधा. विपक्ष ने आरोप लगाया कि दलित वोट पाने की मजबूरी में प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर बोलना पड़ा जबकि कार्रवाई कुछ नहीं हो रही. कांग्रेस के साथ सुर में सुर मिलाते हुए कई राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया कि मोदी सिर्फ बोलते हैं, कार्रवाई नहीं करते. जबकि गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में अधिक हो रही है. एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि अगर मोदीजी इस तरह का बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि गौरक्षा के नाम पर देश में गलत काम हो रहा है. अब उन्होंने बयान दिया है तो जिम्मेदारी भी उनकी ही बनती है. राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने अपने अंदाज में फेसबुक के जरिए कहा कि मोदी जी को मेरी दो दिन पहले कही हुई बात समझ में आ गई कि गाय दूध देती है, वोट नहीं. लालू ने कहा, 'और समझ भी क्यों न आए. गोमाता इनकी सरकार बनवाना तो दूर, बनी-बनाई सरकारों को हिला रही है'. बसपा नेता सुधींद्र भदौरिया ने कहा कि भाजपा की जमीन खिसक चुकी है और मोदी घबरा गए हैं. इतने सारे राज्यों में उनकी सरकारें हैं, उन राज्यों में क्या कार्रवाई हुई है? विपक्ष के हमलों पर भाजपा का कहना है कि प्रधानमंत्री को जो संदेश देना था उन्होंने दे दिया है. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने प्रधानमंत्री के बयान के प्रति अपना समर्थन जताया. संघ के सर सहकार्यवाह भैय्याजी जोशी ने कहा कि गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग कानून हाथ में लेकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं. ऐसे लोगों को बेनकाब किए जाने की जरूरत है. दलितों पर हुए हमलों के प्रति संघ ने सरकार को कठोरता से पेश आने के लिए कहा है. जेडीयू नेता शरद यादव ने भी प्रधानमंत्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों पर पाबंदी लगाई जाए. शरद यादव बोले कि प्रधानमंत्री ने ठीक कहा कि सरकार को गाय बचाने का आयोग चलाना चाहिए. पूरे देश में सड़कों पर गाय पॉलिथीन खा रही है और सबसे ज्यादा गाय की हत्या इस कारण से हो रही है तो गोरक्षक इसकी चिंता करें, जनता कानून को अपने हाथ में न ले.

गुजरात में दलितों की पिटाई का मसला सुर्खियों में ही था कि राजस्थान के हिंगोनिया स्थित सरकारी गौशाला में हजारों गायों के नारकीय हालात में मरने की खबर सामने आई. वहां ढाई साल में 27 हजार गायों की मौत हुई. अर्थात हर महीने 900 गायें मरीं. यानी, प्रतिदिन 30 गायों ने भूख, प्यास और बीमारी से दम तोड़ा. हिंगोनिया गौशाला में एक पखवाड़े में 500 से ज्यादा गायों की मौत की खबर फैलने के बाद पूरा सरकारी तंत्र गौशाला पर जमा हो गया. पूरी सरकार ने गहरे कीचड़ में धंसी पड़ी भूखी प्यासी गायें देखीं. राजस्थान के मुख्य सचिव को मौके पर बताया गया कि पांच दिन में ही वहां 200 गायों की मौत हुई है. गौशाला में 80 फीसदी बाड़ों की नालियां बंद पाई गईं. तकरीबन सारे बाड़ों में गोबर का अंबार लगा था. शहर से गौशाला पहुंचने वाली 90 प्रतिशत गायें मर गईं. गौशाला के आईसीयू में 23 और बाड़ों में 17 गायें मरी पाई गईं. गौशाला के 30 प्रतिशत कर्मचारी काम पर आते ही नहीं. गायों की मौत का यह कांड पूरा का पूरा भ्रष्टाचार जनित है. यह हाल भाजपा शासित सरकार है, जिसके नेता गौरक्षा के नाम पर बड़ी-बड़ी तकरीरें देते हैं और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने, बीफ के कारोबार पर रोक लगाने और गौमांस खाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की बातें करते रहते हैं. राजस्थान में भाजपा की सरकार है, लेकिन हिंगोनिया में गायों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है. गौभक्त होने का दावा करने वाली भाजपा सरकार ने गौ-संरक्षण के लिए विशेष कदम क्यों नहीं उठाया? हिंगोनिया कांड पर मुख्यमंत्री का कोई बयान भी नहीं आया. मामला अदालत तक जा पहुंचा और इस घटना को संज्ञान में लिया गया. अदालत ने भी सरकारी इंतजामात और कार्रवाई के बारे में पूछा. अदालत ने इस बात पर गहरी चिंता जाहिर की कि गोबर से बने दलदल में फंस कर सैकड़ों गायें मर गईं. अदालत के निर्देश पर प्रदेश के महाधिवक्ता ने गौशाला का निरीक्षण भी किया और वहां की बदतर स्थिति के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश की. महाधिवक्ता ने देखा कि बाड़ों में गोबर का नारकीय दलदल बना था, जिसमें गायें मरी पड़ी थीं और अनगिनत गायें मरणासन्न हालत में थीं. गोबर और गंदगी का साम्राज्य ऐसा था कि बुल्डोजरों से गायें खींची जा रही थीं. महाधिवक्ता ने मौके पर रजिस्टर की जांच की तो पता चला कि औसतन रोजाना 35 से 40 गायों की मौत हो रही है. अर्थात हर महीने 1200 गायें मर रही हैं.■

मोदी की फटकार राजनीतिक हथकंडा: आईपीएफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गौरक्षकों को फटकार केवल राजनीतिक हथकंडा है. यह कहना है ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता एसआर दारापुरी का. दारापुरी ने कहा कि देश में गौरक्षा समितियों का गठन भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में किया गया था और उन्हें पूरा सरकारी संरक्षण दिया गया था. वास्तव में भाजपा ने गौरक्षा को अपने विरोधियों को दबाने के लिए एक हथियार के रूप में अपनाया था. इसी लिए दो साल तक पूरे देश में गौरक्षकों की गुंडागर्दी निर्बाध चलती रही. इस पर न तो कोई प्रभावी कार्रवाई हुई और न भाजपा के किसी नेता ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की. गुजरात में गौरक्षकों द्वारा चार दलितों की निर्मम पिटाई के मामले को लेकर दलितों का एक बड़ा जनांदोलन उठ खड़ा हुआ है, इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है. निकट भविष्य में गुजरात, उत्तर प्रदेश और अन्य कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं जिनमें दलित प्रतिरोध का असर पड़ना ज़रूरी है. इसीलिए मोदी ने दलितों की नाराज़गी को कम करने के लिए गौरक्षकों को फटकार लगाई है. यह केवल एक राजनीतिक हथकंडा है.■

दलितों की पिटाई में कांग्रेस विधायक और सरपंच का हाथ!

गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई पर देश के सारे लोगों का ध्यान गया. वहां भाजपा की सरकार है, लिहाजा भाजपा अपने शासनिक दायित्वों से नहीं बच सकती. दलितों की पिटाई के मसले में जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं और जिस तरह अलग-अलग सियासी खेमों के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं या जिन फरार लोगों की खोज की जा रही है, वह इस घटना के पीछे राजनीतिक साजिशों की तरफ इशारा कर रही है. इस मामले में गिरफ्तार तकरीबन दो दर्जन लोगों से चौंकाने वाली जानकारियां मिल रही हैं. इस घटना में ऊना के कांग्रेसी विधायक वंश पंजाभाई भीमभाई और मोटा समढियाला गांव के सरपंच प्रफुल्ल कोराट का नाम सामने आ रहा है. फोन रिकॉर्ड खंगालने से पता चला है कि घटना के पहले कांग्रेस विधायक और सरपंच के बीच तीन सौ से अधिक बार बात हुई थी. घटना के बाद से सरपंच फरार है. विधायक और सरपंच के बीच काफी अच्छे संबंध बताए गए हैं. पता चला कि सरपंच प्रफुल्ल कोराट का स्थानीय दलित परिवार से काफी दिनों से झगड़ा चल रहा था. झगड़े के पीछे वह जमीन है जिसे खाली करने की धमकियां दी जा रही थीं. दलित परिवार उसी जमीन पर मरे हुए जानवरों की खाल उतारने का काम किया करता था. दलितों की पिटाई का वीडियो भी सरपंच के मोबाइल फोन से ही बनाया गया है. दलितों की पिटाई में इस्तेमाल में लाई गई गाड़ी दमन से ऊना आई थी. दमन से ऊना की दूरी छह सौ किलोमीटर से ज्यादा है. जांच हो रही है कि दलितों की पिटाई करने वाले गौरक्षक दमन से ऊना क्यों आए थे? दलितों की पिटाई के मामले में एक मुस्लिम युवक भी आरोपी है.■

feedback@chauthiduniya.com

पुलिसिया दमन के ख़िलाफ़ विपक्ष की गोलबंदी

हजारीबाग के बड़कागांव में एनटीपीसी की कर्णपुरा (पकरी-बरवाडीह) कोल परियोजना के तहत जबरन ज़मीन अधिग्रहण के विरोध में किसानों का संघर्ष जारी है. किसानों के विरोध को दबाने के लिए पुलिस दमन का रास्ता अख्तियार कर रही है.

कुमार कृष्णन

झारखंड में भाजपा-आजसू की गठबंधन सरकार जहां निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जगह-जगह रोड शो कर रही है, वहीं विपक्ष ने भूमि अधिग्रहण और जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा वाले दो कानूनों में किए गए बदलाव के खिलाफ विरोध तेज कर दिया है. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हाल में देश की राजधानी नई दिल्ली में रोड शो किया, जबकि पकरी-बरवाडीह कोयला खनन परियोजना के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरोध में अदालत में गिरफ्तारी देने के लिए विपक्षी पार्टियों के नेता हजारीबाग गए. विपक्षी नेताओं के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके जवाब में वे अदालत में गिरफ्तारी देने गए थे. हालांकि पुलिस ने इस आधार पर उन्हें गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया कि मामले की जांच चल रही है. अध्यादेश के जरिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी) और संथाल परगना काश्तकारी (एसपीटी) अधिनियम में बदलाव करने की सरकारी पहल का विरोध करने के लिए विपक्षी पार्टियां झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), झारखंड विकास मोर्चा-प्रजातांत्रिक (झाविमो-प्र) और कांग्रेस एकजुट हो गई हैं.

हजारीबाग के बड़कागांव में एनटीपीसी की कर्णपुरा (पकरी-बरवाडीह) कोल परियोजना के तहत जबरन ज़मीन अधिग्रहण के विरोध में किसानों का संघर्ष जारी है. किसानों के विरोध को दबाने के लिए पुलिस दमन का रास्ता अख्तियार कर रही है. पुलिस-प्रशासन द्वारा किये जा रहे दमन की जांच के लिए एआईपीएफ, विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की टीम घटनास्थल पर गई थी. इस टीम में फादर स्टेन स्वामी, अरविंद अविनाश, प्रशांत राही, अनिल अंशुमन व शिखा राही थे.

टीम ने हजारीबाग स्थित पकरी-बरवाडीह कोल परियोजना के मुख्य इलाके बड़कागांव प्रखंड में विभिन्न गांवों का दौरा किया. उन्होंने पुलिसिया दमन के शिकार ग्रामीणों से मिलकर घटना की विस्तृत जानकारी ली. साथ ही जबरन ज़मीन अधिग्रहण व विस्थापन के खिलाफ संघर्ष कर रहे किसानों व विभिन्न जन संगठनों के साथियों पर फ़र्ज़ी मुकदमों के संबंध में भी जानकारी ली.

जांच टीम ने बड़कागांव प्रखंड के सोनबरसा, सिंदुआरी, चुरचू तथा डाड़ीकला के ग्रामीणों तथा संघर्षरत जन संगठनों से जानकारी हासिल की. एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा ज़मीन अधिग्रहण के प्रयासों का क्षेत्र के किसानों ने लगातार विरोध किया है. इसके बावजूद कोयला खनन का ठेका 2 निजी कंपनियों को देकर चिरुडीह तिलैया टांड़ में काम शुरू करा दिया गया, तब आसपास के किसानों (रैयतों) ने भी 31 मार्च 2016 से खननस्थल के समीप शांतिपूर्ण ढंग से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया. 16 मई को जब खनन कंपनियों ने पोकलेन और बुलडोज़र लेकर खनन कार्य शुरू किया, तो विरोध करनेवाले रैयत-किसानों की संख्या भी बढ़ने लगी. 17 मई को जब सैकड़ों किसान धरने पर बैठे थे, तभी बड़कागांव थाना प्रभारी राम दयाल मुंडा वहां पहुंचे और किसानों से पूछा कि जब शांतिपूर्ण धरना दे रहे हो तो पास में ये लाठियां क्यों

रखे हो? यह सुनकर किसानों ने अपनी लाठियां हटा दीं. इसके बाद अचानक बिना किसी चेतावनी के पुलिसवालों ने किसानों पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसानी शुरू कर दी. इस लाठी चार्ज में सैकड़ों किसान घायल हुए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चिरुडीह तिलैया टांड़ में निहत्थे ग्रामीणों पर लाठी-चार्ज के बाद करीब 400 हथियारबंद पुलिसवालों ने आस-पास के गांवों पर हमला बोल दिया. बच्चे, बूढ़े, किशोर और महिला जो जहां मिला, उन्हें बुरी तरह से पीटा गया. दरवाजे तोड़कर पुलिसवाले घरों में घुसे. महिलाओं को गंदी-गंदी गालियां दीं और उनके साथ मार-पीट भी की. घर के सभी सामान तहस-नहस कर दिये गये. कई लोगों के सिर फूटे तो कइयों के हाथ-पांव तोड़ दिए गए, यहां तक कि गर्भवती महिला व नयी बहू को भी नहीं छोड़ा गया. जांच टीम को हर जगह पुलिस की दरिंदगी के प्रत्यक्ष प्रमाण मिले.

सोनबरसा गांव में छात्र मुकेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने हमारे साथ जैसा अत्याचार किया वैसा तो अंग्रेजों ने भी कभी नहीं किया होगा. बासो देवी ने क्षुब्ध स्वर में कहा कि कंपनी से मोटा पैसा लेकर पुलिस हमें मारने आई थी. मीना, चमेली देवी, दीपक साव, कौलेसर साव, दीपक साव व देव प्रसाद महतो समेत सबने एक स्वर में गहरे दर्द और क्षोभ के साथ पुलिसिया करतूत के बारे में जांच टीम को आपबीती सुनाई.

डाड़ीकला की सुकरी देवी, चाहो खातून, 70 वर्षीय रामेश्वर भुईया समेत वहां जुटे सभी महिला-पुरुषों ने बताया कि घटना के दिन जब टोले में लोग रसोई बना रहे थे, तभी सैकड़ों पुलिसवालों ने उनपर हमला बोल दिया. सिंदुआरी गांव की रेशमी महतो, यदुवीर साव व छात्रा संगीता और सभी ने पुलिसिया हमले की घटना बताई. चुरचू गांव के निवासियों ने कहा कि कई दिनों तक हमलोग डर से घर भी नहीं लौटे. कई रात गांव से बाहर इधर-उधर सोना पड़ा. पुलिसवाले हमें यह धमकी देकर गए थे कि जल्दी से इलाका खाली कर दो, नहीं तो फिर आकर ऐसे ही मारेंगे. गांव के लोगों का कहना है कि हमारी पुश्तैनी ज़मीन हमसे छीनी जा रही है. हमारे बाल-बच्चे कहां जाएंगे? हमलोगों के जीने-खाने का क्या होगा? सरकार हमारी ज़मीन लेना चाहती है तो पहले यहां आकर देखे कि ज़मीन बंजर है या उपजाऊ. यहां बहुत अच्छी फसल होती है. सब्जियां, धान, मक्का, गन्ना सब कुछ उगाते हैं और यहां का गुड़ तो दूर-दूर तक भेजा जाता है.

गौरतलब है कि बड़कागांव प्रखंड के डाड़ीकला, सोमवर्षा, सिंदवारी, दाड़ी, नगड़ी, इतीज, सिरया, चुरचू, उरूल समेत कई गांवों के करीब 150 पुरुष व महिलाएं तिलैयाटांड (चिरूडीह) में 54 दिनों से धरने पर बैठे हैं.

बड़कागांव प्रखंड के डाड़ीकला, सोमवर्षा, सिंदवारी, दाड़ी, नगड़ी, इतीज, सिरया, चुरचू, उरूल समेत कई गांवों के करीब 150 पुरुष व महिलाएं तिलैयाटांड (चिरूडीह) में 54 दिनों से धरने पर बैठे हैं. ग्रामीण सरकार द्वारा तय किए गए मुआवजे को कम बता रहे हैं. एमओयू के तहत बिजली उत्पादन के लिए हजारीबाग जिले के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के 37 गांवों की करीब 17 हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है.

ग्रामीण सरकार द्वारा तय किए गए मुआवजे को कम बता रहे हैं. एमओयू के तहत बिजली उत्पादन के लिए हजारीबाग जिले के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के 37 गांवों की करीब 17 हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है. अभी तक सभी प्रभावित किसान परिवारों को मुआवजा नहीं दिया गया है. इतना ही नहीं, जिन्हें मुआवजा मिला भी है, उसमें करीब 200 एकड़ जमीन के मुआवजे का भुगतान जमीन के वास्तविक मालिक को नहीं किया गया है. ऐसे कई फर्जी मामले अदालत में दायर किये गये हैं. बड़कागांव में अधिग्रहण से प्रभावित होनेवाले 36 गांवों में करीब 3000 परिवार रहते हैं. यहां की जमीन उपजाउ होने के कारण अधिकतर परिवारों का मुख्य पेशा खेती है. यहां किसान खेत से साल में तीन फसल लेते हैं.

85 बरस के सुगन साव कहते हैं कि हमलोग 12 साल से जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. हम कोयला खनन के विरोधी नहीं हैं, लेकिन इस परियोजना में हमारा घर, जमीन, खेत सबकुछ चला जा रहा है. वहीं सरकार हमारे 25 कट्ठा जमीन का मुआवजा मात्र 10 लाख रुपए दे रही है, जबकि दूसरी जगह जमीन की कीमत 20 लाख रुपया कट्ठा है. हमें यह मुआवजा मंजूर नहीं है. जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, हम विरोध करते रहेंगे. बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के 35 से ज्यादा गांवों के किसानों को बेघर होने की चिंता सता रही है. वे किसी भी कीमत पर आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. उनका कहना है कि हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं, कंपनी से है. 10 साल पहले 25 एकड़ जमीन के लिए 10 लाख रुपया मुआवजे की बात हुई थी. अब 20 लाख देना चाहते हैं. हम एक करोड़ रुपए मुआवजे और एक नौकरी की मांग कर रहे हैं. हमारे गांव के कुछ लोगों ने बेटी की शादी करने या बीमारी का इलाज करवाने के लिए मुआवजा ले लिया है. ये उनकी मजबूरी थी. लेकिन 75 प्रतिशत लोगों ने अपनी जमीन नहीं दी है. जिन्होंने अपनी जमीन दे भी दी है, वे अब दलाल की झूठी बातों में फंसकर अब पछता रहे हैं.

सीएनटी अधिनियम (1908) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की जमीन के हस्तांतरण पर रोक लगाता है. हालांकि एक जनजाति बिक्री, विनिमय, उपहार या इच्छापत्र के जरिए अपने थाना क्षेत्र के निवासी को अपनी जमीन हस्तांतरित कर सकता है. इसी तरह एसपीटी अधिनियम झारखंड की संथाल जनजातियों के भूमि अधिकार को संरक्षण देता है.

विपक्ष का आरोप है कि रघुवर दास एक गैर जनजातीय मुख्यमंत्री हैं. वे प्रतिबंधित जनजातीय इलाकों में अपने घनिष्ठ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इन दोनों कानूनों में बदलाव करना चाहते हैं, ताकि भूमि अधिग्रहण को आसान बनाया जा सके. इस मुद्दे पर राज्य विधानसभा की कार्यवाही पहले कई बार बाधित हो चुकी है. झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि इन दोनों कानूनों में बदलाव के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे गए अध्यादेश के खिलाफ उनकी पार्टी विश्व जनजातीय दिवस पर आंदोलन करेगी.

झामुमो के अध्यक्ष शिबू सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की और उनसे अध्यादेश राज्य को वापस लौटा देने की मांग की. बड़कागांव ब्लॉक में पकरी-बरवाडीह कोयला खंड 2010 में एनटीपीसी को आवंटित किया गया था, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों के विरोध के कारण काम शुरू नहीं हो सका. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई थीं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी.

अदालत में गिरफ्तारी देने के लिए हजारीबाग जाने वाले नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, जनता दल (यू) के प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा और कांग्रेस की स्थानीय विधायक निर्मला देवी शामिल थीं. प्रतिबंधित खनन क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश करने के आरोप में इन नेताओं और अन्य चार सौ लोगों के खिलाफ गत 24 जुलाई को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. ये नेता भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे ग्रमीणों से मिलने गए थे. मरांडी ने कहा कि साल 2004 से चल रही लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक हम जीत नहीं जाएंगे. पूर्व केंद्रीय मंत्री सहाय ने कहा कि 2004 से 2016 के बीच भूमि अधिग्रहण के लिए एक बार भी ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाई गई. एक बार उपायुक्त के चेंबर में बैठक हुई, जिसका पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने विरोध किया तो उनकी पिटाई की गई. विरोध-प्रदर्शन के कारण ही उनकी पत्नी एवं विधायक निर्मला देवी समेत अन्य पर कई केस दर्ज कर दिये गये हैं, जबकि योगेंद्र साव पर सीसीए लगाने के बाद उन्हें जिलाबदर कर दिया गया. उन्होंने कहा कि जबरन भूमि अधिग्रहण के कारण बड़कागांव ही नहीं बल्कि चांडिल एवं संथाल परगना के कई इलाकों में भी ग्रामीण संघर्षरत हैं. कांग्रेस विधायक दल के नेता आलम ने कहा कि पार्टी विस्थापितों के संघर्ष के साथ है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में ही वर्ष 2013 में नया भूमि अधिग्रहण कानून केंद्र में आया, लेकिन राज्य सरकार इसका भी पालन नहीं कर रही है. ■

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

सरकारी नीति पर प्रतिक्रिया देना आरबीआई गवर्नर का काम नहीं है

संसद का मानसून सत्र समाप्त हो गया. मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से संसद का यह सत्र पिछले सभी सत्रों के मुकाबले बेहतर था. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कोई हंगामा नहीं हुआ, कई विधायी कार्य भी संपन्न हुए. बेशक, इसमें जीएसटी सबसे महत्वपूर्ण बिल था, लेकिन दूसरे बिल भी बिना किसी हंगामे के पास हुए. ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है. जीएसटी लागू करने के हिसाब से एक मुश्किल बिल है क्योंकि इसकी सफलता अलग-अलग राज्यों व अलग-अलग फॉर्मूलेशन और टैक्स रेट पर निर्भर करती है. मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकारें इसे उचित तरीके से लागू करेंगी और केंद्र सरकार के साथ सहयोग करेंगी.

दूसरा मुद्दा कश्मीर का है. दुर्भाग्यवश, केंद्र सरकार की गलतियों के कारण एक बार फिर कश्मीर के साथ समस्या उत्पन्न हो गई है. संसद में गृह मंत्री ने कहा कि अब पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत होगी तो सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के मसले पर ही होगी. ऐसा कहना सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल ठीक है. संसद ने कई बार यह प्रस्ताव पास किया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. पाकिस्तान को पीओके पर अपना कब्जा खत्म करना चाहिए, लेकिन राजनैतिक रूप से यह रास्ता हमें किसी समाधान की तरफ नहीं ले जाता है. भाजपा के एक वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा कहते हैं कि पाकिस्तान के सामने बातचीत का प्रस्ताव नहीं रखना चाहिए क्योंकि वहां निर्णय लेने वाली कोई एक अथॉरिटी नहीं है. वहां सेना है, आईएसआई है, सिविलियन गवर्नमेंट है और धार्मिक नेता हैं, लिहाजा वहां से कुछ भी निकल कर नहीं आएगा. जब भी सरकार बातचीत करने की कोशिश करती है, पठानकोट जैसी कोई न कोई घटना सामने आ जाती है. यह कहना कि हम केवल पीओके पर बात करेंगे, इसका मतलब है कि हम आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान किसी भी हालत में पीओके पर बात करने के लिए तैयार नहीं होगा. असल मुद्दा यह है कि कश्मीर में शांति कैसे स्थापित की जाए? इसका जवाब इससे नहीं मिलेगा कि पाकिस्तान कश्मीर में अशांति फैला रहा है क्योंकि यहां आपके अपने लड़के, कश्मीरी नागरिक गुस्से में हैं. जबतक उनका गुस्सा शांत नहीं किया जाएगा, मैं नहीं समझता कि कश्मीर पर बेहतर तरीके से शासन किया जा सकता है.

रघुराम राजन के साथ समस्या ये रही कि वे मीडिया के साथ बहुत अधिक बातचीत करते थे. वे मीडिया गवर्नर बन गए थे, जो इस पद के लिए उचित नहीं था. अगर किसी को बयान देना हो तो वो बयान प्रधानमंत्री दे सकते हैं, वित्त मंत्री दे सकते हैं, ये राजनीतिक व्यक्ति हैं. यहां तक कि वित्त सचिव, सीबीडीटी के चेयरमैन भी कोई सार्वजनिक बयान नहीं देते क्योंकि ये नौकरशाह हैं. गवर्नर का पद इससे थोड़ा अलग है. गवर्नर साल में एक या दो बार प्रेस से बात कर सकते हैं, ब्याज दर की घोषणा करने के लिए वे मीडिया में आ सकते हैं, लेकिन सरकार की हर नीति पर प्रतिक्रिया देना गवर्नर पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है.

रघुराम राजन चार सितंबर को पदमुक्त हो रहे हैं. लोग यह जानना चाहेंगे कि उनका तीन साल का कार्यकाल कैसा रहा? रघुराम राजन भी अन्य आरबीआई गवर्नर की तरह ही थे. आरबीआई गवर्नर का काम सरकार की नीतियां बनाना नहीं होता है. इस पद को नियुक्ति के जरिए भरा जाता है न कि निर्वाचन के जरिए. इनकी नियुक्ति एक खास काम के लिए होती है, जिसमें मौद्रिक नीति, ब्याज दर, डॉलर और रुपए का समन्वय करना आदि शामिल है. मैं समझता हूं कि रघुराम राजन से पहले 22 गवर्नर हुए हैं और सबने अच्छा काम किया है. हो सकता है कि उनमें से एकाध ने अच्छा काम न भी किया हो. हर एक गवर्नर को अपना काम पता होता है. रिजर्व बैंक एक ऐसी संस्था है जिसके काम करने का तरीका फिक्स (तय) है. रघुराम राजन के साथ समस्या ये रही कि वे मीडिया के साथ बहुत अधिक बातचीत करते थे. वे मीडिया गवर्नर बन गए थे, जो इस पद के लिए उचित नहीं था. अगर किसी को बयान देना हो तो वो बयान प्रधानमंत्री दे सकते हैं, वित्त मंत्री दे सकते हैं, ये राजनीतिक व्यक्ति हैं. यहां तक कि वित्त सचिव, सीबीडीटी के चेयरमैन भी कोई सार्वजनिक बयान नहीं देते क्योंकि ये नौकरशाह हैं. गवर्नर का पद इससे थोड़ा अलग है. गवर्नर साल में एक या दो बार प्रेस से बात कर सकते हैं, ब्याज दर की घोषणा करने के लिए वे मीडिया में आ सकते हैं, लेकिन सरकार की हर नीति पर प्रतिक्रिया देना गवर्नर पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है. मैं आशा करता हूं कि नए गवर्नर इस बात को समझेंगे और आरबीआई की वर्षों पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे. गवर्नर को राजनीति करने के लालच से परहेज करना चाहिए. अगर राजनीति करनी है तो पहले इस्तीफा दें और तब राजनीति में उतर जाएं. बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां से लोगों ने इस्तीफा दिया और फिर राजनीति में शामिल हुए. गवर्नर जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसे मामलों में सावधान रहना चाहिए. अगर बोलने से विवाद पैदा होता है तो खामोश रहना ही ज्यादा सही है. हाल में रघुराम राजन ने एक बयान दिया कि वे अपने सेवा विस्तार के लिए तैयार थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उनकी आलोचना की. इस आलोचना को उन्होंने खुद ही आमंत्रित किया था. अब उन्हें दोबारा नियुक्त किया जाता या नहीं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है. लेकिन रघुराम राजन ने अपने बयानों के जरिए कोई विश्वास नहीं जगाया. मैं आशा करता हूं कि इस पद के लिए सरकार की नई पसंद ज्यादा शालीन और बेहतर होगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

संसद में गृह मंत्री ने कहा कि अब पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत होगी तो सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के मसले पर ही होगी. ऐसा कहना सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल ठीक है. संसद ने कई बार यह प्रस्ताव पास किया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. पाकिस्तान को पीओके पर अपना कब्जा खत्म करना चाहिए, लेकिन राजनैतिक रूप से यह रास्ता हमें किसी समाधान की तरफ नहीं ले जाता है. भाजपा के एक वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा कहते हैं कि पाकिस्तान के सामने बातचीत का प्रस्ताव नहीं रखना चाहिए क्योंकि वहां निर्णय लेने वाली कोई एक अथॉरिटी नहीं है. वहां सेना है, आईएसआई है, सिविलियन गवर्नमेंट है और धार्मिक नेता हैं, लिहाजा वहां से कुछ भी निकल कर नहीं आएगा.

पाठकों की दुनिया

मासूमों का क्या कसूर है?

चौथी दुनिया साप्ताहिक समाचार पत्र में कश्मीर की समस्या पर कवर स्टोरी बैलेट बड़ा या पैलेट(08 अगस्त- 14 अगस्त 2016) पढ़ा. हारुन रेशी और डॉ. फरहा युसुफ द्वारा कश्मीर पर लिखी कवर स्टोरी पढ़ने के बाद कश्मीर की सच्चाई का पता चलता है. इस लेख में ऐसी कई बातें लिखी हैं, जिसे देश की मीडिया ने न कभी दिखाया और न कभी बताया. कश्मीर की समस्या का सबसे बुरा परिणाम वहां की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है. सुरक्षा बलों की फायरिंग, पैलेट गन के इस्तेमाल और पत्थरबाजी से जो लोग जख्मी हुए हैं उनमें अधिकतर कश्मीर की आम जनता है. पैलेट गन से घायल हुए लोगों में कई ऐसे हैं, जिनकी आंखें चली गई हैं. पैलेट गन से छोटे-छोटे बच्चे घायल हुए हैं. भला इन बच्चों की क्या गलती थी? एक तरफ देश के गृहमंत्री कहते हैं कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं होगा, तो वहीं सीआरपीएफ के डीजी कहते हैं कि पैलेट गन का इस्तेमाल जारी रहेगा. सेना, सरकार व अलगाववादियों से कश्मीर की आम जनता सवाल कर रही है कि पैलेट गन से घायल और आंखें खोने वाले मासूमों का क्या कसूर है?

–देवाशीष दासगुप्ता, *यमुना विहार, दिल्ली.*

सरकार की कमजोर विदेश नीति

बंदूक और बात साथ नहीं चल सकती (08 अगस्त- 14 अगस्त 2016) शीर्षक से लिखे अपने लेख में लेखक कमल मोरारका ने तीन खबरों की चर्चा की है. भगवंत मान द्वारा संसद का वीडियो बनाया जाना सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर मामला था और इसे लेकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाकर इसे पेचीदा बना दिया गया है. लोकसभा अध्यक्ष के पास अधिकार हैं और वे अपने अधिकार का इस्तेमाल कर मान को चेतावनी देकर मामला खत्म कर सकती थीं. दूसरी बात भाजपा और शिवसेना का गठबंधन अच्छी स्थिति में नहीं है. शिवसेना गठबंधन में होते हुए भी बार-बार प्रधानमंत्री और भाजपा दोनों पर हमला करती है. दोनों पार्टियों के बीच यह गतिरोध बाला साहब ठाकरे की मृत्यु के बाद से ही देखने को मिल रहा है. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी दोनों पार्टियों ने अलग लड़ा था. यह बिलकुल सही है कि मोदी सरकार नेपाल के साथ संबंधों को संभाल नहीं पा रही है. यह एक कमजोर विदेश नीति का परिणाम है. पाकिस्तान के साथ सरकार को बातचीत बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते. भाजपा विपक्ष में थी, तो वह बार-बार इस बात को दोहराती थी. प्रधानमंत्री भी इस बात को कह चुके हैं कि धमाकों के बीच आवाज सुनाई नहीं देती.

–अमित सिंह, *लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

कश्मीरियों को समझने की जरूरत है

जब तोप मुकाबिल हो-हमें कश्मीरियों की बात ध्यान से सुननी चाहिए (08 अगस्त- 14 अगस्त 2016) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. संतोष भारतीय ने अपने संपादकीय में बिलकुल सही कहा है कि कश्मीर में आज हुर्रियत भी बेबस है, सरकार भी बेबस है. वहां के आम आदमी भी बेबस हैं. बस, अगर कोई खुश है, तो वो लोग जो कश्मीर के इस असंतोष में अपनी राजनीति को सफल होता हुआ देख रहे हैं या फिर वो ताक़तें जो कश्मीर की इस स्थिति से सारी दुनिया से पैसा कमाने का एक ज़बरदस्त मौक़ा हासिल कर चुकी है. कश्मीर में लगभग एक महीने से अधिक समय से कर्फ्यू लगा हुआ है जिससे वहां की जनता को आम जरूरतों के सामान नहीं मिल पा रहे हैं. खाने-पीने की चीजें नहीं मिल रही हैं, लेकिन उनकी परेशानी को अनदेखा कर राजनीतिक पार्टियां अपना हित साध रही हैं. वहां की समस्या को समझने की जरूरत है. बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर में बवाल मच गया और उसके जनाजे में पांच लाख लोगों के शामिल होने की बात कही गई. पाकिस्तान और आतंकी हाफिज सईद ने भी कश्मीर को लेकर बयानबाजी शुरू कर दी. सभी राजनीतिक दलों को वहां के निवासियों की समस्याओं को समझना चाहिए और उनका हल निकालना चाहिए जिससे कश्मीरियों में सरकार के प्रति विश्वास बहाल किया जा सके.

–आदिल खान, *अलीगढ़, उत्तर प्रदेश.*

भाजपा आत्मचिंतन करे

आलेख-भाजपा के सेल्फ गोल(08 अगस्त- 14 अगस्त 2016) पढ़ा. काफी विचारोत्तजेक लेख है. मेघनाद देसाई से मैं सहमत हूं कि कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व को लेकर समस्या हो सकती है (भले ही इसके नेता संसद में ऊंघ रहे हों), लेकिन पार्टी में कुछ बहुत ही चतुर नेता हैं जो समझते हैं कि राजनीति में चीजें कैसे काम करती हैं. उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश दोनों जगहों पर मोदी सरकार ने जल्दबाजी में राष्ट्रपति शासन लगाया जिसकी वजह से उसे दोनों जगहों पर मुंह की खानी पड़ी. उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस वापस सत्ता पर काबिज हो गई. कांग्रेस ने अरुणाचल में मुख्यमंत्री बदलकर भाजपा को मात दी और वह देखती रह गई. यह सही है कि केंद्र सरकार को दोनों जगहों पर वहां की सरकारों को बहुमत साबित करने का मौका देना चाहिए था. सरकार और भाजपा को आत्मचिंतन और अपनी की हुई गलतियों से सबक लेने की जरूरत है.

–राजेश यादव, *पटना, बिहार.*

देशहित में अपनी जिम्मेदारी निभाएं

चौथी दुनिया समाचार पत्र अंक (25 जुलाई-31 जुलाई 2016) में 'नीयत सही, नीति बदले' के जरिए कमल मोरारका ने बहुत बेहतर ढंग से अपनी बात राष्ट्रहित में सकारात्मक ढंग से प्रस्तुत किया. इस आलेख में नकारात्मक पहलू को भी ईमानदारी से कहा गया है. कहते हैं जो वातावरण हम बनाते हैं, उसी के आधार पर नई पीढ़ी का चरित्र बनता है. उन्हें जिम्मेदार बनाना है, तो खुद जिम्मेदार बनना ही होगा. सरकार की मंशा स्पष्ट है कि राष्ट्र का विकास हो, किसानों की आय छह वर्ष में दोगुनी हो और भी कई बेहतर कार्य हों. यह देश के लिए शुभ संकेत है. सरकार के कुछ सांसद अपने अव्यवहारिक बयानबाजी बंद करें और देशहित में अपनी जिम्मेदारी निभाएं. जनता ने बेतुकी बयानबाजी के लिए नहीं चुना है. यह बात अक्षरत: स्पष्ट है कि हमारे राष्ट्र को अगर तरक्की की राह पर ले जाना है, तो अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता जिसे लोग आंकड़ा डूबे हैं उसे दूर करना होगा. भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए नई नीति बनानी होगी. चारों तरफ अनुशासन कैसे दिखे उस पर कार्य करना है. विगत दो वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छी पहल की है, पारदर्शिता के साथ बेहतर कार्य किया है, लेकिन इस मानसिकता को नहीं बदल पाए हैं जिसमें हर व्यक्ति पैसा चाहता है. व्यवस्था में बैठे लोग जानते हैं कि सरकार बदलती रहती है, ऐसे ही कानून नियम बनते हैं और हमें अपने ढंग से चलना है. कोई भी सरकार कानून के जरिए लोगों को नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ा सकती है. लोगों को विश्वास के साथ शासन ही सुशासन है.

–अशोक निर्मोही(मुन्ना जी), *दरभंगा, बिहार.*

स्वच्छता अभियान की सच्चाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वच्छता अभियान की शुरुआत किए दो साल होने को हैं. प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी. दो साल बीत जाने के बाद भी स्वच्छता अभियान का असर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है. इस अभियान की शुरुआत में नेताओं ने झाड़ू लगाकर खूब फोटो खिंचाए, लेकिन इसपर अमल किसी ने नहीं किया. आज भी हमें सड़क, ट्रेन और स्टेशन पर चारों तरफ गंदगी दिखाई पड़ती है. स्वच्छता अभियान का कोई असर यहां नहीं दिखता है. जैसे यहां की दो साल पहले स्थितियां थीं, वैसी आज भी हैं. दरअसल होता ये है कि सरकार किसी भी योजना की शुरुआत तो कर देती है, लेकिन उसके अमल पर ध्यान नहीं देती. स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों और अन्य स्थानों पर बिलकुल स्वच्छता अभियान का ध्यान नहीं रखा जा रहा है. बात अगर सड़क किनारे कूड़ेदानों की करें तो इनकी जीर्ण-शीर्ण हालत पूरे शहर की गंदगी की दास्तां बयां कर देती है. लोगों को जागरूक करने के लिए शहरों, गावों और कस्बों में अभियान चलाया जाता है, लेकिन समाज के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है. स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है. इसलिए हम सबको स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और गंदगी फैलाने से बचना चाहिए.

–हितेश शेखर, *ग्वालियर, मध्य प्रदेश.*

पाठकों से...

सुधी पाठक, चौथी दुनिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स-आलेखों पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं. आप अपनी बेबाक राय, सुझाव हमें डाक/ईमेल द्वारा भेज सकते हैं. आप हमारी आंख-कान-नाक हैं. जहां तक आपकी पहुंच है, वहां तक हमारी नज़र जाना संभव नहीं है. अख़बार को बेहतर बनाने में आपके सुझाव-विचार हमारी मदद करेंगे. हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11,
गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)-201301, उत्तर प्रदेश.
Email: feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

घृणा की प्रयोगशाला

उत्तर प्रदेश का चुनाव भविष्य में किस तरह की प्रयोगशाला बनेगा, इसे लेकर चिंता हो रही है. उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी का शासन है. माना जाता है कि मुलायम सिंह यादव बुनियादी तौर पर डॉ. लोहिया के आदर्शों में विश्वास करते हैं. वहां की दूसरी बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती, डॉ. अम्बेडकर के सिद्धांतों में विश्वास रखती हैं. उन दोनों के विचारों में बुनियादी तौर पर कोई मतभेद नहीं है, पर मतभेद इतना है कि दोनों एक दूसरे को औपचारिक तौर पर नमस्कार भी नहीं करते और आंखें भी नहीं मिलाते.

चिंता यह नहीं है कि मुलायम सिंह यादव और मायावती एक दूसरे की तरफ देखते नहीं हैं. चिंता यह है कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक शक्तियां जिस तरह की तैयारी कर रही हैं, उसकी इन्हें जरा भी चिंता नहीं है. एक तरफ कांवड़ के कपड़े पहने हुए लोग और उनके हाथ में भारत का राष्ट्रीय ध्वज. मानो भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक खास तरह की धार्मिक विचारधारा का प्रतीक बन गया है. हर राजनीतिक दल फरवरी 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा है, लेकिन कुछ ताकतें बिना किसी राजनीतिक विचारधारा के समूचे प्रदेश में भावनात्मक ध्रुवीकरण करना चाहती हैं. ये ध्रुवीकरण विकास के लिए नहीं है, ये ध्रुवीकरण गरीबी से लड़ने के लिए नहीं है, ये ध्रुवीकरण महंगाई का विरोध नहीं करता, ये ध्रुवीकरण भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग भी नहीं करता. ये ध्रुवीकरण दिमागों को प्रदूषित कर सत्ता पर कब्जा करने का सबसे आसान रास्ता तलाश रहा है. अगर दिमाग में ये भर जाए कि पिछले विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव की जीत इसलिए हुई थी, क्योंकि उन्हें बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों का वोट मिला था और उस अल्पसंख्यक समर्थन के मुकाबले बहुसंख्यक जनता को संगठित कर ध्रुवीकृत कर दिया जाए तो जीता जा सकता है. ये कैसा खतरनाक खेल है, जिसकी मंजिल वोट लेकर सत्ता पाने से ज्यादा उन लोगों के चेहरे को बर्बाद करना है, उनकी रोशनी समाप्त करना है जो उनसे विचारधारात्मक रूप से मेल नहीं खाते.

इन शक्तियों ने देश के तमाम प्रतीकों को साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण से जोड़ने की कोशिश की है. पटेल इसके पहले उदाहरण हैं, गांधी इसके दूसरे उदाहरण हैं, सुभाष चंद्र बोस इसके तीसरे उदाहरण हैं. मानो ये तीनों लोग इस देश में भाईचारा, एकता, साम्प्रदायिक सौहार्द चाहते ही नहीं थे और राष्ट्रीय झंडा, जो हमारे देश और संविधान का प्रतिनिधित्व करता है, अब धार्मिक उन्माद फैलाने वाली शक्तियों के हाथ में पहुंच गया है.

ये कोशिशें उत्तर प्रदेश को एक ऐसी प्रयोगशाला के रूप में तब्दील करने जा रही हैं, जहां रोटी, कपड़ा, बेहतर जिंदगी और समाज में बराबरी की कोई जगह नहीं होगी. ये लोग धर्म के सनातनी व मानवीय स्वरूप की जगह धर्म का एक ऐसा स्वरूप निर्मित करेंगे जिसमें घृणा, प्रतिशोध, जलन और ईर्ष्या दिखाई देगी. उत्तर प्रदेश में ये कोशिशें तेजी से शुरू हो चुकी हैं.

उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता की भट्ठी बनने से रोकने में मीडिया कोई भूमिका नहीं निभाएगा. शायद राजनैतिक दल भी अपनी कोई भूमिका न निभाएं और उससे लाभ उठाने की कोशिश करें. नेता और पत्रकार वो होता है जो आने वाले वक्त में घटने वाली संवेदनशील और निराशाजनक घटनाओं के संकेतों को समझ सके. अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश में या तो ऐसे पत्रकार चुप हैं, राजनेता भी चुप हैं, जो इस आहट के संकेतों को पहचान सकें.

ये कोशिशें सरकार के मुखिया अखिलेश यादव को नहीं दिखाई देती हैं. ये कोशिशें समाजवादी विचारधारा के मुखिया मुलायम सिंह यादव को भी नहीं दिखाई देती हैं. ये कोशिशें अंबेडकरवादी परिवर्तनकारी ताकतों की नेता मायावती को भी दिखाई नहीं देती हैं. कांग्रेस के देखने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि उसने अपना चश्मा ही अलग कर लिया है. अगर किसी को ये नहीं दिखाई देती हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश में क्या होगा? शायद वो होगा जिसकी कल्पना आज हम नहीं कर सकते और जब हो जाएगा तब सिवाय सिर पीटने के और कुछ रह नहीं जाएगा. ये कोशिश करने वाले नहीं जानते कि जहां वे आग लगाना चाहते हैं, वहां उनका भी घर है. वो जिस घर को जलाना चाहते हैं, भूल जाते हैं कि उस घर से उनके घर की दीवार भी सटी हुई है. शायद वो स्वार्थ में इतने ज्यादा लिप्त हो चुके हैं कि वे ये नहीं देख पा रहे हैं कि इससे देश को कितना नुकसान होने वाला है?

उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता की भट्ठी बनने से रोकने में मीडिया कोई भूमिका नहीं निभाएगा. शायद राजनैतिक दल भी अपनी कोई भूमिका न निभाएं और उससे लाभ उठाने की कोशिश करें. नेता और पत्रकार वो होता है जो आने वाले वक्त में घटने वाली संवेदनशील और निराशाजनक घटनाओं के संकेतों को समझ सके. अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश में या तो ऐसे पत्रकार चुप हैं, राजनेता भी चुप हैं, जो इस आहट के संकेतों को पहचान सकें. इस संकेत की भाषा को न समझना उत्तर प्रदेश का आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य है. ■

editor@chauthiduniya.com

अब काम पर लग जाने का समय है

मेघनाद देसाई

राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित बुलेट ट्रेन स्वयं प्रधानमंत्री और उनके सूट-बूट वाले दोस्तों के लिए चलेगी. मेरे पास राहुल गांधी के लिए एक सरप्राइज है. मैंने अभी-अभी शंघाई से बीजिंग तक की यात्रा बुलेट ट्रेन से की है. यह ट्रेन साधारण चीनी परिवार, जिसमें बूढ़े और बच्चे शामिल थे, से भरी पड़ी थी. वहां बुलेट ट्रेनों के लिए एक स्टेशन बना है, जहां से वे चीन में संचालित होती हैं. दरअसल, चीन में रेल से यात्रा करने वाले आधे यात्री बुलेट ट्रेन से ही सफ़र करते हैं.

बुलेट ट्रेन पर राहुल गांधी की टिप्पणी कांग्रेस और आम तौर पर भारत में विकास को लेकर व्याप्त सोच को ही रेखांकित करती है. यह मान लिया जाता है कि कोई भी नई व आधुनिक चीज़ केवल अमीरों को ही फ़ायदा पहुंचाती है.

आख़िरकार जीएसटी को हमने क़ानूनी रूप दे दिया है. 15 साल के निरर्थक बहस के बाद इसे अब जाकर क़ानूनी रूप दिया गया है. अब क्या यह माना जा सकता है कि यह क़ानून मोदी सरकार की विकास यात्रा को नई ऊर्जा प्रदान करेगा? या फिर, जीएसटी के पारित हो जाने के बाद क्या बाक़ी राजनीतिक दलों को यह चक्रीन हो जाएगा कि तीव्र गति से विकास ही लाभकर रणनीति है और यही एकमात्र रास्ता है जो देश को एक सम्मानपूर्ण आय की तरफ ले जाएगा?

इन नई चीज़ों में वे सभी सुधार भी शामिल हैं जो व्यापार को आसान और अधिक लाभदायक बनाने के लिए किए जाते हैं. राजनेताओं में यह आम धारणा है कि कम समृद्ध लोगों के हितों की रक्षा के लिए विकास की रफ्तार को रोका जा सकता है. उत्पादकता में वृद्धि या किसी विलय (जैसे एसबीआई के मामले में) से मजदूरों की नौकरी चली जायेगी. लिहाज़ा तत्काल कार्यरत मजदूरों की रक्षा के लिए विकास को रोक दिया जाए.

भारत ने विकास के बजाय आत्मनिर्भरता हासिल करने, आयात पर भरोसा करने और समाजवाद के संभ्रांत संस्करण को स्थापित करने में तीस साल बर्बाद कर दिए. चीन ने भी 1949 के बाद अपने 30 साल माओ की विकास नीति की कपोल कल्पना में बर्बाद कर दिए थे. सत्तर के दशक के आखिर तक भारत और चीन में प्रति व्यक्ति आय बराबर थी.

सौभाग्य से चीन में डेंग जियाओपिंग ने तीव्र आर्थिक विकास की परिवर्तनकारी भूमिका को पहचाना और बिना किसी दुविधा के उसे अपनाया. इसका नतीजा यह हुआ कि चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन गया जो तीन दशकों तक निरंतर उच्च विकास दर हासिल करता रहा. वर्ष 2008 में चीन ने ओलंपिक खेलों का आयोजन कर और देश में बुलेट ट्रेन चला कर अपनी उपलब्धियों को दिखा दिया. बुलेट ट्रेनों की वजह से इस विशाल देश में यात्रा करना आसान हो गया.

भारत ने अस्सी के दशक को संरचनात्मक सुधार के बजाय आयात के उदारीकरण में बर्बाद कर दिया. अत्यधिक उधार के कारण 1991 में देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी. लेकिन नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के कठोर सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था को बचा लिया था. लेकिन उन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अपनी गति खो दी. नतीजा यह हुआ कि सुधारों की प्रक्रिया थम गई या फिर अनमने ढंग से आगे बढ़ती रही. श्रम कानूनों में कोई सुधार नहीं हुआ, मेन्युफैक्चरिंग को जीवंत रखने और किसानों को उनके खेत के अलावा अलग से स्थाई रोज़गार देने का कोई प्रयास नहीं किया गया. यूपीए-2 कार्यकाल के दौरान सुधारों को आगे बढ़ाने के बजाय पर्यावरण संबंधी प्रावधान लाकर विकास का गला ही घोंट दिया गया. सिंगूर प्रकरण, जिसने मेन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नुकसान पहुंचाया था, को वर्ष 2013 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के रूप में नीतिगत रूप दे दिया गया.

अब, आखिरकार जीएसटी को हमने क़ानूनी रूप दे दिया है. 15 साल के निरर्थक बहस के बाद इसे अब जाकर क़ानूनी रूप दिया गया है. अब क्या यह माना जा सकता है कि यह क़ानून मोदी सरकार की विकास यात्रा को नई ऊर्जा प्रदान करेगा? या फिर, जीएसटी के पारित हो जाने के बाद क्या बाक़ी राजनीतिक दलों को यह यक़ीन हो जाएगा कि तीव्र गति से विकास ही लाभकर रणनीति है और यही एकमात्र रास्ता है जो देश को एक सम्मानपूर्ण आय की तरफ ले जाएगा?

समस्या यह है कि राजनेता विकास में विश्वास नहीं रखते हैं. वे कम विकास दर चाहते हैं, ताकि उन्हें लोगों को आरक्षण और सब्सिडी देने का मौक़ा मिलता रहे. यह काम यूपीए-2 सरकार ने बहुत कारगर ढंग से किया. भाजपा/एनडीए सरकार में भी लोगों को गरीबी उन्मूलन के बजाय गौ रक्षा पर बहस करने में अधिक दिलचस्पी है.

अभी बहुत कुछ किया जाना बाक़ी है. गंगा की सफाई की जानी है. स्वच्छ भारत से स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाना है. रेलवे का कायाकल्प करना है, ताकि गरीब लोग भी इसमें आराम से यात्रा कर सकें. अब काम पर लग जाने का समय आ गया है. ■

शराबबंदी के नाम पर सताए जा रहे हैं दलित : सुशील मोदी

दलितों के नाम पर हो रही राजनीति से दुखी सुशील मोदी कहते हैं कि नीतीश कुमार को गुजरात की चिंता छोड़कर पहले बिहार के दलितों की चिंता करनी चाहिए. राजधानी पटना से सौ किमी की दूरी पर मुजफ्फरपुर के पारू में दो दलित युवकों के साथ मारपीट और उनके मुंह में पेशाब करने की शर्मनाक घटना घटी. महागठबंधन के नेता लालू प्रसाद यादव के 15 साल के राज में एक दो नहीं सैंकड़ों दलितों का सामूहिक नरसंहार हुआ, तो नीतीश कुमार के राज में सभी नरसंहारों के आरोपी साक्ष्य के अभाव में एक-एक कर हाईकोर्ट से बरी हो गए. अरवल के लक्ष्मणपुर बाथे में 58 दलित, भोजपुर के बथानी टोला में 21 और औरंगाबाद के मियांपुर में 34 दलित मारे गए थे.

सरोज सिंह

बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी का मानना है कि शराबबंदी के नाम पर सरकार वास्तविक अपराधियों को पकड़ने के बजाय दलितों और गरीबों को तंग कर रही है. शराबबंदी की आड़ में दलितों व महादलितों के छह गांवों पर सामूहिक जुर्माना लगाकर सरकार ने ब्रिटिश काल की याद को ताजा कर दिया है. सुशील मोदी कहते हैं कि हम सभी शराबबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन शराबबंदी के नाम पर पुलिस को असीमित अधिकार देने, अंग्रेजों की तरह गांव पर सामूहिक जुर्माना लगाने, हत्या और बलात्कार से भी कठोर शराबबंदी कानून लागू करने की वजह से बिहार की जगहंसाई हो रही है. नीतीश कुमार अगर सच में शराबबंदी को लेकर गंभीर हैं तो उन्हें जमीनी सच्चाई को ध्यान में रखते हुए कदम बढ़ाना चाहिए.

उनका कहना है कि आतंकवाद को लेकर नीतीश कुमार का ढीला रवैया हमें परेशान कर रहा है. पटना की सड़क पर पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी और जाकिर नाइक के महिमामंडन ने फिर साबित किया है कि नीतीश सरकार न केवल आतंकवादियों के प्रति नरमी बरत रही है, बल्कि उनका दुस्साहस बढ़ा रही है. पटना के जिस जुलूस में जाकिर नाइक और आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे, वह पुलिस की मौजूदगी में निकला था. पुलिस देशविरोधी नारेबाजी से तब तक इंकार करती रही, जबतक नारे लगाने लोगों का 14 सेकेंड का वीडियो वायरल नहीं हो गया. नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि भड़काऊ भाषणों की वजह से जिस जाकिर नाइक को बांग्लादेश, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा ने प्रतिबंधित कर दिया है, उसके समर्थन में पटना में जुलूस कैसे निकला? बिहार के लोग भूले नहीं हैं कि तीन साल पहले कैसे नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर आतंकी मॉड्यूल के ठिकाने बन गए थे.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर में नल का वादा किया है इसे वह कैसे पूरा करेंगे? इस पर सुशील मोदी कहते हैं, मुख्यमंत्री ने ही स्वीकार किया है कि तमाम प्रयासों के बावजूद अभी राज्य के मात्र 5 हजार बसावटों में ही पाइप से पानी पहुंचाया जा सका है. अगर जलापूर्ति की सारी योजनाएं पूरी कर ली जाएं तो भी 22 प्रतिशत से ज्यादा घरों में नल से पानी नहीं पहुंच पाएगा. ऐसे में मुख्यमंत्री बताएं कि उनकी सरकार अगले चार साल में सूबे के एक लाख से ज्यादा बसावटों में पाइप से जलापूर्ति कैसे कर पाएगी? नीतीश कुमार की सरकार पिछले चार साल में तय लक्ष्य का 80 हजार चापाकल नहीं लगा सकी. 2015-16 में अनुसंशित 55,228 चापाकलों में से मात्र 2,572 ही लगा पाई. दूसरी ओर दावा किया कि ग्रामीण जलापूर्ति के नाम पर शुरू की गई पाइप जलापूर्ति योजना, मिनी पाइप जलापूर्ति योजना तथा सौर चालित पम्प आदि योजनाओं में से 90 प्रतिशत या तो आधी-अधूरी हैं या अधिकांश बंद पड़ी हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री शहरी और ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में विधायकों की भूमिका को पूरी तरह से खत्म करने की निन्दा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री चापाकल योजना में विधायकों की अनुशंसा पर ही चापाकल लगाए जाते थे. 11 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अब नीतीश कुमार को लग रहा है कि गांवों में पाइप से जलापूर्ति के लिए जलमीनारों की कोई उपयोगिता नहीं है, जबकि जलापूर्ति योजना की 40 प्रतिशत राशि जलमीनारों के निर्माण पर ही खर्च हुई है. मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि जो जलमीनारें बन चुकी हैं, उनका क्या होगा?

दलितों के नाम पर हो रही राजनीति से दुखी सुशील मोदी कहते हैं कि नीतीश कुमार को गुजरात की चिंता छोड़कर पहले बिहार के दलितों की चिंता करनी चाहिए. राजधानी पटना से सौ किमी की दूरी पर मुजफ्फरपुर के पारू में दो दलित युवकों के साथ मारपीट और उनके मुंह में पेशाब करने की शर्मनाक घटना घटी. महागठबंधन के नेता लालू प्रसाद यादव के 15 साल के राज में एक दो नहीं सैंकड़ों दलितों का सामूहिक नरसंहार हुआ, तो नीतीश कुमार के राज में सभी नरसंहारों के आरोपी साक्ष्य के अभाव में एक-एक कर हाईकोर्ट से बरी हो गए.

अरवल के लक्ष्मणपुर बाथे में 58 दलित, भोजपुर के बथानी टोला में 21 और औरंगाबाद के मियांपुर में 34 दलित मारे गए थे. इन सभी नरसंहारों के नामजद अभियुक्त जिन्हें निचली अदालत से सजा मिली थी, नीतीश कुमार के राज में साक्ष्य के अभाव में रिहा हो गए. बड़े भाई ने पिछड़ों व दलितों को आरक्षण से वंचित कर पंचायत चुनाव करा लिया था.

बड़े और छोटे भाई हमेशा दलितों को अपमानित करते रहे हैं. महादलित जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से अपमानित कर हटाने वाले नीतीश कुमार की सरकार में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से वंचित हजारों दलित छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ने के लिए बाध्य हो रहे हैं. वहीं, सरकार द्वारा प्रोन्नति में आरक्षण के मामले को कोर्ट में मजबूती से नहीं लड़े जाने की वजह से हजारों दलित और आदिवासी प्रोन्नति से वंचित हैं. ऐसे में क्या इन बड़े और छोटे भाइयों को दलितों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने का कोई हक है? सुशील मोदी कहते हैं कि गुजरात में दलित उत्पीड़न की एक घटना पर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने जोर-जोर से छाती पीटना शुरू कर दिया ताकि बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित युवकों की पिटाई, बुजुर्ग दलित दम्पती की हत्या, दरभंगा-किशनगंज में महिलाओं का उत्पीड़न और भभुआ में दलित छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद उसकी नृशंस हत्या की लगातार हुई पांच घटनाओं की ओर देश-दुनिया का ध्यान ही न जाए. यह ऐसा ही कृत्य है जैसे घर के भीतर अपराध के समय टीवी की आवाज कुछ ज्यादा ही तेज कर दी जाती है. लालू प्रसाद जिस दिन दलित प्रेम दिखाने के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी जारी कर रहे थे और उनके समर्थक पटना में पुतले फूंकने में हाथ जला रहे थे, उसी दिन किशनगंज और दरभंगा से दलित औरतों को नंगा कर पीटने की खबरें आ रही थीं. क्या लालू प्रसाद कोई पत्र नीतीश कुमार को भी लिखेंगे? राहुल गांधी और केजरीवाल के बाद शरद यादव, वृंदा करात और डी राजा भी गुजरात के इन पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंच गए, जिनसे मिलकर आनंदीबेन पटेल पहले ही समुचित मुआवजा और दोषियों को सख्त सजा दिलाने का भरोसा दिला चुकी थीं. गुजरात में दलित घरों का राजनीतिक पर्यटन करने वाले ये नेता क्या मुजफ्फरपुर, दरभंगा और किशनगंज के पीड़ित-प्रताड़ित दलितों के घर नहीं जाएंगे? गुजरात में कथित दलित प्रताड़ना को लेकर हाय तौबा मचाने वाले मुख्यमंत्री बिहार में दलितों के उत्पीड़न पर चुप क्यों है? गुजरात में जहां 2015 में दलित उत्पीड़न की मात्र 1,052 घटनाएं घटीं वहीं बिहार में इसी अवधि में 7,874 घटनाएं दर्ज की गईं जो 2013 की 4,821 से करीब तीन हजार अधिक हैं. बिहार में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं मगर सरकार आरोपितों पर कार्रवाई करने की जगह मामलों की लीपापोती में जुटी है. कैमूर के भभुआ में एक दलित युवती की हत्या और यौन शोषण के मामले को पुलिस जांच से पहले ही आत्महत्या बता रही है. मुजफ्फरपुर के पारू में दलित युवकों को पेशाब पिलाने के आरोप को सरकार नकार रही है. पिछले तीन दिनों में नरकटियागंज में एक दलित युवती के साथ हथियार का भय दिखा कर अवैध संबंध बनाने और जमीन रजिस्ट्री नहीं करने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी, जहानाबाद के मखदुमपुर में दलितों के साथ मारपीट और घर में आग लगाने तथा दरभंगा के कुशेश्वरस्थान में दलितों के उत्पीड़न के मामले प्रकाश में आए हैं. इन सभी मामलों में कारगर कार्रवाई करने की जगह सरकार मामले को रफा-दफा करने में लगी हुई है. क्या इससे मुख्यमंत्री का दलित विरोधी चेहरा उजागर नहीं हो रहा है?

सूबे में निवेश को लेकर मोदी कहते हैं कि बिहार में उद्योग के क्षेत्र में कोई बड़ा निवेश नहीं हो पाया है. सरकार की उदासीनता से रोजगार के सर्वाधिक संभावना वाले आईटी के प्रक्षेत्र में भी बिहार देश के अन्य राज्यों की तुलना में निचले पायदान पर खड़ा है. नतीजतन आईटी प्रक्षेत्र में सृजित होने वाले रोजगार के बड़े अवसरों से वंचित बिहार के युवाओं को बंगलुरु व अन्य शहरों में जाने के लिए विवश होना पड़ रहा है.

भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर के लिए राज्य सरकार ने 2014 में नालंदा के राजगीर में 250 एकड़ जमीन चिन्हित कर केंद्र सरकार को सूचित किया था, मगर आजतक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है. इसी तरह केंद्र सरकार द्वारा राजगीर में प्रस्तावित आईटी सिटी भी जमीन के अभाव में अधर में है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना बक्सर और मुजफ्फरपुर में तथा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की भागलपुर और दरभंगा में करना था, जिसके लिए राज्य सरकार आज तक जमीन उपलब्ध नहीं करा सकी है. निलेट के लिए अन्ततः बिहटा में जो जमीन दी गई उसमें से 2.64 एकड़ पर अतिक्रमण है.

आईआईटी, पटना में केंद्र सरकार की ओर से स्थापित होने वाले इन्क्यूबेशन सेंटर के मैचिंग ग्रांट के तौर पर दिए जाने वाले 25 करोड़ में से राज्य सरकार बमुश्किल 5-6 करोड़ ही दे पाई है. डिजिटल इंडिया के तहत बिहार के करीब पांच हजार पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर खोला गया है, मगर राज्य सरकार की ओर से इन केंद्रों को आय प्रमाण पत्र, बिजली बिल आदि जमा करने जैसी सेवाएं नहीं दी जा रही हैं जिसकी वजह से यह केंद्र लाभकारी साबित नहीं हो पा रहे हैं.

2011 में बनी आईटी पॉलिसी के निष्प्रभावी होने की वजह से बिहार में उम्मीद के अनुरूप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में सौ करोड़ का पूंजी निवेश भी नहीं हो पाया. ऐसे में बिहार के लिए अब नई आईटी पॉलिसी की जरूरत है. बिहार न केवल आईटी क्षेत्र में पिछड़ गया है, बल्कि यहां के युवाओं को रोजगार के बड़े अवसरों से भी वंचित होना पड़ा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि क्या केवल शराबबंदी को लेकर दिन-रात अभियान चलाने से बिहार के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? सुशील मोदी का आरोप है कि गरीबों के अनाजों के उठाव में फर्जीवाड़े को रोकने में बिहार सरकार बुरी तरह से विफल रही है. सूबे के 1.54 करोड़ राशन कार्डधारियों में से मात्र 9 हजार को ही आधार नंबर से जोड़ा जा सका है. आधार कार्ड बनाने में भी बिहार देश के तमाम बड़े राज्यों में सबसे अंतिम पायदान पर है. राज्य में अभी तीन करोड़ से ज्यादा लोगों को आधार नंबर दिया जाना बाकी है. अनाजों के उठाव में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए पीडीएस दुकानों में 'प्वाइंट आफ सेल' डिवाइस लगाने की योजना अभी बिहार में ठीक से शुरू भी नहीं हो पाई है.

गरीबों को दो रुपये किलो दिए जाने वाले गेहूं पर करीब 22 रुपये और तीन रुपये किलो दिए जाने वाले चावल पर 30 रुपये का अनुदान भारत सरकार देती है. मगर बिचौलिए और दलाल उन्हें हड़प जा रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनता को बताना चाहिए कि गरीबों का अनाज जो दलालों व बिचौलियों के हाथों में चला जा रहा है, क्या उसे रोका नहीं जा सकता है?

बिहार में राशन कूपन योजना विफल हो चुकी है. ऐसे में राशनकार्ड के डिजिटलीकरण के बाद उन्हें उपभोक्ताओं के आधार नंबर से जोड़ने की जरूरत है. उसके बाद पीडीएस दुकानों पर प्वाइंट ऑफ सेल उपकरण लगाया जाए, जिससे कि लाभार्थियों की अंगुली के निशान से अनाज उठाव की पुष्टि हो तथा अन्य सरकारी योजनाओं को भी डीबीटी से जोड़ कर ही फर्जीवाड़े को रोका जा सके. आंध्रप्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्य प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस और राशन कार्ड को आधार नंबर से जोड़कर फर्जीवाड़े को रोकने में सफल रहे हैं. सरकारी योजनाओं के बंदरबांट और फर्जीवाड़े को रोकने में विफल रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या कालेधन पर आवाज उठाने का कोई हक है?

लालू प्रसाद के दोहरे व्यवहार पर सुशील मोदी कहते हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने सभी केंद्रीय मंत्रियों के सरकारी बंगले में गोपालन के लिए पीएम को पत्र लिखने से पहले क्या बिहार के मंत्रियों से गोपालन सुनिश्चत करा लिया है? लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री बनते हैं, तब घोटाला कर 900 करोड़ रुपये का चारा खा जाते हैं और जब आय से अधिक संपति के मामले में फंसते हैं, तब अपने को दूध का व्यापारी बताते हैं. उन्होंने दावा किया था कि दहेज में मिली एक बाछी से गायों की संख्या बढ़कर 100 हो गई और गायों का दूध बेचने से लाखों रुपये की जो कमाई हुई, उसे आय के ज्ञात स्त्रोत से अधिक संपति बताया जा रहा है. वे गोपालक हैं या दूध-व्यवसायी? ■

feedback@chauthiduniya.com

सरकारी दावों की पोल खोलती कांवड़ यात्रा

राजेश/गीता

विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के समापन के बाद प्रशासनिक तौर पर कांवड़ियों के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था की सच्चाई सामने आ गई है. बोलबम के जयकारे के बीच अनेक परेशानियों के बावजूद शिवभक्त कांवड़िए कावड़ लेकर देवघर पहुंचे. प्रशासनिक तौर कांवड़ियों को अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन सुल्तानगंज से देवघर के बीच झपटमार और अपराधियों का बोलबाला रहा. झपटमारों और अपराधियों ने कई कांवड़ियों को अपना निशाना बनाया. देवघर पहुंचे कांवड़ियों का दर्द सुनकर पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. कांवड़ियों की सुविधाओं के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन कांवड़ियों के आराम और रात्रि विश्राम के लिए बनाए गए भवन जर्जर हालत में हैं, तो सड़के गड्ढों ओर पत्थरों से भरी हुई हैं. रास्ते में खुली दुकानों के सामानों का मूल्य निर्धारण कर दिया जाता है, लेकिन दुकानदार प्रशासन को ठेंगा दिखाकर कांवड़ियों को मनमाने मूल्य पर उनके जरूरत के सामान देते हैं. सुल्तानगंज से देवघर के बीच कांवड़ियों को होने वाली समस्याओं से न बिहार सरकार और न ही झारखंड सरकार छुटकारा दिला पाई. कांवड़ लेकर देवघर (बैजनाथ धाम) जाने वाली सीवान की राखी कुमारी ने बताया कि मनोकामना पूर्ण होने के बाद वह लगभग दस वर्षों से देवघर आ रही हैं, लेकिन कभी भी कांवड़ियों को कोई सुविधा नहीं दी जाती है. रास्ते में समस्याएं ही समस्याएं मिलती हैं. कांवड़ लेकर देवघर जाने वाले निशांत कुमार बताते हैं कि कांवड़िया पथ पर बालू होने की वजह से कांवड़िए तपते बालू पर जाने को मजबूर हैं. प्रशासन की तरफ से उस पर कभी पानी का छिड़काव नहीं किया जाता. एक और कांवड़िए अभिषेक का कहना है कि विभिन्न सामानों के मूल्य निर्धारण के बाद भी भोजन अस्सी से नब्बे रुपये प्लेट मिलता है और प्रति कप चाय की कीमत दस रुपये वसूली जाती है. यहां तक की दवाईयां भी अधिक से अधिक मूल्यों पर दी जाती हैं. वहीं चंदन कुमार का कहना है कि पूरे रास्ते में कहीं पुलिस नजर नहीं आई और इसका फायदा उठाकर चोर और असामाजिक तत्वों ने लोगों के सामान और पैसे खूब उड़ाए. सरकार कह रही थी कि सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम है. यह सब दिन के उजाले में हो रहा था, रात्रि की तो बात ही छोड़ दीजिए. देवघर आए कई भक्तों ने रास्ते में होने वाली परेशानियों को बताया. सुल्तानगंज से देवघर की 96 किमी की यात्रा कांवड़ियों को असहनीय पीड़ा देती

है. अगुवानी से स्टीमर सेवा, कोसी क्षेत्र से देवघर के लिए रेल सेवा न होने की वजह से शिवभक्त जान हथेली रखकर गंगा नदी पार करते हैं. खगड़िया जिले के अगुवानी घाट से नाविक नावों पर क्षमता से अधिक लोगों बैठाकर नदी पार कराते हैं, इस पर भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, जिसकी वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. लेकिन भागलपुर के आयुक्त उदय कुमार का कहना है कि कांवड़ियों की सुख-सुविधा के लिए पूरी व्यवस्था की गई थी. उनका कहना है कि अगर ओवरलोडेड नावों का परिचालन हुआ है, तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. कांवड़िए रास्ते में होने वाली समस्याओं के बीच प्रति वर्ष देवघर जाते हैं. लेकिन न बिहार सरकार और न ही झारखंड सरकार को कावड़ियों की होने वाली समस्याओं से कोई लेना देना है. ■

ईम्पोर्टेड केमिकल से तैयार, लैब टेस्टेड
पेन्ट डिस्टेम्पर
कोई भी हो
वॉल पुट्टी केवल ईटालियन वॉल पुट्टी
Laboratory Tested
Please Compare Lab Report
Made from Imported Chemicals
ईटालियन व्हाइट वॉल पुट्टी
Slight Costly but Superior
लैब रिपोर्ट अवश्य चेक करें ।
लैब रिपोर्ट हमारे सभी डीलर्स के यहां उपलब्ध है
प्रखण्ड स्तर या अपने क्षेत्र हेतु सप्लायर / डीलरशिप के लिए सम्पर्क करें ।
Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com
सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाऐ
सीमेन्ट
कोई भी हो परन्तु
वाटरप्रूफिंग केमिकल सिर्फ
मिस्टर केमिस्ट
सीमेन्ट कोई भी हो लेकिन वाटरप्रूफिंग केमिकल मिस्टर केमिस्ट ही हो, क्योंकि मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग केमिकल ईम्पोर्टेड केमिकल से बनाया गया है, प्रत्येक पैक पर नम्बर युक्त होलोग्राम से नकल से पूरी तरह सुरक्षित १, ५, १०, २० एवं २०० लीटर होलोग्रामिक पैक में अब आपके यहां भी उपलब्ध । मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाए ।
Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com

बिहार टुन्नाजी पांडेय के बहाने

क़ानून को ठेंगा दिखा रहे जन प्रतिनिधि

पार्टी ने जांच के लिए एक कमिटी भी गठित कर दी है. इस मामले में अब भाजपा के पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, सिवाय खुद के बचाव के. ऐसे मामलों में वह सत्तारूढ़ महागठबंधन के दल, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल(यू) और कांग्रेस से अपने को बेहतर साबित करने में जुटी है. ट्रेन में महिला से छेड़खानी के आरोपित विधायक सरफराज आलम पर कार्रवाई करने में जद (यू) को दो दिन लगे थे, जबकि नाबालिग से बलात्कार के आरोपित विधायक राजवल्लभ यादव पर कार्रवाई करने में राजद को कोई एक सप्ताह का वक्त लग गया. वहीं, कांग्रेस ने तो महिला को अगवा करने के आरोपित अपने विधायक सिद्धार्थ शर्मा पर कोई कार्रवाई ही नहीं की.

सरोज सिंह

बिहार में विधान मंडल अधिवेशन के ठीक पहले राजनीतिक चाल का पासा बदला हुआ दिख रहा है. सूबे का मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और इस लिहाज से एनडीए बचाव में है. भाजपा और इसके सहयोगी दल महागठबंधन के विधायकों पर उच्छृंखल व गैर-सामाजिक आचरण के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन इस बार भाजपा खुद बैकफुट पर है. इसके विधान परिषद सदस्य टुन्नाजी पांडेय को चलती ट्रेन में नाबालिग से छेड़खानी के आरोप में जेल भेज दिया गया

> **टुन्नाजी पाडेय महिलाओं के साथ आपराधिक आचरण करने के मामले में मीडिया की सुर्खियां बटोरने वाले पहले जनप्रतिनिधि नहीं हैं. विधानसभा चुनाव के बाद महिला पर अपराध (बलात्कार, अपहरण, छेड़खानी, बदसलूकी) का पहला आरोप जद (यू) विधायक सरफराज आलम पर लगा था और उसे पार्टी से निकाल दिया गया. दिल्ली की एक महिला ने आलम पर गुवाहाटी राजधानी में यात्रा के दौरान बदसलूकी का आरोप लगाया था. उत्तर-पूर्वी बिहार के बाहुबली नेता तस्लीमुद्दीन के पुत्र सरफराज आलम की खुद की पहचान भी साफ-सुथरी नहीं है.**

है. हालांकि भाजपा ने घटना के कुछ ही घंटों के भीतर टुन्नाजी पांडेय को पार्टी से छह साल के लिए निलंबित कर दिया और कारण बताओ नोटिस जारी कर उससे जवाब तलब किया गया है. पार्टी ने जांच के लिए एक कमिटी भी गठित कर दी है. इस मामले में अब भाजपा के पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, सिवाय खुद के बचाव के. ऐसे मामलों में वह सत्तारूढ़ महागठबंधन के दल, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल(यू) और कांग्रेस से अपने को बेहतर साबित करने में जुटी है. ट्रेन में महिला से छेड़खानी के आरोपित विधायक सरफराज आलम पर कार्रवाई करने में जद (यू) को दो दिन लगे थे, जबकि नाबालिग से बलात्कार के आरोपित विधायक राजवल्लभ यादव पर कार्रवाई करने में राजद को कोई एक सप्ताह का वक्त लग गया. वहीं, कांग्रेस ने तो महिला को अगवा करने के आरोपित अपने विधायक सिद्धार्थ शर्मा पर कोई कार्रवाई ही नहीं की.

भाजपा के एमएलसी पूर्वांचल एक्सप्रेस से दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) से आ रहे थे. उसी कोच के एक यात्री थाईलैंड के भारतीय व्यवसायी विजयप्रकाश पांडेय की बारह वर्षीय पुत्री ने विधान पार्षद पर छेड़खानी का आरोप लगाकर रेल पुलिस में मामला दर्ज कराया. आरोप है कि एमएलसी ने लड़की को चूमने की कोशिश की, और भी कुछ कहा. हाजीपुर में रेल पुलिस ने टुन्नाजी को गिरफ्तार कर लिया. अदालत से उसे चौदह दिन की न्यायिक हिरासत मिली है. टुन्नाजी का आरोप है कि उसे साजिशन फंसाया गया है. एमएलसी का कहना है कि बोगी में अंधेरा था और मोबाइल का चार्जर निकालने के लिए उन्होंने लाइट जलाई थी. एमएलसी को इस बात पर भी आक्रोश है कि पार्टी ने एकतरफा कार्रवाई की, उसका पक्ष तक नहीं सुना. आरोपित टुन्नाजी पांडेय पर कार्रवाई के बावजूद भाजपा पर विपक्ष के हमले जारी हैं. हालांकि इसी समय बड़हड़िया (सीवान) के जद (यू) विधायक श्याम बहादुर सिंह पर जिले के पंचरूखी थाने में जिले के दो डॉक्टरों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई. डॉक्टरों का आरोप है कि उन लोगों ने पंचरूखी में जमीन खरीदी है, जिस पर विधायक कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके एवज में वह बीस लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे हैं. ये वही श्याबहादुर सिंह हैं, जिनके बार-बालाओं के साथ भोंडे नाच के वीडियो पिछले दिनों वायरल हुए थे.

टुन्नाजी पांडेय महिलाओं के साथ आपराधिक आचरण करने के मामले में मीडिया की सुर्खियां बटोरने वाले पहले जनप्रतिनिधि नहीं हैं. विधानसभा चुनाव के बाद महिला पर अपराध (बलात्कार, अपहरण, छेड़खानी, बदसलूकी) का पहला आरोप जद (यू) विधायक सरफराज आलम पर लगा था और उसे पार्टी से निकाल दिया गया. दिल्ली की एक महिला ने आलम पर गुवाहाटी राजधानी में यात्रा के दौरान बदसलूकी का आरोप लगाया था. उत्तर-पूर्वी बिहार के बाहुबली नेता तस्लीमुद्दीन के पुत्र सरफराज आलम की खुद की पहचान भी साफ-सुथरी नहीं है. इस प्रकरण में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, पर जमानती धाराएं होने के कारण थाने से ही जमानत मिल गई. इस मामले में स्पीडी ट्रायल की बात कही गई थी, लेकिन सात महीने गुजर जाने के बावजूद इसकी तफ्तीश भी पूरी नहीं हुई है. हालांकि सरफराज आलम के इस कारनामे के सामने आने के बाद जद (यू) ने उन पर कार्रवाई की और पार्टी से छह साल के लिए निकाल दिया. पर, ऐसा करने में जद (यू) नेतृत्व को दो दिन का वक्त लग गया. कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ शर्मा के कारनामे भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं. पटना के एक नामचीन शिशुरोग विशेषज्ञ डॉक्टर के इस बिगड़ैल विधायक पुत्र पर एक बालिका के अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था. चार दिन बाद अगवा

बीमा भारती

मनोरमा देवी

सरफराज़ आलम

राजवल्लभ प्रसाद यादव

युवती और विधायक थाने में नमूदार हुए. युवती ने मीडिया को बताया कि उसका अपहरण नहीं हुआ है. विधायक जी के चालक से उसका प्रेम-संबंध रहा और वे दोनों शादी करना चाहते थे. राजद विधायक और राबड़ी सरकार के पूर्व मंत्री राजवल्लभ प्रसाद यादव ने तो अब तक का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया. नाबालिग लड़की के बलात्कार के आरोप में वह अभी जेल में बंद है. बिहारशरीफ की एक नाबालिग लड़की को झांसा देकर नवादा ले जाया गया. उसके साथ बलात्कार करने का आरोप राजवल्लभ पर है. इस प्रकरण में राजवल्लभ पर कार्रवाई करने में राजद को एक हफ्ता लग गया था. उसे दल से छह साल के लिए निकाला गया.

राजवल्लभ प्रसाद यादव, सिद्धार्थ शर्मा, सरफराज आलम और टुन्नाजी पांडेय में क्या समानता है? वस्तुतः चारों में एक बात समान है- ये सभी गैर राजनीतिक रास्ते से राजनीति में आए. धन ने जहां उन्हें राजनीति का रास्ता दिया, वहीं हैसियत और शोहरत भी दी. राजवल्लभ यादव की बलात्कार के एक मामले में फंसने के बाद उसकी विधानसभा की उम्मीदवारी काट दी गई थी, पर निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद वह फिर लालू दरबार का रत्न बन गया था.

सरफराज आलम के पिता मोहम्मद तस्लीमुद्दीन किसी दौर में लालू प्रसाद के खास लोगों में थे. नीतीश की हवा चलने के बाद वे उनके साथ हो गए. फिलवक्त पिता राजद सांसद और पुत्र जद (यू) विधायक हैं. विधायक बनने से पहले तक सिद्धार्थ शर्मा की पहचान पटना के एक ख्यातिप्राप्त शिशुरोग विशेषज्ञ के पुत्र की ही थी, जो हत्या जैसे संगीन अभियोग में जेल की यात्रा कर चुके हैं. सीवान-गोपालगंज क्षेत्र में टुन्नाजी पांडेय बतौर शराब कारोबारी काफी जाना-पहचाना नाम है. कानून को ठेंगा दिखाने के जनप्रतिनिधियों के आचरण के उदाहरण तो और भी हैं. बिहार के मंत्री अब्दुल गफूर ने बाहुबली सरगना मोहम्मद शहाबुद्दीन से जेल में जाकर मुलाकात की. राजद सुप्रीमो ने उनका बचाव ही किया. बिहार में नई सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद जद (यू) विधायक बीमा भारती पर अपने बाहुबली पति अवधेश मंडल को पुलिस की गिरफ्त से भगाने का आरोप लगा था. जद (यू) की विधान पार्षद मनोरमा देवी पर शराबबंदी कानून के उल्लंघन का तो आरोप लगा ही, आदित्य सचदेवा की हत्या के आरोपी पुत्र को भगाने का भी आरोप लगा. विधायकों के ऐसे कारनामों की फेहरिस्त काफी लंबी है.

वस्तुतः राजनीति में गैर राजनीतिक तत्वों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है. कानून के उल्लंघन का अराजक भाव जनप्रतिनिधियों में पैदा हो गया है, जो सार्वजनिक जीवन में संकट का एक नया कारण बन सकता है.■

feedback@chauthiduniya.com

एक बार डाक्टर से मिलने पर भी हड्डी रोग का इलाईज संभव
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

डॉ अभीनीत कुमार
M.B.B.S. (Pat), Gold Medalist
M.S. Ortho, (Narayan Health Care Centre) ARA

नारायण हेल्थ केयर सेन्टर, हड्डी एवं दाँत क्लीनिक, आरा से डॉ. अभिनित कुमार से बातचीत हुई इस क्रम में उन्होंने बताया कि आजकल की जीवन शैली के कारण हड्डी और कई प्रकार के रोग पनप रहे हैं। दूसरा मन में भी भ्रांति है की एक बार डॉक्टर से मिलने के बाद बार-बार सम्पर्क में रहना पड़ेगा। लेकिन डॉ. अभिनित ने बताया कि हड्डी रोग चिकित्सा में कई रोग ऐसे भी हैं कि मरीज एक बार डॉक्टर से मिल ले तो उसे कुछ सलाह और एक्सरसाईज बताकर एक ही बार में बिमारी का निदान किया जा सकता है। डॉ अभिनीत का मानना है कि 95 प्रतिशत मरीज के हाथों में होता है आप अपने रोग को बताये गये उपायों से कम कर सकते हैं।

डॉ. अभिनीत ने बताया कि बिटामीन डी एवं कैल्शियम की कमी से बच्चों में अक्सर बच्चों में रिकट्स और ऑस्टोमलेशिया पाया जाता है जिसकी पहचान यह है कि बच्चे की हड्डी में दर्द, टेढ़ापन खासकर घुटना, कलाई, केहूनी आदि में। हड्डी सबंधित रोग होने पर इग्नोर नहीं करें तुरंत अपने नजदीकी ऑर्थो चिकित्सक से सम्पर्क करें। इनके भोजन में सुधार जरूर करें और इन्हें कैल्शियम, एवं बीटामिन युक्त भोजन जैसे दूध अंडा, हरी ताजी पत्तेदार सब्जियों दें साथ ही इन्हें सूर्य की रौशनी भी मिलनी चाहिए। आजकल व्यस्त लाइफ की वहज, लोगों का बैठकर कमप्यूटर पर काम करने की वजह, बैठने का पॉस्चयर आदि से भी हड्डी रोग ज्यादा हो रहे हैं बच्चे हों या बड़े हर किसी को सुबह की धूप जरूरी है। नियमित व्ययाम और सही लाइफ स्टाइल से भी आप खुद को और बच्चों में कई प्रकार के होने वाले हड्डी रोगों से बचा सकते हैं। बच्चों के लिए खेलकूद जरूरी है इसलिए अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों के फिजिकल खेल पर ध्यान दें जिससे उनका विकास हो सके ।■ चित्रा भारती

Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.
A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil
Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg
Acoba Syp.
Methylocobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

JOHNSON PAINTS
— Interior & Exterior Wall Paints —
JP
बड़े अच्छे लगते हैं...

बसपा का नफा नुकसान

वैष्णवी वंदना

विधानसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति रोचक मोड़ पर आ गई है. कुछ ही दिन पहले भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह की बोली से मृतप्राय बसपा में जान आ गई थी, लेकिन दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाती सिंह ने अपने बूते पूरी राजनीति की दिशा मोड़ दी. महिला अस्मिता की रक्षा के लिए जिस तरह स्वाती सिंह मैदान में कूद पड़ीं, उसने मायावती को अचानक भौंचक्का कर दिया और उन्हें बैकफुट पर जाना पड़ा. अब जमीनी राजनीति की स्थिति यह है कि बसपा का ग्राफ नीचे और स्वाती सिंह का ग्राफ ऊंचाई पर जा रहा है. इसमें भाजपा भी हक्की-बक्की हालत में ही है, क्योंकि भाजपा नेतृत्व को यह सूझ नहीं रहा कि जिस मायावती से भय खाकर दयाशंकर सिंह को आनन-फानन पार्टी से निकाल बाहर किया गया, उसी नेता की पत्नी ने पूरी पार्टी को रेस्क्यू कर लिया. ऐसे में अब दयाशंकर सिंह का क्या किया जाए. बहुत संभव है कि दयाशंकर सिंह का निष्कासन जल्दी ही वापस ले लिया जाएगा.

दयाशंकर सिंह ने जमानत मिलते ही मायावती और नसीमुद्दीन समेत उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिस तरह ललकारा, उससे यही लगा कि इस मनोबल के पीछे पार्टी की ताकत काम कर रही है. मऊ की जेल से छूटकर लखनऊ पहुंचे दयाशंकर सिंह अपनी पत्नी स्वाती सिंह के साथ मीडिया से मुखातिब हुए. राजधानी के प्रेस क्लब में आनन-फानन में आयोजित प्रेस वार्ता में दयाशंकर सिंह ने आते ही सीधा हमला बसपा सुप्रीमो मायावती और नसीमुद्दीन पर बोला. दयाशंकर सिंह ने मायावती को चुनौती दी कि प्रदेश के किसी भी सामान्य सीट पर स्वाती सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ कर दिखाएं. उन्होंने दावा किया कि स्वाती सिंह निर्दलीय लड़कर भी मायावती को हराएंगी, यह चैलेंज है. मायावती ने इस चैलेंज को स्वीकार करने के बजाय कहा कि यह सवाल ही फालतू है और ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास वक्त नहीं है. राष्ट्र के काम में वे वैसे ही बहुत व्यस्त रहती हैं.

मायावती के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी के सवाल पर दयाशंकर ने कहा कि उन्होंने अपने बयान पर फौरन ही माफी मांग ली थी. इसके बाद भी उन्हें सजा मिली, मुकदमा दर्ज हुआ और अपराधियों की तरह उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया. दूसरी तरफ बसपा नेताओं ने उनकी पत्नी, बेटी व मां के खिलाफ सार्वजनिक मंच से जो अभद्र टिप्पणियां कीं उस पर मायावती और नसीमुद्दीन ने आज तक माफी नहीं मांगी और न ही उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने कोई कार्रवाई की. नसीमुद्दीन समेत अन्य दोषी बसपा नेताओं की अभी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. दयाशंकर ने कहा कि वे इस बात पर फिर से जोर देकर कहते हैं कि मायावती टिकट बेचती हैं, टिकट बेचती हैं, टिकट बेचती हैं. इस आरोप की सीबीआई जांच कराई जाए तो सारा खेल स्पष्ट हो जाएगा. उन्होंने कहा कि इसके लिए वह कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, क्योंकि मायावती को टिकट बेचकर दलितों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि मायावती देश की सबसे भ्रष्ट नेता हैं. उनकी सम्पत्ति की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए. साथ ही आम आदमी से करोड़पति बन गए उनके करीबी नसीमुद्दीन और सतीशचंद्र मिश्रा की सम्पत्ति की भी जांच होनी चाहिए. दयाशंकर यह भी बोले कि गेस्ट हाउस कांड के वक्त मायावती की इज्जत बचाने में भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी के साथ वह भी मौजूद थे.

दयाशंकर सिंह की चुनौती के बारे में पूछे जाने पर बसपा नेता मायावती को गुस्सा आ गया. वे बोलीं कि कोई और सवाल पूछना हो तो पूछें. मायावती ने इस सवाल को फालतू बताते हुए कहा कि ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास वक्त नहीं है. उल्लेखनीय है कि बसपा प्रमुख मायावती पर दयाशंकर द्वारा की गई विवादित टिप्पणी के खिलाफ बसपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर दयाशंकर सिंह की मां, बहन और बेटी पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी. इसके बाद ही दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाती सिंह ने बिफर कर मोर्चा संभाल लिया और मायावती समेत बसपा नेताओं को रक्षात्मक रवैया अपनाना पड़ा. दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाती सिंह ने कहा कि मायावती ने अभी तक उनके सवालों का जवाब नहीं दिया है. वे एक सामान्य महिला की तरह मायावती से जवाब मांग रही हैं. स्वाती सिंह ने भी चुनौती दोहराई कि मायावती में नैतिक बल है तो वे प्रदेश की किसी भी सामान्य सीट पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ कर दिखाएं. ■

feedback@chauthiduniya.com

राजनाथ के बयान के सियासी मायने

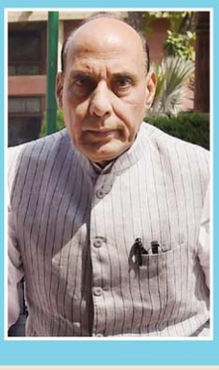

आम तौर पर मुलायम और अखिलेश के खिलाफ सार्वजनिक तल्ख टिप्पणियां देने से परहेज रखने वाले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अब अखिलेश सरकार पर खुल कर प्रहार शुरू कर दिया है. राजनाथ के बयान के गहरे राजनीतिक निहितार्थ तलाशे जा रहे हैं. भाजपाई भी यह कयास लगा रहे हैं कि आखिरी वक्त कहीं राजनाथ ही भाजपा का चेहरा तो नहीं बन रहे. बुलंदशहर की घटना पर राजनाथ ने अखिलेश सरकार की कानून व्यवस्था को आड़े हाथों लिया और कहा कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई है. राजनाथ बोले कि जनता के मन में यूपी को लेकर इतने सवाल खड़े हो गए हैं कि यह अपने आप में प्रश्न प्रदेश बन कर रह गया है. राजनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को अराजक, बदतर और लचर कहा. राजनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में दुष्कर्म की घटनाओं में 161 फीसदी की वृद्धि हुई है. यह शर्मनाक है. ये आंकड़े खुद यूपी सरकार के राज्य अपराध ब्यूरो के हैं. राजनाथ ने उत्तर प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी प्रहार किया और कहा कि भ्रष्टाचार तो यहां संस्थागत हो गया है. प्रदेश में पिछले 15 वर्षों से सपा और बसपा की सरकारें रही हैं, लेकिन प्रदेश विकास के मामले में हाशिए पर पहुंच गया.

गंगा सफाई को लेकर केंद्र सरकार को सूझ नहीं रहा कोई ठोस जवाब

आंकड़े ही आंकड़े दे रहे हैं बांकुड़े!

सूफी यायावर

गंगा की सफाई को लेकर अजीबोगरीब आंकड़े सामने आ रहे हैं. इन आंकड़ों से गंगा की सफाई के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भावनात्मक जुड़ाव के बयानों पर सवाल खड़े हो रहे हैं. सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवालों पर जो आधिकारिक जवाब और आंकड़े उजागर हुए हैं वे आश्चर्यजनक हैं और हास्यास्पद भी. भाजपा के पिछले दो वर्षों के शासन काल में गंगा की सफाई के लिए करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं, लेकिन इस खर्च का कोई असर गंगा पर दिख नहीं रहा है.

लखनऊ के एक स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा ऐश्वर्या पाराशर ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय से सात सवालों का जवाब मांगा था. गंगा सफाई को लेकर पूछे गए सवाल बजटीय प्रावधानों, खर्चों और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठकों के विवरण से संदर्भित थे. लेकिन इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय ने नहीं दिया. पीएमओ के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी सुब्रतो हजारा ने इतना ही कहा कि ऐश्वर्या का पत्र केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय के पास भेज दिया गया है. विडंबना यह है कि इस मंत्रालय ने भी कई महत्वपूर्ण सवालों का जवाब नहीं दिया और उसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास भेज दिया. केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय के अवर सचिव केके सप्रा ने अपने इस बुद्धिमत्ता भरे कृत्य के बारे में लिखित तौर पर जानकारी दी.

बहरहाल जो जवाब सामने आए, वे भी अत्यंत रोचक हैं. मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय गंगा सफाई मिशन के लिए 2014-15 में 2,137 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. बाद में इसमें 84 करोड़ रुपये की कटौती कर इसे 2,053 करोड़ रुपये कर दिया गया. लेकिन केंद्र सरकार ने भारी प्रचार-प्रसार के बावजूद सिर्फ 326 करोड़ रुपये खर्च किए, और इस तरह 1,700 करोड़ रुपये बिना खर्च हुए रह गए. वर्ष 2015-16 में केंद्र सरकार ने प्रस्तावित 2,750 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन को घटाकर 1,650 करोड़ रुपये कर दिया. जिसमें से 18 करोड़ रुपये बचे रह गए. मौजूदा वित्त वर्ष (2016-17) में आवंटित 2,500 करोड़ रुपये में से अबतक कितना खर्च हुआ, केंद्र सरकार के पास उसका कोई विवरण मौजूद नहीं है. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) की तीन बैठकों में से प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक बैठक की अध्यक्षता 26 मार्च, 2014 को की थी. अन्य दो बैठकों की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने की थी, जो 27 अक्टूबर 2014 और चार जुलाई 2016 को हुई थीं. पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान हुई एनजीआरबीए की सभी तीन बैठकों की अध्यक्षता की थी. ये बैठकें पांच अक्टूबर 2009, पहली नवंबर 2010 और 17 अप्रैल 2012 को हुई थीं. ■

लखनऊ के एक स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा ऐश्वर्या पाराशर ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय से सात सवालों का जवाब मांगा था. गंगा सफाई को लेकर पूछे गए सवाल बजटीय प्रावधानों, खर्चों और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठकों के विवरण से संदर्भित थे. लेकिन इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय ने नहीं दिया. पीएमओ के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी सुब्रतो हजारा ने इतना ही कहा कि ऐश्वर्या का पत्र केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय के पास भेज दिया गया है.

कल-कारखानों से लेकर नागरिक तक फैला रहे गंदगी

आरटीआई के तहत केंद्र सरकार से सवाल-जवाब की कागजी औपचारिकताओं के बरक्स जमीनी स्थिति और भी भयावह दिखती है. गंगा की अविरल और निर्मल धारा बहाल करने में गंगा के किनारे-किनारे स्थित 764 उद्योग और उनसे निकलने वाले हानिकारक अवशिष्ट विशाल चुनौती की तरह सामने हैं. आधिकारिक तथ्य है कि गंगा नदी के किनारे कुल 764 उद्योग हैं, जिनमें 444 चमड़ा उद्योग, 27 रसायनिक उद्योग, 67 चीनी मिलें, 33 शराब उद्योग, 22 खाद्य और डेयरी उद्योग, 63 कपड़ा एवं रंग उद्योग, 67 कागज एवं पल्प उद्योग और 41 अन्य उद्योग शामिल हैं. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा तट पर स्थित इन उद्योगों द्वारा प्रतिदिन 112.3 करोड़ लीटर जल का उपयोग किया जाता है. इनमें रसायन उद्योग 21 करोड़ लीटर, शराब उद्योग 7.8 करोड़ लीटर, कागज एवं पल्प उद्योग 30.6 करोड़ लीटर, चीनी उद्योग 30.4 करोड़ लीटर, चमड़ा उद्योग 2.87 करोड़ लीटर, कपड़ा एवं रंग उद्योग 1.4 करोड़ लीटर एवं अन्य उद्योग 16.8 करोड़ लीटर गंगा जल का उपयोग प्रतिदिन कर रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि गंगा नदी के तट पर स्थित प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग और गंगा जल के अंधाधुंध दोहन से नदी का अस्तित्व संकट में है. गंगा की सफाई हिमालय क्षेत्र में इसके उद्गम से शुरू करके मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी एवं सहायक नदियों में होनी चाहिए, जो अबतक नहीं हुई है. उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर बनने वाली जलविद्युत परियोजनाएं गंगा की धारा के मार्ग में बड़ी बाधा हैं. इसके कारण गंगा नदी के ही समाप्त हो जाने का खतरा सामने है, क्योंकि नदी पर बांध बनाने की परियोजनाएं इसके उद्गम पर ही अवस्थित हैं. नमामि गंगे योजना को कारगर करने के लिए सरकार ने प्रतिष्ठित संगठनों एवं एनजीओ को इस काम में जोड़ने का निर्णय लिया ताकि त्यौहारों के मौसम और सामान्य दिनों में गंगा में फूल, पत्ते, नारियल, प्लास्टिक और ऐसे ही कचरे बहाने पर नियंत्रण किया जा सके, केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री, मथुरा, वृंदावन, गढ़मुक्तेश्वर, इलाहाबाद, वाराणसी, वैद्यनाथ धाम, गंगासागर तक मानव-प्रेरित गंदगियों से मुक्ति का अभियान चलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन लोग गंगा को गंदगी दान करने में कतई पीछे नहीं हट रहे हैं. ■

चुनाव आया तो विकास में सहयोग के लिए अखिलेश ने लिखा सांसदों को पत्र

चतुर चिंता की चिट्ठी...

दीनबंधु कबीर

उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव सामने है तब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव में विकास के प्रति अतिरिक्त चिंता जाग्रत होने लगी है. सियासी नजरिए से यह स्वाभाविक है. सामाजिक नजरिए से विकास कहीं दिख नहीं रहा तो कम से कम उसकी चिंता चुनाव के समय सार्वजनिक तौर पर तो दिखनी चाहिए. समाजवादी सरकार को समाज का विकास कुछ किलोमीटर की मेट्रो ट्रेन की पटरी लगाकर दिखाने और एक्सप्रेस हाई-वे बनाने में सक्रियता दिखाने पर केंद्रित है. गन्ना किसानों के सैकड़ों करोड़ रुपये बकाया हैं, गेहूं-धान की फसलें खरीदी नहीं गईं, किसानों को अपने कृषि उत्पाद बाजार में औने-पौने भाव में बेचने को विवश होना पड़ा, रोजगार का कोई साधन विकसित हुआ नहीं, एक भी कल-कारखाना लगा नहीं, फिर क्या चार-पांच किलोमीटर की पटरी पर चलने वाली मेट्रो रेल खाएंगे किसान? मेट्रो रेल या एक्सप्रेस हाई-वे जैसी सुविधाएं समाज के किस वर्ग के लिए होंगी, यह समाज और समाजवाद को समझने वाले लोग जानते हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यूपी के सांसदों को पत्र लिख कर केंद्र में अटकी पड़ी विकास की विभिन्न योजनाओं को पास कराने में सहयोग मांग रहे हैं. करीब-करीब सारे सांसद चूंकि भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसलिए इस राजनीति की अभी अखिलेश को ज्यादा आवश्यकता भी थी. जब समाजवादी पार्टी निवर्तमान यूपीए सरकार के साथ एकतरफा प्यार में कुर्बान हुई जा रही थी, उस समय सपा के नेताओं को सांसदों की याद नहीं आ रही थी. बहरहाल, अगर विकास की मंशा है भी तो यह पांच साल पूरा होने के वक्त ही क्यों उछाल मारने लगी? यही पत्र पहले क्यों नहीं लिखा गया? अखिलेश परिवार में उनके पिता मुलायम सिंह यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव और दो भाई धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव मिला कर समाजवादी पार्टी के कुल जमा चार सांसद हैं, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ने इन 'पारिवारिक' सांसदों को भी पत्र लिख कर उत्तर प्रदेश के विकास के काम में सहयोग मांगा होगा.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश के सभी सांसदों को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश के विकास हित में केंद्र सरकार में लम्बित राज्य के विभिन्न प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए अपने स्तर से समुचित कदम उठाने का अनुरोध किया है. अखिलेश ने इस पत्र में उल्लेख किया है कि उत्तर प्रदेश के विकास और तरक्की के लिए विभिन्न विषयों पर समय-समय पर प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार से अनुरोध किया जाता रहा है. कई पत्र प्रधानमंत्री को भी लिखे गए. सांसदों को लिखे गए मुख्यमंत्री के पत्र में सरकार ने केंद्र सरकार को प्रेषित किए गए महत्वपूर्ण प्रकरणों को भी संलग्न किया है. सांसदों से यह अनुरोध किया गया है कि राज्य के विकास हित में लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए वे अपने स्तर से भी समुचित कदम उठाएं. पत्र के साथ संलग्नक के तौर पर प्रेषित एक पुस्तिका में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजे गए 28 महत्वपूर्ण मामले शामिल किए गए हैं. इनमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सम्बन्धित चार प्रकरण, विधि एवं न्याय मंत्रालय से सम्बन्धित एक प्रकरण, ग्राम्य विकास मंत्रालय से जुड़े दो प्रकरण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से सम्बन्धित एक प्रकरण, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्रालय से सम्बन्धित तीन प्रकरण, गृह मंत्रालय से सम्बन्धित पांच प्रकरण, संस्कृति मंत्रालय से सम्बन्धित दो प्रकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से सम्बन्धित एक प्रकरण, रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित तीन प्रकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से सम्बन्धित तीन प्रकरण और ऊर्जा मंत्रालय से सम्बन्धित तीन प्रकरण शामिल हैं.

मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय को प्रेषित प्रकरणों में राज्य में चार लाख शिक्षक एवं अनुदेशकों के पारिश्रमिक के भुगतान संकट को देखते हुए वर्ष 2015-16 के अवशेष केंद्रांश 3585 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त किया जाना, मध्यान्ह भोजन योजना में रसोइयों का मानदेय, जो सात वर्षों से नहीं बढ़ा है, को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रतिमाह किया जाना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत केंद्रांश की लगभग 187 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त किया जाना और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत निर्मित हो रहे 26 राजकीय विद्यालयों के लिए द्वितीय किस्त प्राप्त न होने के कारण प्रभावित हो रहे निर्माण कार्य को सुचारू बनाए रखने के लिए 441 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त किया जाना शामिल है. गृह मंत्रालय से संदर्भित प्रकरणों में भू-मानचित्रों के डिजिटाइजेशन के लिए 14 करोड़ रुपये की अंतर धनराशि की स्वीकृति, वर्ष 2015 में ओलावृष्टि से कृषि फसलों को हुई क्षति की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय आपदा कोष से 4742 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त किया जाना, राज्य आपदा मोचक निधि से लघु और सीमान्त कृषक के साथ ही भूमिहीन लोगों के पशुओं को भी चारा, दवाएं वगैरह दिए जाने सम्बन्धी मानकों में संशोधन, राज्य आपदा मोचक निधि से प्रभावित परिवारों को अहैतुक सहायता दिए जाने के मानकों में संशोधन के विषय शामिल हैं.

सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्रालय को भेजे गए मामलों में एआईबीपी वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए केंद्रांश की धनराशि का अवमुक्त किया जाना, राजकीय नलकूपों का सौर ऊर्जा एवं ग्रिड ऊर्जा के हाइब्रिड मॉडल से संचालन और बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम से सम्बन्धित मामले शामिल हैं. इसी तरह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जनपद मुख्यालय को 4-लेन मार्ग/2-लेन विद पेव्ड शोल्डर मार्ग से जोड़ने की योजना में धीमी प्रगति, केंद्रीय मार्ग निधि योजना के तहत पर्याप्त धनराशि (01 हजार करोड़ रुपये) उपलब्ध कराया जाना और राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण का प्रकरण भेजा गया है.

रक्षा मंत्रालय को भेजे गए मामलों में प्रदेश के जनपद कन्नौज एवं रामपुर में 02 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना, जनपद लखनऊ में दिलकुशा एवं जनेश्वर मिश्र पार्क के मध्य गोमती नदी (पिपरा घाट) सेतु के निर्माण की परियोजना पर सेना द्वारा वर्किंग परमिशन दिए जाने और जनपद लखनऊ में लोहिया पथ पर गोमती बैराज से कुकरैल नाले के बाएं तटबंध से होते हुए खुर्रमनगर तक 6-लेन मार्ग एवं आरओबी सह फ्लाईओवर के निर्माण हेतु सेना की भूमि पर वर्किंग परमिशन दिए जाने के मामले शामिल हैं. ऊर्जा मंत्रालय को मेजा तापीय विद्युत गृह से प्रदेश को आंवटित शेयर में वृद्धि किए जाने के प्रकरण भी प्रेषित किए गए हैं. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को नए मेडिकल कॉलेज (डिस्ट्रिक्ट/रेफरल हॉस्पिटल्स के साथ) के निर्माण लागत की सीमा बढ़ाया जाना, ग्राम्य विकास मंत्रालय को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम 1500 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की आवश्यकता और प्रदेश के बुंदेलखंड एवं विध्य क्षेत्रों में सरफेस सोर्स आधारित पेयजल परियोजनाओं के लिए शत्-प्रतिशत केंद्रीय सहायता के रूप में 2360 करोड़ रुपये की मांग, विधि एवं न्याय मंत्रालय को अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय भवनों एवं न्यायिक अधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण की योजना में केंद्रांश अवमुक्त किया जाना और संस्कृति मंत्रालय को टैगोर कल्चरल कॉम्प्लेक्स योजना के तहत लखनऊ स्थित राष्ट्रीय कथक संस्थान के भवन के निर्माण के लिए 09 करोड़ रुपये अवमुक्त किया जाना और टैगोर कल्चरल कॉम्प्लेक्स मथुरा में ऑडिटोरियम के लिए 14 करोड़ रुपये अवमुक्त किए जाने के प्रकरण प्रेषित किए गए हैं.

सांसदों को लिखे पत्र के तथ्यों पर गौर करिए. जिन विशेषज्ञों की निगाह विकास की जमीनी स्थिति पर रहती है, उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव आने के वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार आंकड़ों की बाजीगरी करके आम जनता के समक्ष नियोजित झांसा परोस रही है, क्योंकि लोग अब विकास की जमीनी स्थिति के बारे में आमने-सामने से पूछेंगे. इन समीक्षकों का कहना है कि प्रदेश के विकास का सारा ठेका केंद्र सरकार का ही है तो फिर राज्य सरकारों का औचित्य क्या है! मुख्यमंत्री के पत्र में जिन कार्यों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि वे केंद्र में लंबित हैं, तथ्य बताते हैं कि उनमें से अधिकांश की मंजूरी केंद्र से मिल चुकी है और समय-समय पर उसकी खबरें प्रकाशित भी होती रही हैं. सांसदों को लिखे पत्र पर प्रदेश के जुझारू किसान नेता शिवाजी राय कहते हैं कि प्रदेश के मरते और तबाह होते किसानों के सवालों का जवाब और प्रदेश की सड़ियल कानून व्यवस्था के भुक्तभोगियों के सवालों के जवाब तो सरकार दे नहीं सकती, उसे सांसदों को पत्र लिखने का नैतिक अधिकार क्या है? शिवाजी राय कहते हैं कि यह पत्र नहीं, दायित्वों की टोपी है, जिसे अखिलेश यादव अब चुनाव के समय दूसरों को पहनाने का फूहड़ आयोजन कर रहे हैं. ■

जब खुद सांसद थे तो क्या किया था!

पुराना प्रकरण है. अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने के पहले सांसद ही थे. वर्ष 2012 के पहले वे कन्नौज से सांसद थे. संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए मिलने वाली सांसद-निधि के अपव्यय का मसला अखिलेश यादव के साथ भी चिपका हुआ है. यहां तक कि तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष तक को कन्नौज संसदीय क्षेत्र से शिकायतें भेजी गई थीं कि अखिलेश यादव के सांसद निधि के व्यय में अपव्यय हो रहा है. सांसद निधि का धन विकास के काम में खर्च होने के बजाय निजी कामों में खर्च हो रहा था. उस समय अखिलेश यादव के लिए विकास का मसला प्राथमिकता पर नहीं था. अब भी नहीं था. चुनाव के वक्त विकास का मसला फिर से याद आया, यह वक्त का तकाजा है, जनता को यह पता है.

किसानों का बकाया देने के लिए चीनी मिल मालिकों को भी पत्र लिखिए

पत्र लिख कर अपना दायित्व पूरा समझने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गन्ना किसानों का करोड़ों रुपये का बकाया देने के लिए चीनी मिल मालिकों को न पत्र लिखने की जरूरत समझते हैं और न हिदायत देने की. अगर ऐसा हुआ होता तो बकाये का विकराल पहाड़ नहीं खड़ा होता. गन्ना पेराई सत्र 2015-16 में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 2428 करोड़ रुपया बकाया है. यह पूरे देश में सबसे अधिक है, जबकि इस अवधि में बिहार में किसानों का चीनी मिलों पर 143 करोड़, पंजाब में 28 करोड़, उत्तराखंड में 198 करोड़, आंध्र प्रदेश में 181 करोड़, तेलंगाना में 99 करोड़, गुजरात में 255 करोड़, महाराष्ट्र में 883 करोड़, कर्नाटक में 1325 करोड़, तमिलनाडु में 610 करोड़, पुडुचेरी में 11 करोड़, छत्तीसगढ़ में 15 करोड़, ओड़ीशा में 32 करोड़, मध्य प्रदेश में 16 करोड़ और गोवा में मात्र एक करोड़ रुपये बकाया है. प्रदेश के गन्ना किसानों का बकाया देने के सिलसिले में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार झूठ बोल रही है. असलियत का आधिकारिक आंकड़ा आपके सामने है. उत्तर प्रदेश में चीनी मिले चलाने वाले ऐसे कई बड़े औद्योगिक घराने हैं जो गन्ना किसानों का हजारों करोड़ हड़पे हुए हैं. चीनी मिल मालिकों पर तकरीबन तीन हजार करोड़ रुपये बकाया है, लेकिन इसकी उगाही के बजाय प्रदेश सरकार तिकड़में रचती रहती है और उल्टे चीनी मिल मालिकों को ही राहत पैकेज देती रहती है. जबकि इन चीनी मिलों पर करोड़ों रुपया बकाया है. शिवाजी राय कहते हैं कि यह सरकार और चीनी मिल मालिकों की स्पष्ट मिलीभगत है.

feedback@chauthiduniya.com

इतिहास से छंटती धुंध

अनंत विजय

साहित्य अकादमी पुरस्कारों को लेकर साहित्य जगत में कई तरह की किंवदंतियां और मिथक मौजूद हैं. कब किसको मिला और कब किसको नहीं मिला, इसको लेकर भी कई तरह की बातें और प्रसंग साहित्य जगत में गूंजते रहते हैं, बहुधा साहित्यिक बैठकों में तो कई बार पुस्तकों में आए प्रसंगों के उल्लेख के तौर पर. 1962 में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसी लेखक को नहीं दिया गया था. आमतौर पर लोगों के बीच धारणा ये रही है कि 1962 में चीन के साथ युद्ध की वजह से पुरस्कार नहीं दिया गया, लेकिन जब 1911 में हिंदी के प्राध्यापक लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब 'व्योमकेश दरवेश' प्रकाशित हुई तो उसमें एक अलग ही प्रसंग नजर आया. 1962 के साहित्य अकादमी पुरस्कार को लेकर इस तरह की बात की गई है, जिससे लगता है कि रामधारी सिंह दिनकर के दबाव की वजह से उस वर्ष किसी को पुरस्कार नहीं दिया गया. त्रिपाठी जी दिनकर पर तंज भी कसते हैं-यशपाल के विषय में विवाद हुआ. कहते हैं कि दिनकर ने आपत्ति दर्ज की कि 'झूठा सच' के लेखक ने किताब में जवाहरलाल नेहरू के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है. नेहरू भारत के प्रधानमंत्री होने के साथ-साथ अकादमी के अध्यक्ष भी थे. नेहरू तक बात पहुंची हो या न पहुंची हो, द्विवेदी जी पर दिनकर की धमकी का असर पड़ा होगा. भारत के सर्वाधिक लोकतांत्रिक नेता की अध्यक्षता और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के संयोजकत्व में यह हुआ. अगर यह सच है तो अकादमी के अध्यक्ष और हिंदी के संयोजक दोनों पर धब्बा है यह घटना और मेरे नगपति मेरे विशाल के लेखक को क्या कहा जाए जो अपने समय का सूर्य होने की घोषणा करता है. (पृष्ठ 214). साहित्य अकादमी से डीएसराव की किताब-फाइव डिकेड्स, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ साहित्य अकादमी का अनुवाद छपा है. 'पांच दशक' के नाम से प्रकाशित उस किताब का अनुवाद भारत भारद्वाज ने किया है. इस किताब में ये प्रसंग है. यहां यह साफ है कि नेहरू जी को ये बात पता थी. लिहाजा त्रिपाठी जी की ये आशंका निर्मूल साबित होती है कि नेहरू तक ये बात पहुंची या नहीं. प्रसंग ये है-साहित्य अकादमी की एक्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक में साहित्य अकादमी के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने जानना चाहा कि उस वर्ष यशपाल के 'झूठा सच' को अकादमी पुरस्कार क्यों नहीं मिला. हिंदी के संयोजक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि इस उपन्यास में नेहरू की आलोचना है. इस पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए नेहरू ने कहा कि पुरस्कार के लिए किताब के न चुने जाने का कारण ये नहीं हो सकता है. इस पर द्विवेदी जी ने स्पष्ट किया कि सिर्फ ये कारण नहीं है बल्कि कई अन्य बेहतर किताबें पुरस्कार के लिए थीं. लेकिन किसी को पुरस्कार दिया नहीं जा सका. साहित्य अकादमी के पांच दशक के इतिहास से यह बात साफ हो जाती है कि यशपाल को पुरस्कार नहीं देने के पीछे रामधारी सिंह दिनकर नहीं थे.

उस दौर में दिनकर के विरोधियों ने यह बात सुनियोजित तरीके से फैलाई गई कि इसके पीछे दिनकर का दबाव था. विश्वनाथ त्रिपाठी ने अपनी किताब में इस प्रसंग को उद्धृत करते हुए ये टिप्पणी भी की-मेरे नगपति मेरे विशाल के लेखक को क्या कहा जाए जो अपने समय का सूर्य होने की घोषणा करता है. इससे साफ है कि अपनी किताब में विश्वनाथ त्रिपाठी ने अपने गुरू आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को बेदाग दिखाने के लिए दिनकर पर तोहमत लगाया. दरअसल दिनकर सचमुच

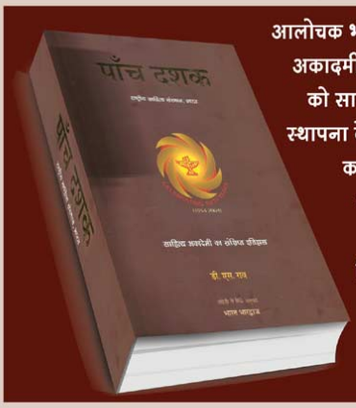

आलोचक भारत भारद्वाज द्वारा अनुदित यह किताब अकादमी के पचास सालों के गौरवशाली इतिहास को सामने लाती है. इसमें साहित्य अकादमी की स्थापना के पीछे की सोच से लेकर इसकी स्वायत्ता का आधार भी मौजूद है. शुरुआती दौर की बहसें भी इस किताब में हैं. इसके अलावा साहित्य अकादमी का संविधान भी इस किताब में है, जिसको पढ़कर हिंदी के उन लेखकों का ज्ञानचक्षु खुल सकता है जो अकादमी के क्रियाकलापों के बारे में मनगढ़ंत टिप्पणी करते रहते हैं.

अपने समय का सूर्य थे और बहुधा उस सूर्य पर ग्रहण लगाने की कोशिश की जाती रही, लेकिन सूर्य तो सूर्य होता है. साहित्य अकादमी के पांच दशक के इतिहास से इस तरह के कई धुंध छंटते नजर आते हैं. इस किताब से जवाहरलाल नेहरू की साहित्यिक रुचियों और उनके लोकतांत्रिक होने का पता चलता है. साहित्य अकादमी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने टिप्पणी की थी-साहित्य अकादमी के अध्यक्ष होने के नाते मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूं कि मैं नहीं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री भी मेरे काम में हस्तक्षेप करें. दरअसल जवाहरलाल नेहरू ने साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के अपने दस साल के कार्यकाल में उस भूमिका का निर्वाह किया जो किसी भी संस्था को बनाने के लिए जरूरी होता है. जवाहरलाल नेहरू अकादमी के कई दिलचस्प प्रसंग इस किताब में हैं. साहित्य अकादमी और हिंदी साहित्य के इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए यह एक जरूरी किताब है.

पिछले दिनों साहित्य अकादमी पुरस्कार वापसी को लेकर बहुत चर्चा हुई थी, तब पुरस्कार वापस करने वालों और उनके समर्थकों ने इस तरह का माहौल बनाया कि साहित्य अकादमी के इतिहास में अपनी तरह की यह पहली घटना है. साहित्य अकादमी का इतिहास-'पांच दशक' पलटने के बाद यह भी गलत साबित हो रही है. 1981 में तेलुगू लेखक वीआर नार्ला के नाटक 'सीता जोस्यम जिअर' पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, लेकिन जब अकादमी की पत्रिका इंडियन लिटरेचर में उसकी प्रतिकूल समीक्षा छपी तो उन्होंने पुरस्कार वापस कर दिया. इसी तरह से देशबंधु डोगरा 'नूतन' को उनके डोगरी उपन्यास 'कैदी' के लिए 1982 में चुना गया था. वो पुरस्कार वितरण समारोह में पहुंचे और वहां उन्होंने ये कहते हुए पुरस्कार लौटा दिया कि साहित्य अकादमी ने उनको पुरस्कार देने में बहुत देर कर दी, उनको तो बहुत पहले पुरस्कार मिल जाना चाहिए था. इसी तरह से 1983 में गुजराती लेखक सुरेश जोशी को उनकी किताब 'चिंतयामि मनसा' के लिए अकादमी पुरस्कार दिया गया, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए पुरस्कार लौटा दिया कि उनकी किताब में छिटपुट लेख हैं जो पुरस्कार के लायक नहीं हैं. उन्होंने उस वक्त एक टिप्पणी भी की थी-अकादमी चुके हुए लेखकों को पुरस्कृत करती है. इस आरोप पर उस वक्त के अध्यक्ष गोकाक ने टिप्पणी की थी-यह पता लगाना दिलचस्प होगा कि लेखक अपनी रचनात्मक शक्तियों के शिखर पर कब होता है. तब वह बिना चुकी हुई शक्ति होता है? यह कहना मुश्किल होगा. आयु वर्ग को ध्यान में रखते हुए, हम नहीं कह सकते कि मुनष्य तीसवें वर्ष में, चालीसवें में, पचासवें में, साठवें में अपने लेखन के प्रखर रूप में होता है. हो सकता है कि कुछ अद्भुत लड़के चट्टान की तरह हों या थोड़ा उम्रदराज शैली या कीट्स की तरह हों. वर्ड्सवर्थ की प्रतिभा का उम्र बढ़ने के साथ ह्रास हुआ, लेकिन रवीन्द्रनाथ जैसे लेखक भी थे जिनकी रचनात्मक उर्जा सत्तर पार भी अक्षुण्ण थीं. बाद में लेखकों को पुरस्कृत करने में इस तरह के तर्कों का सहारा मिला. बाद में भी कई बार साहित्य अकादमी पुरस्कार को लेकर विवाद उठा. यह बात भी समय समय पर उठी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार बना दिया जाना चाहिए. साहित्य अकादमी पुरस्कार पर कृष्णा सोबती की टिप्पणी भी गौर करने लायक थी जब उन्होंने इसको आईसीसी में तय होने की बात की थी.

आलोचक भारत भारद्वाज द्वारा अनुदित यह किताब अकादमी के पचास सालों के गौरवशाली इतिहास को सामने लाती है. इसमें साहित्य अकादमी की स्थापना के पीछे की सोच से लेकर इसकी स्वायत्ता का आधार भी मौजूद है. शुरुआती दौर की बहसें भी इस किताब में हैं. इसके अलावा साहित्य अकादमी का संविधान भी इस किताब में है, जिसको पढ़कर हिंदी के उन लेखकों का ज्ञानचक्षु खुल सकता है जो अकादमी के क्रियाकलापों के बारे में मनगढ़ंत टिप्पणी करते रहते हैं. साहित्य अकादमी का पचास साल का इतिहास हिंदी में प्रकाशित हो गया है. अब आवश्यकता इस बात की है कि उसके बाद के करीब बारह साल का इतिहास भी प्रकाशित हो. साहित्य अकादमी को कुछ इस तरह का इंतजाम करना चाहिए कि हर दस साल बाद इसका इतिहास एक दस्तावेज के रूप में सामने आए. इससे साहित्य के नए पाठकों को अकादमी के बारे में जानने समझने में सहूलियत होगी. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.vbn@gmail.com

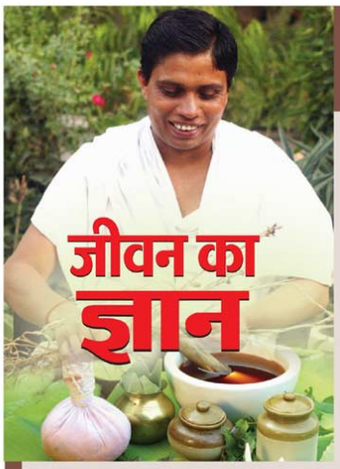

बड़ी इलायची

परिचय

बड़ी इलायची के फल एवं सुगंधित बीजों से भला कौन अपरिचित हो सकता है. भारतीय रसोई में यह इस तरह से रची बसी है कि इसका प्रयोग मसालों से लेकर मिष्ठानों तक में किया जाता है. इसकी एक प्रजाति, मोरंग इलायची भी होती है. यह पूर्वी हिमालय प्रदेश में विशेषत: नेपाल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम आदि में पायी जाती है. छोटी इलायची का भी प्रयोग औषधियों में होता है. बड़ी इलायची की मुख्य प्रजाति के अतिरिक्त एक और प्रजाति पाई जाती है जिसका प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है.

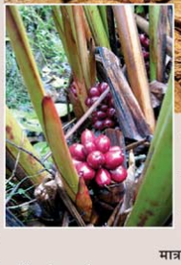

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

- **शिरो रोग-** बड़ी इलायची को पीसकर मस्तिष्क पर लेप करने से एवं बीजों को पीसकर सूंघने से सिर दर्द का शमन होता है.
- **मुख रोग-**बड़ी इलायची को पीसकर शहद में मिलाकर मुंह में छालों पर लगाने से मुखपाक में लाभ होता है.
- **दांत दर्द-**बड़ी इलायची और लौंग तेल को बराबर-बराबर मात्रा में लेकर दांतों पर मलने से दंत दर्द का शमन होता है.
- **लार का बहना-** यदि अधिक थूक आता हो तो बड़ी इलायची और सुपारी को बराबर-बराबर पीसकर, 1-2 ग्राम मात्रा में लेकर चूसते रहने से यह कष्ट दूर हो जाता है.
- **दमा-** 5-10 बूंद बड़ी इलायची तेल में मिश्री मिलाकर नियमित सेवन करने से दमा में लाभ होता है.
- **हिचकी-** एक कप पानी में दो बड़ी इलायची पीसकर उबालें. आधा शेष रहने पर छानकर, ठंडा कर पिलाने से हिचकी में तुरंत लाभ होता है.
- **पाचन-शक्ति-** 2 ग्राम सौंफ के साथ बड़ी इलायची के 8-10 बीजों का सेवन करने से पाचन-शक्ति बढ़ती है.
- 10 नग छिलकों सहित बड़ी इलायची को लेकर कुट कर 250 मिली दूध और 250 मिली जल के साथ पकाएं, दूध मात्र शेष रहने पर छानकर उसमें थोड़ी मिश्री मिलाकर दिन में चार बार पिलाएं इससे पेशाब की जलन व रुकावट दूर होती है.
- **पथरी-** बड़ी इलायची के बीज चूर्ण में खरबूजों के बीज और मिश्री मिलाकर 2-3 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से पथरी टूट-टूट कर निकल जाती है.
- **वात-वेदना-** 1-2 बड़ी इलायची के चूर्ण को दिन में तीन बार नियमित सेवन करने से वात वेदना का शमन होता है.
- **ज्वर-** सभी प्रकार के ज्वर में बड़ी इलायची के बीज 2 भाग तथा बेल छाल के 1 भाग को मिलाकर चूर्ण बनाकर एक चम्मच चूर्ण को दूध और पानी में मिलाकर पकाएं और केवल दूध शेष रहने पर 20 मिली की मात्रा में सुबह, दोपहर तथा सायं सेवन करने से ज्वर में लाभ होता है. ■

प्रयोज्यांग : *बीज, फल तथा बीज-तेल.*

मात्रा- *1-3 ग्राम अथवा चिकित्सक के परामर्शानुसार.*

आचार्य बालकृष्ण

साईं वंदना

जरूरतमंद व्यक्ति की पहचान कैसे सम्भव है?

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

सत्कर्म-विचार पूरा करें

कभी-कभी ऐसा होता है कि हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में किसी गरीब द्वारा भीख मांगने पर मन में यह इच्छा होती है कि उसे कुछ दे दें किंतु किन्हीं कारणों से उस गरीब को उस वक्त यदि हम कुछ दे न पाएं तो हम क्या करें? इस संबंध में आप हमें कुछ बताएं.

सत् कर्म का संकल्प जिस समय भी मन में उत्पन्न हो, उसको उसी समय करने का प्रयास करना चाहिए. अगर किन्हीं कारणों से वह उस समय नहीं हो पा रहा है तो बाद में अनुकूल परिस्थितियों में उसको अवश्य कर लेना चाहिए. जैसे उदाहरण के तौर पर गाड़ी के चलते समय एक गरीब बच्चे ने शीशे को खटखटाया. मन में भाव आया कि उसे दो रुपये या पांच रुपये दे दें. पर पास में सौ रुपये का नोट था, जो हम देना नहीं चाहते थे. या तो हम पहले से ही पैसे निकाल कर रखते. पर हरी बत्ती हुई और गाड़ी चल दी. इस प्रकार की बात को मन में याद रखना चाहिए और जब भी मंदिर जाएं उसे दान-पात्र में डाल दें.

अशुद्ध भाव व मंदिर

कभी मंदिर का वातावरण अच्छा नहीं लगता हो या हमारा मंदिर जाने का मन नहीं करता हो तो हम क्या करें?

यदि ऐसा हो तो मंदिर मत जाओ. मंदिर तो हम इसलिए जाते हैं कि हममें मंदिर की अच्छी भावना उत्पन्न हो और वहां का वातावरण हमारी भावना शुद्ध करे. हां, यह हो सकता है कि हमारी ही भावना उतनी शुद्ध न हो - जितनी कि हम समझते हैं.

ऐसी परिस्थिति में उचित है कि दूसरों की कुभावना से खुद को प्रभावित न होने दें और अपनी प्रतिक्रियात्मक भावना से मंदिर के वातावरण को भी प्रभावित न होने दें. उचित यही होगा कि जब ऐसा हो, तो उतने समय में अपने घर में 'श्री साईं सच्चरित्र' पढ़ें या ईष्ट-गुरु का ध्यान करें. उससे अधिक लाभ होगा.

यदि मंदिर न जा पाएं...

बहुत से लोग परिस्थितियों में बंधे रहने के कारण मंदिर आने में असमर्थ रहते हैं. ऐसी स्थिति में भक्त क्या करें?

बाबा की पूजा करने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि हम कितनी बार मंदिर गए या उन्हें पुष्प, नारियल आदि चढ़ाए. आवश्यकता है, भाव-रूप में बाबा को हृदय में स्थापित करने की-जो कि घर में भी किया जा सकता है.

मंदिर न जा पाए तो क्या
याद तुम्हारी काफ़ी है,
दर्शन न मिला तो क्या?
प्यार तुम्हारा साथ में है.

प्रकृति ने हमारे लिए एक दिनचर्या निश्चित की है, जिसके चारों ओर अनेक गतिविधियां सक्रिय हैं, जैसे हमारा

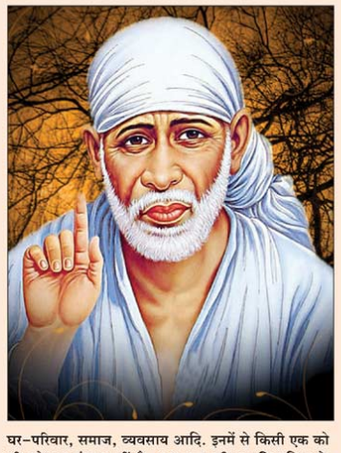

घर-परिवार, समाज, व्यवसाय आदि. इनमें से किसी एक को भी छोड़ना संभव नहीं है. सब कुछ जीवन की गणित के अनुसार निश्चित है. कर्मबंधन के अनुसार जीव बंधा हुआ है. कुछ भी छोड़ना न तो उसके लिए संभव है, न ही उचित है क्योंकि यदि वह एक स्थान पर बढ़ाने के लिए दूसरे स्थान से घटाता है तो आगे चलकर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उसे चुकाना पड़ता है. प्रारब्ध कर्मफल को भोग करके ही समाप्त किया जाता है.

सुपात्र या कुपात्र

यदि हम किसी की मदद करना चाहें, तो वास्तविक रूप से जरूरतमंद व्यक्ति की पहचान कैसे सम्भव है? इस संदर्भ में अक्सर संशय बना रहता है.

प्रत्येक व्यक्ति जरूरतमंद है. सभी बाबा से कुछ न कुछ पाने की कामना से प्रार्थना करते हैं. बाबा ने कहा था कि पूर्वजन्मों के सम्बन्धों से कारण ही कोई किसी के पास सहायता प्राप्त करने की कामना से आता है. मैं इस संदर्भ में यही कहना चाहता हूं कि अपनी निर्णयात्मक शक्ति का प्रयोग करें. यदि आपका संदेह दूर हो जाता है और आप यह मान लेते हैं कि यह व्यक्ति-विशेष वस्तुत: जरूरतमंद है, तो उसकी सहायता कर दीजिए. मन में यदि तनिक भी संशय होता है, तो निर्णय बाबा पर डाल दीजिए. अगर आपके मन में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दस रुपये देने की इच्छा है और आप संदेहग्रस्त हैं कि वह व्यक्ति उपयुक्त पात्र है या नहीं, तो उसे बाबा की दान-पेटी में डाल दीजिए और बाबा को निर्णय करने दें. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों! आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

लोकेश राहुल में टेस्ट क्रिकेटर बनने का दम

लोकेश राहुल के करियर पर नजर दौड़ायी जाये तो इतना साफ है कि आने वाले समय में वह टीम इंडिया की बल्लेबाजी की विरासत को संभाल सकते हैं. लोकेश को घरेलू क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी की धाक जमाने के बाद राष्ट्रीय टीम में खेलने का मौका मिला. दरअसल लोकेश राहुल के पिता का सपना है कि उनका बेटा सुनील गवास्कर जैसा बड़ा बल्लेबाज बने. पिता के सपनों को उड़ान देने के लिए राहुल ने बेहद कम उम्र में बल्ला थाम लिया था. राहुल के क्रिकेट की पहली पाठशाला के गुरु सेमुअल जयराज थे. सेमुअल जयराज ने लोकेश की प्रतिभा को पहचाना और तराशना शुरू कर दिया था. उनकी क्रिकेट में इतनी लगन थी वह शुरुआती दौर में मैंगलोर टीम का हिस्सा बन गये.

सैयद मोहम्मद अब्बास

भारतीय क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर है. टीम इंडिया की युवा टीम वेस्टइंडीज जैसी कमजोर टीम के सामने रनों का पहाड़ खड़ा कर रही है. पहले टेस्ट में विराट व अश्विन का जलवा देखने को मिला तो दूसरे टेस्ट में लोकेश राहुल का बल्ला भी खूब चला. पहली पारी में शतक लगाकर राहुल ने टीम इंडिया में अपनी जगह को और मजबूती दी है. हाल के दिनों में उनकी फॉर्म गजब की रही है. टेस्ट क्रिकेट में राहुल की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई थी और वह कंगारुओं के खिलाफ सुपर फ्लॉप रहे थे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मुकाबले में राहुल ने पहली पारी में तीन व दूसरी पारी में एक रन बनाये थे. उनके इस प्रदर्शन को लेकर कई सवाल खड़े किये गये थे. इतना ही नहीं राहुल के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में शॉट स्लेक्शन को लेकर भी ऊंगली उठी थी, लेकिन इसके बाद लोकेश राहुल ने टेस्ट क्रिकेट में शानदार वापसी करते हुए अब तक तीन शतक जड़ चुके हैं. उनके प्रदर्शन में लगातार सुधार हो रहा है. यह भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद अच्छी खबर है. वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में उनकी जगह बनती नहीं दिख रही थी, लेकिन मुरली विजय के चोटिल होने के बाद उनको टीम में जगह दी गई. उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए शानदार शतक लगाकर अपने चयन को सही बताया है. राहुल ने जब छक्का मारकर शतक पूरा किया तो उन्होंने वीरू की याद दिला दी. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी अक्सर छक्का लगाकर शतक पूरा करते थे. लोकेश राहुल ने करियर में तीन शतक जड़े हैं. खास बात यह है कि तीनों शतक विदेशी धरती पर लगाया है. किंगस्टन के विकेट में थोड़ी उछाल थी, ऐसे में राहुल के बल्ले से निकला शतक काफी अहम माना जायेगा. लोकेश राहुल को बतौर टेस्ट बल्लेबाज के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन हाल के दिनों में वह क्रिकेट के हर फॉर्मेट में अपने बल्ले का दम-खम दिखा रहे हैं. हाल में जिम्बाब्वे दौरे की टीम में उनको शामिल किया गया था. वहां उन्होंने वन डे और टी-20 में अच्छा प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन के बल पर उन्हें वेस्टइंडीज के दौरे पर जाने का मौका मिला. कहा जाता है, उनकी बल्लेबाजी में राहुल द्रविड़ का अक्स दिखता है लेकिन अभी इसके बारे में कहना जल्दबाजी होगी.

लोकेश राहुल के करियर पर नजर दौड़ायी जाये तो इतना साफ है कि आने वाले समय में वह टीम इंडिया की बल्लेबाजी की विरासत को संभाल सकते हैं. लोकेश को घरेलू क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी की धाक जमाने के बाद राष्ट्रीय टीम में खेलने का मौका मिला. दरअसल लोकेश राहुल के पिता का सपना है कि उनका बेटा सुनील गवास्कर जैसा बड़ा बल्लेबाज बने. पिता के सपनों को उड़ान देने के लिए राहुल ने बेहद कम उम्र में बल्ला थाम लिया था. राहुल के क्रिकेट की पहली पाठशाला के गुरु सेमुअल जयराज थे. सेमुअल जयराज ने लोकेश की प्रतिभा को पहचाना और तराशना शुरू कर दिया था. उनकी क्रिकेट में इतनी लगन थी वह शुरुआती दौर में मैंगलोर टीम का हिस्सा बन गये. राहुल द्रविड़ भी उनकी बल्लेबाजी से काफी प्रभावित हुए. लोकेश राहुल ने राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर अंडर-19 टीम का टिकट हासिल कर लिया. रणजी के रण में भी उनकी शुरुआत धांसू रही. लोकेश ने 2010-11 के सीजन में 1033 रन बनाकर भारतीय क्रिकेट में दस्तक देनी शुरू कर दी. 2014 में पहली बार टेस्ट खेलने का मौका मिला, लेकिन वह रन बनाने में पूरी तरह से नाकाम रहे. इसके बाद लोकेश ने हार नहीं मानी और दूसरे टेस्ट में कंगारुओं को अपने बल्ले से करारा जवाब दिया. उन्होंने सिडनी की तेज पिच पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए शतक लगाया. यह वही दौर था जब टीम इंडिया बदलाव के दौर से गुजर रही थी. इतना ही नहीं इसके बाद लोकेश राहुल की मांग आईपीएल में बढ़ गई थी. हालांकि 2013 से आईपीएल मैच में दम दिखाने वाले लोकेश राहुल ने 2016 के सीजन में 44.11 की औसत से 397 रन बनाकर टी-20 में अपना जलवा दिखाया. लोकेश राहुल जरूरत पड़ने पर विकेटकीपर का रोल अदा कर सकते हैं. इस समय भारतीय क्रिकेट में युवा क्रिकेटरों को भी खूब मौके मिल रहे हैं. सचिन, सौरभ व राहुल द्रविड़ के जाने के बाद से टीम इंडिया की बल्लेबाजी का क्रम हाल के दिनों में कुछ मौकों पर नहीं चल सका है, लेकिन विराट व रहाणे के आने के बाद टीम की बल्लेबाजी का क्रम मजबूत हुआ है. ऐसे में लोकेश राहुल जैसे बल्लेबाजों को टीम में अपनी जगह पक्की करने का सुनहरा मौका है. वेस्टइंडीज के खिलाफ अभी टीम इंडिया को कुछ और टेस्ट खेलने हैं. अब यह देखना रोचक होगा कि आने वाले समय में बल्लेबाज लोकेश राहुल किस तरह का प्रदर्शन करते हैं.■

टेस्ट क्रिकेट में राहुल की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई थी और वह कंगारुओं के खिलाफ सुपर फ्लॉप रहे थे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मुकाबले में राहुल ने पहली पारी में तीन व दूसरी पारी में एक रन बनाये थे. उनके इस प्रदर्शन को लेकर कई सवाल खड़े किये गये थे. इतना ही नहीं राहुल के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में शॉट स्लेक्शन को लेकर भी ऊंगली उठी थी, लेकिन इसके बाद लोकेश राहुल ने टेस्ट क्रिकेट में शानदार वापसी करते हुए अब तक तीन शतक जड़ चुके हैं.

नाकामियों के बीच पदक की आस

रियो ओलम्पिक में भारतीय खिलाड़ियों की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. कई बड़े नाम विश्व के सबसे बड़े खेल मेले में गुम होते हुए दिखे. हालांकि कुछ खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर भारतीय झंडा बुलंद किया है. स्टार खिलाड़ियों में पेस से लेकर निशानेबाज अभिनव ने भारतीय खेल प्रेमियों को निराश किया है. पेस करियर के अंतिम दौर में है, ऐसे में रियो ओलम्पिक में पदक जीतने का सपना अब खत्म हो गया है, क्योंकि पेस-बोपन्ना की जोड़ी पहले दौर में हारकर ओलम्पिक से बाहर हो गई. जबकि सानिया-प्रार्थना की जोड़ी भी कमाल नहीं कर सकी. अभिनव बिंद्रा के फाइनल में प्रवेश करने के बाद उनका निशाना भी चूक गया और पदक की आस भी दम तोड़ गई. इतना ही नहीं गगन नारंग का निशाना तो फाइनल तक भी नहीं पहुंच सका. हालांकि गगन को अभी अन्य इवेंट में भाग लेना है. इससे पूर्व पदक का दावा करने वाले जीतू राय का निशाना भी ठिकाने पर नहीं लगा. हॉकी में पुरुष व महिला टीमों का प्रदर्शन अभी मिला-जुला रहा है. पुरुष हॉकी में भारतीय टीम ने शुरुआती मैच में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन जर्मनी के खिलाफ दूसरे मैच में अंतिम वक्त में पराजित होना पड़ा. दरअसल भारतीय हॉकी की पुरानी कमजोरी एक बार फिर सामने आई. अंतिम लम्हों पर कोताही करना एक बार फिर टीम पर भारी पड़ा. महिला हॉकी की कहानी भी यही है. इसके आलावा टेबल टेनिस में भी भारत को बुरी खबर सुनने को मिली. अनुभवी अचंत शरत कमल रियो में चमक नहीं सके. मौमा दास, मणिका बत्रा और सौम्यजीत घोष का प्रदर्शन भी बेहद खराब रहा. मीराबाई भारोत्तोलन में भारत की उम्मीदों का बोझ नहीं उठा सकीं.

दूसरी ओर दीपा करमाकर ने इतिहास रचते हुए जिमनास्टिक प्रतियोगिता के फाइनल में अपना स्थान पक्का करके भारत का मान रियो ओलम्पिक में बढ़ा दिया है. हाल के दिनों में दीपा ने कई मौकों पर भारत का डंका बजाया है. दीपा बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं. यह भी एक कटु सत्य है कि ओलम्पिक में भारत की बेटी दीपा जब पहली बार जिमनास्टिक की दुनिया में कदम रखा था तब उसके पैरों में जूते तक नहीं थे. कहते हैं कि अगर आपमें कुछ करने का हौसला हो तो रास्ते खुद व खुद खुलने लगते हैं. दीपा के साथ ऐसा ही है. दरअसल दीपा हिन्दुस्तान की तरफ से ओलम्पिक में जाने वाली पहली महिला जिमनास्ट हैं. इससे पूर्व भारत की तरफ से 11 पुरुष जिमनास्ट खिलाड़ी ओलम्पिक में भाग ले चुके हैं, इसके साथ ही 52 साल बाद दीपा के रूप में कोई भारतीय खिलाड़ी जिमनास्ट में दम-खम दिखा रहा है. कुल मिलाकर कई और खेल हैं जिनमें भारत को पदक मिल सकते हैं. उनमें अभी बैडमिंटन व कुश्ती सबसे अहम मानी जा रही है. भारत के प्रदर्शन को अभी आंकना जल्दबाजी होगा. कुछ बड़े खिलाड़ियों के हार जाने से भारत की दावेदारी थोड़ी कमजोर पड़ती दिख रही है, लेकिन ओलम्पिक का शुरुआती चरण है.

दूसरी ओर विदेशी खिलाड़ी लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं. रियो ओलम्पिक के शुरुआती रूझानों पर गौर किया जाये तो अमेरिका और चीन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. तैराकी के बेताज बादशाह माइकल फेल्प्स का जलवा खूब देखने को मिल रहा है. उन्होंने संन्यास के बाद शानदार वापसी करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर एक और नया इतिहास बनाया है. दरअसल तैराकी की दुनिया में माइकल फेल्प्स की बादशाहत चलती है. इसके साथ 31 साल के फेल्प्स 19 स्वर्ण के साथ कुल 23 पदक हासिल कर चुके हैं. ■

शानदार उद्घाटन

रियो ओलम्पिक शुरू हो गया. इसके साथ ही पदकों की जंग भी शुरू हो गई. इससे पूर्व रियो ओलम्पिक की तैयारियों को लेकर तमाम बाते भले ही होती रही हों, लेकिन उद्घाटन समारोह में ब्राज़ील के रियो शहर का नजारा पूरा बदला हुआ था. ओलम्पिक जैसी बड़ी प्रतियोगिता में अक्सर आयोजकों पर सफल मेजबानी का दबाव बना रहता है. ऐसे में ब्राजील भी इससे अछूता नहीं रहा. ब्राजील में इस समय हालात ठीक नहीं चल रहे हैं. आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है यह देश उम्मीदों पर खरा उतरा है. खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ की तैयारी ब्राजील ने कई बरस से की थी. उद्घाटन समारोह बेहद शानदार रहा. समारोह को सफल बनाने के लिए आयोजकों ने कोई कसर नहीं छोड़ी. ब्राज़ील के कलाकारों ने म्यूज़िक, थ्रीडी इमेजिन और लेजर तकनीक का अद्भुत नमूना पेश किया. इतना ही नहीं छह हज़ार से ज़्यादा वॉलिंटियर्स ने इस उद्घाटन समारोह में भाग लिया. रियो ओलम्पिक के उद्घाटन समारोह की खास बात यह रही कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर एक बेहद खास संदेश दिया है. दरअसल विश्व के लिए खतरा बन रहे ग्लोबल वार्मिंग के तहत तापमान में वृद्धि को लेकर छोटा संदेश, लेकिन काबिले तारीफ था. इसके आलावा रियो के मशहूर सांबाश् नृत्य ने वहां मौजूद खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया.

feedback@chauthiduniya.com

एम फॉर यू का टॉप-50 इंडियन आईकॉन अवार्ड समारोह सम्पन्न

एम फॉर यू द्वारा आयोजित टॉप-50 इंडियन आईकॉन अवार्ड समारोह भव्य रूप से सम्पन्न हो गया. अवार्ड समारोह में देश-विदेश से चुनी गईं 50 महान विभूतियों ने अपनी उपस्थिति से चार चांद लगा दिए.

बीते 29 जुलाई को मुंबई में एम फॉर यू द्वारा आयोजित टॉप-50 इंडियन आईकॉन अवार्ड समारोह भव्य रूप से सम्पन्न हो गया. अवार्ड समारोह में देश-विदेश से चुनी गईं 50 महान विभूतियों ने अपनी उपस्थिति से चार चांद लगा दिए. इस मौके पर उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री श्री ओम प्रकाश मुख्य अतिथि और एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन श्री मनिन्दर जीत सिंह बिट्टा अतिविशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित थे. समारोह में बॉलीवुड अभिनेत्री मंजरी फड़णवीस, ज़ोया अफरोज़, पाखी हेगड़े सहित एफटीआई के अध्यक्ष गजेंद्र चौहान जैसी बॉलीवुड की शख्सियतों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, तो वहीं सिंगापुर, थाईलैंड और दुबई से आए हुए अतिथियों ने कार्यक्रम की भव्यता को ऊंचाई पर पहुंचा दिया. वरिष्ठ पत्रकार श्री संतोष भारतीय ने कार्यक्रम के आयोजक दुष्यन्त सिंह की सफल आयोजन के लिए दिल खोलकर प्रशंसा की. कार्यक्रम को अपने तरह का एक अनोखा प्रयास बताते हुए इसे समाज की आवश्यकता बताया. कार्यक्रम का संचालन रितु सिंह ने किया. इस कार्यक्रम के सह आयोजक वेद प्रकाश और करमजीत सिंह थे. अनुराग बत्रा मीडिया प्रभारी थे.■

बॉडी हो तो जॉन जैसी

जॉन अब्राहम की फिटनेस का राज़

जॉन रोजाना 2 से 3 घंटे तक वर्कआउट करते हैं. इसके लिए वह हर हाल में समय निकाल ही लेते हैं, अगर शूटिंग से उन्हें समय नहीं मिल पाता तो वह घर पर जाकर वर्कआउट करते हैं, चाहे रात के दो ही क्यों न बज जाएं.

धूम, दोस्ताना, शूटआउट वडाला, फोर्स, रॉकी हैंडसम और डिशूम जैसी कई फिल्मों में अपनी बेहतरीन बॉडी से जॉन ने न केवल युवा पीढ़ी को आकर्षित किया, बल्कि यह भी बता दिया कि फिट रहने के लिए वर्कआउट करना भी बेहद जरूरी है. जॉन अब्राहम आज बॉलीवुड में सबसे फिट बॉडी वाले अभिनेता माने जाते हैं. भले ही उनकी उम्र 39 वर्ष की हो, लेकिन आज की युवा पीढ़ी उनकी फैन है. कॉलेज के दिनों में जॉन बॉस्केटबॉल और फुटबॉल खेलने में माहिर थे. उनकी बॉडी इस तरह की है कि वह जब चाहें अपना वजन बढ़ा-घटा सकते हैं. लेकिन जॉन अपनी फिटनेस और बॉडी के लिए क्या करते हैं? आइये जानते हैं जॉन अब्राहम की फिटनेस का राज.

जॉन रोजाना 2 से 3 घंटे तक वर्कआउट करते हैं. इसके लिए वह हर हाल में समय निकाल ही लेते हैं, अगर शूटिंग से उन्हें समय नहीं मिल पाता है तो वह घर पर जाकर वर्कआउट करते हैं, चाहे रात के दो ही क्यों न बज जाएं. उनका मानना है कि अगर फिट बॉडी चाहिए तो तीन मुख्य चीज़ों का ख्याल रखना बहुत जरुरी है, एक अच्छा खाना, अच्छी नींद और सही रूटीन से ही आप फिट रह सकते हैं. जॉन हर रोज 30 मिनट तक कॉर्डियो करते हैं, जिसमें दौड़ना, जॉगिंग और किक बॉक्सिंग आदि शामिल है. वेट लिफ्टिंग उनके वर्कआउट का ख़ास हिस्सा है.

जॉन को बाहर जाकर वर्कआउट करना ज्यादा पसंद है, लेकिन समय के अभाव में ऐसा मौका कम ही मिल पाता है. जॉन दिन में 5-6 बार थोड़ा-थोड़ा खाते हैं. उनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फाइबर की मात्रा रहती है. उन्हें शाकाहारी भोजन पसंद है, लेकिन वह अंडे का सफेद भाग और प्रोटीन के लिए मछली खाते हैं. क्योंकि मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन खाना बहुत जरुरी है. लंच में चपाती, दाल, टोफु, फ्राइड वेजिटेबल लेते हैं. आगे जॉन बताते हैं कि वह सूप, प्रोटीन शेक और कॉर्न उनके डेली रूटीन में शामिल हैं. जॉन ने कहा कि स्ट्रेस बस्टर उनकी एक्सरसाइज और उनकी बाइक है, जिसके साथ होते ही उनका तनाव गायब हो जाता है. कभी लंबी राइड पर चला जाता हूं या फिर वर्क आउट कर लेता हूं. इनसे मुझे बेहद खुशी मिलती है.■

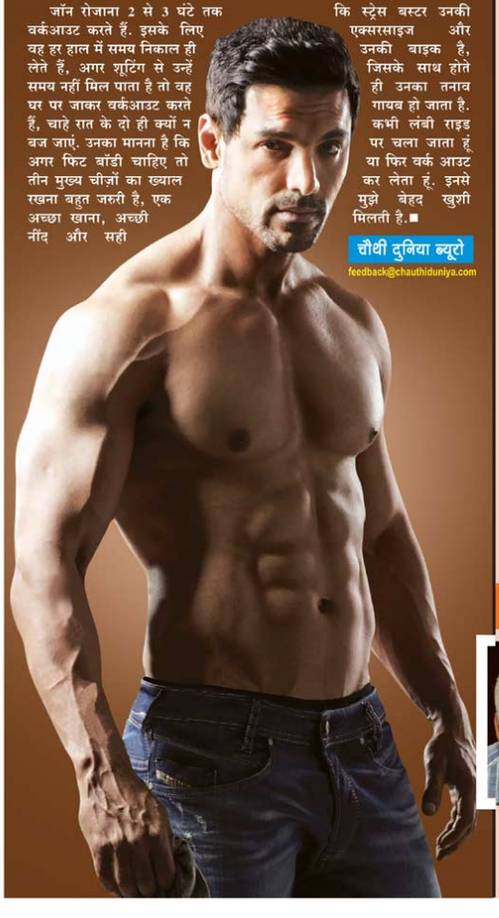

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सारागढ़ी की ऐतिहासिक लड़ाई पर होगी सन्स ऑफ सरदार

अजय देवगन एक के बाद एक धमाका करते जा रहे हैं. अभी तो फैंस उनकी फिल्म *शिवाय* में ही फंसे हुए हैं, जबकि दूसरी ओर अजय अपनी बाकी फिल्मों से जुड़ी जानकारी भी लगातार शेयर कर रहे हैं. ताज़ा बात करें तो अजय देवगन ने पिछले दिनों अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म *सन्स ऑफ सरदार* का पहला पोस्टर रिलीज़ किया.

अजय देवगन के लिए फिलहाल दो फिल्में काफी ख़ास हैं. पहली शिवाय, जो कि इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज़ हो रही है. दूसरी फिल्म है सन्स ऑफ सरदार, जो 2017 की दिवाली पर रिलीज़ होगी.

सन्स ऑफ सरदार सारागढ़ी की ऐतिहासिक लड़ाई पर बन रही है, जो 12 सितंबर 1897 में सिक्ख रेजिमेंट के चौथे बटालियन के 21 सिक्खों ने लड़ी थी. इस फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है. शिवाय की रिलीज़ के बाद अजय *सन्स ऑफ सरदार* की शूटिंग शुरू करेंगे.

फिलहाल सन्स ऑफ सरदार की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है. अजय देवगन इस फिल्म को अंतराष्ट्रीय स्तर पर ग्रैंड बनाना चाहते हैं. अजय का कहना है कि वे सन्स ऑफ सरदार को भारत की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल करना चाहते हैं. इस फिल्म को लेकर अजय देवगन काफी रिसर्च कर रहे हैं.■

दबंग 3 में होंगी सोनाक्षी सिन्हा

दबंग-3 के लिए कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं. लेकिन अरबाज़ ने अब इस ख़बर पर विराम लगा दिया है. उन्होंने साफ कर दिया कि एक बार फिर सलमान और सोनाक्षी की जोड़ी दबंग-3 में लोगों को दिखाई देगी.

प्रवीण कुमार
feedback@chauthiduniya.com

बॉलीवुड में एक्टर सलमान खान के साथ अपना डेब्यू करने वाली सोनाक्षी सिन्हा एक बार फिर उनके साथ नज़र आने वाली हैं. फिल्म दबंग और दबंग-2 में अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज़ करने वाली सोनाक्षी सिन्हा दबंग-3 में भी सलमान के अपोजिट नज़र आएंगी.

जी हां, फिल्म निर्माता अरबाज़ खान ने कहा है कि उनकी अगली फिल्म दंबग-3 में भी सलमान खान के अपोजिट सोनाक्षी सिन्हा ही रहेंगी. सब जानते हैं कि सलमान का दबंग अंदाज बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहा है. हालांकि फिल्म में सलमान के अपोजिट हीरोइन को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं.

ख़बरें यह भी थीं कि इस बार दबंग में लीडिंग लेडी सोनाक्षी सिन्हा नहीं होंगी, क्योंकि सलमान खान उनसे नाराज़ हैं. बताया जाता है कि अरबाज़ खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म *डॉली की डोली* के लिए पहले सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया था, पर किसी वजह से सोनाक्षी ने फिल्म को करने से इंकार कर दिया. जिसके बाद फिल्म में सोनम कपूर को फाइनल किया गया. सोनाक्षी ने किस वजह से फिल्म को न करने का फैसला किया यह तो वही बता सकती हैं, पर सोनाक्षी के इंकार करने के बाद अरबाज़ और सलमान उनसे काफी नाराज़ थे. ख़ैर कहते हैं न की समय आने पर सब ठीक हो जाता है, सोनाक्षी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और अरबाज़ ने अब इस ख़बर पर विराम लगा दिया है. उन्होंने साफ कर दिया है कि एक बार फिर सलमान और सोनाक्षी की जोड़ी दबंग-3 में लोगों को दिखाई देगी.■

ओम पुरी ने एकता का सबक कौओं से सीखा

उम्दा और गंभीर अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता ओम पुरी ने अपने जीवन में छोटी-छोटी चीजों से काफी कुछ सीखा है. वे कहते हैं कि उन्होंने कौओं से एकता का सबक सीखा है. ओम पुरी ने बताया कि बचपन में एक बार मुझे एक कौए का बच्चा पड़ा दिखा और यूं ही मैंने उस बच्चे को उठाने की कोशिश की. बच्चे को उठाता देख एक कौआ कांव-कांव करने लगा और अचानक कई कौओं ने मुझे घेर लिया, मैं बहुत घबरा गया. तभी एक छड़ी मुझे दिखाई दी और मैंने जोर-जोर से उसे अपने सिर पर घूमाना शुरू कर दिया. कौए के उस बच्चे को वहीं छोड़ कर मैं घर की तरफ भागा. तब मुझे अहसास हुआ कि वे कौए समझ रहे थे कि मैं उनके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कौए जैसे एक छोटे से जीव में भी कितनी एकता होती है कि उन्होंने मुझे वहां से भगा दिया और अपने बच्चे को बचा लिया. मैं तब से यह मानने लगा कि किसी को कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए.■